



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]

नई दिल्ली, शनिवार, मितम्बर 23, 1995/आश्विन 1, 1917

No. 38)

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 23, 1995/ASVINA 1, 1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या हो जाती हैं जिससे कि यह मतलब संक्षय के कथ में
रक्षा का बचे

**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation**

भाग II—खण्ड 3—खण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

भारत सरकार के राज्यालयों (रक्षा राज्यालय के छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य
के अंतर्गत प्रशासनों के छोड़कर) द्वारा विधि के मत्तरात बनाए और बारी किये गये साधारण सांस्थितिक
विधिय (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सौम्यालित हैं)

**General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general
Character) issued by the Ministries of the Government of India (other
than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities
(other than the Administration of Union Territories)**

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय
(कंपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 मितम्बर, 1995

मा. का. नि. 426.—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिकारिय, 1956 (1956 का 1) की धारा 208 की उपशाखा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह नियम देता है कि उन धारा के प्रयोगकों ने लिए, किसी भी दृश्य में अप्रत्यक्ष की दर प्रतिवर्पन वार्ग प्रतिशत में अधिक नहीं होती।

[नं. 28/1/94-सी. ए. 3]
धर्मपाल, अध्यक्ष मन्त्रिय

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY
AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 8th September, 1995

G.S.R. 426.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 208 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby directs that rate of interest shall in no case exceed twelve per cent per annum for the purposes of said section.

[No. 28/1/94-CL.III]

DHARAM PAL, Under Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 मितम्बर, 1995

मा. का. नि. 427.—राष्ट्रपति संविधान के अनुलेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीर केन्द्रीय रिजर्व पुलिम बल महाप्रक निदेशक (लेखा) भर्ती विधिय, 1971 को उन बातों के मिवाय अधिकारिय करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण ने पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय रिजर्व पुलिम बल में महायक निदेशक (लेखा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं अर्थात् :—

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुस्तिक बल, सहायक निवेशक (सेखा) भर्ती नियम, १९९५ है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमानः—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाध्यक्ष अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएँ—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उसमें संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त ग्रन्तसची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विविर्दिष्ट हैं।

4. निर्धनता : वह व्यक्ति:-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; उक्त पद पर नियमित का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ग्रे-से व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्त्रीय विधि के अधीन अनुशेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह शक्ति है कि ऐसा करना आवश्यक या सभीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उल्लंघन को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश बारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति:-—इत नियमों की कोई बात ऐसे ग्राहकण, आयु सीमा से छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकारद्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुमूलित जातियों, अनुमूलित बनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो लिए विवित शायु और जैक्षिक अर्हताएं प्रोफ्रेशन व्यक्तियों की वशा में लागू होगी या नहीं

8

9

10

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोफ्रेशन द्वारा या प्रति-
नियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोफ्रेशन/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोफ्रेशन/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

11

12

प्रोफ्रेशन द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्था-
नान्तरण द्वारा

प्रोफ्रेशन :

ऐसा संयुक्त सहायक निदेशक (लेखा) लिखा परीक्षा अधिकारी जिसने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर संयुक्त सहायक निदेशक (लेखा) लिखा परीक्षा अधिकारी और अनुभाग अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी की श्रेणियों में कुल भिलाकर आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : 1. इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को संयुक्त सहायक निदेशक (लेखा) लेखापरीक्षा अधिकारी के पद के ऐसे नियमित पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है प्रोफ्रेशन के लिए पात्र बने रहेंगे।

टिप्पण:— 2. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोफ्रेशन के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से एक वर्ष से अधिक से कम न हो और उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण:

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी:—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने 2200—4000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, या

(iii) जिन्होंने 2375—3500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर सात वर्ष नियमित सेवा की है, या

(iv) जिन्होंने 2000—3500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है, और

(v) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएँ और अनुभव हैं :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से छिंगी या समतुल्य
- (ii) किसी सरकारी कार्यालय या निकाय या वाणिज्यिक संगठन में पर्यवेक्षी हैंसियत में प्रशासन, लेखा और स्थापन कार्य का पांच वर्ष का अनुभव।

पांच वर्ष के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोफ्रेशन की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काढ़ बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकारी आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम सार्विक को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोफ्रेशन समिति है तो उसकी संरक्षना

भर्ती करने में किन भरिस्यतियों में संबंध लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

**समूह “क” विभागीय प्रोफ्रेशन समिति
(प्रोफ्रेशन के संबंध में विचार करने के लिए)**

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष
2. महानिवेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल—सदस्य
3. संयुक्त सचिव (पुलिस) गृह मन्त्रालय—सदस्य

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फ. सं. आई-45027/61/93/कार्मिक-2]

एन. जे. थामस, डैस्ट्रिक्ट अधिकारी

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 11th September, 1995

G.S.R. 427.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Reserve Police Force Assistant Director (Accounts) Recruitment Rules, 1971, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Accounts) in the Central Reserve Police Force, namely :—

1. (1) Short title and commencement.—These rules may be called the Central Reserve Police Force, Assistant Director (Accounts) Recruitment Rules, 1995.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said post, age limit qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in

consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Assistant Director (Accounts)	4* (1995) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Non-Ministerial	R.s. 3000 -100-3500- 125-4500/-.	Selection	Not applicable.
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972		Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled up by various methods
7	8	9	10	11	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion failing which by transfer on deputation.	
In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made		If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments	
12	13	14			
Promotion:	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion			
Joint Assistant Director (Accounts)/Audit Officer with 7 years' regular service in the grade failing which 8 years' combined regular service in the grades of Joint Assistant Director (Accounts)/Audit Officer and Section Officer/Administrative Officer	1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman. 2. Director General, Central Reserve Police Force—Member 3. Joint Secretary Police, Ministry of Home Affairs— Member				
Note: 1. The existing regular incumbents of the post of Joint Assistant Director (Accounts)/Audit Officer on the date of notification of these rules shall continue to be eligible for promotion with 5 years regular service in the grade.					

Note: 2. Where the juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period.

Transfer on deputation:

Officers under the Central/State Governments:—

- A. (i) Holding analogous posts on regular basis;
OR
(ii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent;
OR
(iii) with 7 years' regular service in posts in the scale Rs. 2375-3500 or equivalent;
OR
(iv) with 8 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent;
AND
- B. Possessing the following qualifications and experience :-
(i) Degree of a recognised University or equivalent.
(ii) Five years' experience of administration, accounts and Establishment work in a supervisory capacity in a Government office or Body or Commercial Organisation.

The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for Consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of application).

[File No. I-45027/61/93-Pers. II]

N. J. THOMAS, Desk Officer

की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 309 में निम्नलिखित सुधार किया जाय :

गुम्बिपत्र

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1995

सा.का.नि. 428.—भारत के राजपत्र भाग II
खंड 3, उपखंड (1) में पृष्ठ 1460 से 1470 पर प्रकाशित
भारत सरकार गृह मंत्रालय की दिनांक 1 जुलाई 1995

1. अनुसूची के स्तम्भ 7 में दोनों पदों अर्थात् सहायक निवेशक (विधि) और सहायक निवेशक (प्रबक्षा) के लिए “नहीं” शब्द के स्थान पर “लागू नहीं” शब्द अन्तःस्थापित किए जायें।

2. अनुसूची के स्तम्भ 12 में दोनों पदों अर्थात् सहायक निदेशक (विधि) और महायक निदेशक (प्रबन्धन) के लिए अंतिम पैराग्राफ में “प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पकालिक संविदा सहित)/स्थानान्तरण के लिए अधिकतम आयु सीमा” के स्थान पर “स्थानान्तरण” शब्द को हटा कर “प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा” वाक्य अन्तःस्थापित किया जाये।

[फा. सं. 5/2/95-एन.ई.-II]

श्रीमती एम. तोषेंग, निदेशक
(एन ई सी)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th September, 1995

G.S.R. 428.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 309 dated

the 1st July, 1995, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) at pages 1460 to 1470, the following may be corrected :—

- In Column 7 of the Schedule for both the posts i.e. Assistant Director (Law) and Assistant Director (Lecturer), the words 'Not applicable' may be inserted in place of word 'No'.
- In Column 12 of the Schedule for both the posts i.e. Assistant Director (Law) and Assistant Director (Lecturer) in the last paragraph, the sentence 'Maximum age limit for transfer on deputation (including short-term contract)' may be inserted in place of 'Maximum age limit for transfer on deputation (including short-term contract)/transfer by deleting the words 'transfer'.

[F. No. 5/2/95-NE.II]

SMT. L. TOCHHONG, Director (NEC)

आयु प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1995

सा. का. नि. 429.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मात्रियकी सर्वेक्षण (ज्येष्ठ मात्रियकी वैज्ञानिक/ज्येष्ठ मात्रियकी वैज्ञानिक (प्रबोधन और विस्तार), मात्रियकी वैज्ञानिक और सर्विस इंजीनियर (यांत्रिक) भर्ती नियम, 1987 का संशोधन करते के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मात्रियकी सर्वेक्षण (ज्येष्ठ मात्रियकी वैज्ञानिक/ज्येष्ठ मात्रियकी वैज्ञानिक) (प्रबोधन और विस्तार), मात्रियकी वैज्ञानिक और सर्विस इंजीनियर (यांत्रिक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 है।
(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय मात्रियकी सर्वेक्षण (ज्येष्ठ मात्रियकी वैज्ञानिक/ज्येष्ठ मात्रियकी वैज्ञानिक (प्रबोधन और विस्तार), मात्रियकी वैज्ञानिक और सर्विस इंजीनियर (यांत्रिक) भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची में, ज्येष्ठ मात्रियकी वैज्ञानिक और ज्येष्ठ मात्रियकी वैज्ञानिक (प्रबोधन और विस्तार) के पद से संबंधित क्रम सं. 1 और उनमें संबंधित प्रविधियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों को सं.	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले अधिकारी	सेवा में जोड़े गए वर्षों का
1	2	3	4	5	व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	फ्रायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) f. 1972 के नियम 30 के अधीन अनुसंधान या नहीं।
1. ज्येष्ठ मात्रियकी वैज्ञानिक	15*	साधारण केन्द्रीय मेवा, समूह "क"	3000-100-3500-125-4500 रु. राजपत्रित अननुसन्चितवाय	पदन	40 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा आरी किए गए अनुदेशों वा	हाँ

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

अननुसन्धानीय

आदेशों के अनुसार भरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पणः—आयु-सीमा अबधारित करने के लिए निष्पायक तारीख भारत में अध्याधियों में आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अण्णाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिक्रोम, जम्मू कश्मीर राज्य के नहार खड़, हिमाचल प्रदेश के नाहोल और सीति जिले तथा चम्बा जिले के पांची उपखंड, अंडमान और निकोद्वार द्वीप या लक्षद्वीप के अध्याधियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के अधेक्षित शैक्षिक और अन्य अहंताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक प्रहृताएं प्रोत्तत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं

परिवेक्षा की अवधि, यदि कोई हो

8

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय में प्रमाणित विज्ञान या समृद्धी जीवविज्ञान या सात्स्विकी प्रबंध या समृद्धी विज्ञान में मास्टर डिप्लोमा या समतुल्य या

केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुवर्रि में सात्स्विकी विज्ञान में स्नातकोनर डिप्लोमा या समतुल्य,

- (ii) समृद्धी भास्त्विकी जिसके अंतर्गत परि भ्रमण योजना और समृद्धी भास्त्राओं में भाग लेना भी है, के सर्वेक्षण या अनुसंधान में पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पणः—1. अहंताएं अन्यथा मुअहित अभ्य विद्यों की दशा में संच लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

9

आयु : नहीं

शैक्षिक अहंताएं : हाँ

10

सीधी भर्ती के लिए एक धर्य

(8)

टिप्पण :—2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हता एं) संघ लोक सेवा आयोग के विचारकानुसार अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के अध्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अध्यर्थियों के प्राप्ति संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

वांछनीय:—मत्स्य गियर प्रौद्योगिकी में अनुभव।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्हति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

प्रोन्हति/प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनमें प्रोन्हति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।

(11)

33.33 प्रतिशत प्रोन्हति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।
33.33 प्रतिशत सीधी भर्ती।

33.33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्हति :

ऐसा मात्रिस्थकी वैज्ञानिक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कृषि विष्वविद्यालय/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों/अर्ध-सरकारी/कानूनी या स्वप्राप्ती संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 2200—4000 रु. या समतुल्य वेतन-मान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने 2000—3500 रु. या समतुल्य वेतन-मान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण:—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्हति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्हति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके

(12)

अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अधिक है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोफेशन समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(13)

(14)

समूह "क" विभागीय प्रोफेशन समिति (प्रोफेशन के संबंध में विचार सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति/संविदा पर अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए)

भर्ती करते समय, संघ लोक सेवा आयोग से फरमार्ज करना आवश्यक है।

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष
2. संयुक्त संचिव (प्रशासन), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय—
—सदस्य
3. महानिदेशक, भारतीय मार्टियकी संबोधण—सदस्य
समूह "क" विभागीय प्रोफेशन समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)।
1. संयुक्त संचिव (प्रशासन), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
—अध्यक्ष
2. महानिदेशक, भारतीय मार्टियकी संबोधण—सदस्य

टिप्पणी:—संघ भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोफेशन समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोफेशन समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में किए जाएंगी।

[सं. 2-27/92-एफ वार्ड (प्रशासन)]

ओ. पी. जैन, अवर सचिव

टिप्पणी—मख नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 15 अगस्त, 1987 में सा. का. नि. 623 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi, the 29th August, 1995

G.S.R. 429.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Fishery Survey of India (Senior Fisheries Scientist/Senior Fisheries Scientist (Monitoring & Extension), Fisheries Scientist and Service Engineer (Mechanical) Recruitment Rules, 1987, namely :—

(i) These rules may be called the Fishery Survey of India Senior Fisheries Scientist/Senior Fisheries

Scientist (Monitoring & Extension)/Fisheries Scientist and Service Engineer (Mechanical) Recruitment (Amendment) Rules, 1995.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Fishery Survey of India (Senior Fisheries Scientist/Senior Fisheries Scientist (Monitoring & Extension), Fisheries Scientist and Service Engineer (Mechanical) Recruitment Rules, 1987, for serial number 1 relating to the post of Senior Fisheries Scientist and the entries relating thereto/Senior Fisheries Scientist (Monitoring & Extension) the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection or non-selection post.
1	2	3	4	5
"1. Senior Fisheries Scientist	15* 1995 *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3000-100-3500-125- 4500/-.	Selection

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions
Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)			

Note :—The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangj Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

6	7	8	9
Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)	Essential :— (i) Master's Degree in Zoology or Marine Biology or Fisheries Management or Oceanography of a recognised University or equivalent. OR Post-Graduate Diploma in the Fisheries Science of the Central Institute of Fisheries Education, Bombay or equivalent; and (ii) 5 years experience in Survey or research of Marine Fisheries including cruise planning and participation in voyages. Note :—(1) The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note :—(2) The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing	Age :—No. Educational Qualifications :— Yes.	

requisite experience are not likely to
be available for filling up the vacancies
reserved for them.

Desirable:—

Experience in Fishing Gear Technology

Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/Transfer and percentage of the vacancy to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/Deputation/Transfer, grades from which Promotion/Deputation/Transfer to be made
----------------------------	--	---

10	11	12
1 year for direct recruits	<p>33.33% promotion failing which by transfer on deputation including short term contract.</p> <p>33.33% direct recruitment.</p> <p>33.33% transfer on deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.</p>	<p>Promotion :— Fisheries Scientist with 5 years regular service in the grade.</p> <p>Transfer on Deputation (including short term contract) :— Officers under Central/State Governments/Union Territories/ Agricultural Universities/Indian Council of Agriculture Research/Recognised Research Institutions or Councils/ Semi-Government/Statutory or Autonomous Organisations:</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) With 5 years regular service in the posts in the scale of Rs. 2000-3500/- or equivalent; and,</p> <p>(b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.</p> <p>Note :—The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)</p>

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
---	---

13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :—	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation/contract.
<p>1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman.</p> <p>2. Joint Secretary (Administration), Ministry of Food Processing Industries—Member</p> <p>3. Director General, Fishery Survey of India—Member.</p> <p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :—</p> <p>1. Joint Secretary (Administration), Ministry of Food Processing Industries—Chairman.</p> <p>2. Director General, Fishery Survey of India—Member.</p> <p>"Note :—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held."</p>	

[No. 2 27/92-Fy (Admn.)
O.P. JAIN, Under Secy.

Note : Principal Rules were published vide G.S.R. 623 of the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (i) on 15th August, 1987.

मानव संशोधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 30 अगस्त 1995

सा.का.नि. 430 :—राष्ट्रपति, भविधान के अनुष्ठेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संलग्न अनुबंध में उल्लिखित भर्ती नियमों का अधिकरण करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिकरण में पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय/वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग वर्ग (ए) और वर्ग (बी) राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रथातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—

इन नियमों का संक्षिप्त नाम

- (i) केंद्रीय हिंदी निदेशालय/वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग वर्ग (ए) और वर्ग (बी) राजपत्रित और अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 1995 है।
- (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रबूत होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 में 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती को पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि

उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

निरहता : वह व्यक्ति—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्त नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू वैयक्तिक विधि के अधीन अनुशेष्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति

जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखावद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रबर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यापूति

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए श्रादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

टिप्पणी :

निम्न पदों के मुक्त नियम भारत के राजपत्र में निम्न प्रकार प्रकाशित किए गए थे।

- (i) मूल्यांकक (पताचार पाठ्यक्रम) सा.का. नियम 206 दिनांक 10-2-79 तथा बाद में उनमें सा.का. नियम 345 तारीख 5-4-82 द्वारा संशोधन किया गया था।
- (ii) सहायक शिक्षा अधिकारी (क्षेत्रीय भाषा) सा.का. नियम 710 तारीख 3-6-1978 तथा बाद में उनमें सा.का.नि. 721 दिनांक 28-8-82 और सा.का. नियम 859 तारीख 13/14-10-1988 के अनुसार संशोधन किया गया था।
- (iii) सहायक शिक्षा अधिकारी (पताचार पाठ्यक्रम) सा.का. नियम 887 तारीख 19-6-76 तथा बाद में सा.का. नियम 225 तारीख 11-02-1978 के अनुसार संशोधन किया गया था।

- (iv) सहायक सिक्षा अधिकारी (सामान्य) सा.का. नियम 53 तारीख 10-1-1976।
- (v) वैज्ञानिक अधिकारी—सा.का. नियम 50 तारीख 10-1-1976।
- (vi) सहायक निदेशक—सा.का. नियम 298 तारीख 15-3-1977 तथा बाद में उनमें सा.का. नियम 675 तारीख 7-8-82, सा.का. नियम 690 तारीख 17-9-83 तथा सा.का. नियम 64 तारीख 28-11-84 के अनुसार संशोधन किया गया था।
- (vii) सेक्रेटरी अधिकारी—सा.का. नियम 119 तारीख 8-1-1963 तथा बाद में उनमें सा.का. नियम 379 तारीख 13-04-1986 के अनुसार संशोधन किया गया।
- (viii) उप निदेशक (प्रदाचार पाठ्यक्रम)—सा.का. नियम 917 तारीख 6-9-1980।
- (ix) उप निदेशक—सा.का. नियम 462 तारीख 2-4-1977 तथा बाद में उनमें सा.का. नियम 205 तारीख 10-2-79 सा.का. नियम 500 तारीख 28-5-81 तथा सा.का. नियम 797 तारीख 28-7-84 के अनुसार संशोधन किया गया था।
- (x) प्रधान संपादक—सा.का. नियम 410 तारीख 13-3-1961।

प्रत्यक्षी

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	बेतनमान	प्रबलग पद	सीधे भर्ती या प्रप्रबलग पद	सेवा में किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आमु-सीमा सिविल सेवा (पेंशन)	सीधे भर्ती योग्य जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय आमु-सीमा आमु-सीमा नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुसूचीय है पा नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आमु-सीमा नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुसूचीय है पा नहीं
प्रधान संपादक	01@ 1995 (हिंदी)	साधारण कार्यभार के कार्यालय	रु. 3000-100-3500-125-	प्रबलग केंद्रीय सेवा, राजप्रदेश	सेवा में किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आमु-सीमा सिविल सेवा (पेंशन)	सामू. नहीं सामू. नहीं सामू. नहीं सामू. नहीं	सामू. नहीं सामू. नहीं सामू. नहीं सामू. नहीं	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 प्रधान संपादक	01@ 1995 (हिंदी)	साधारण कार्यभार के कार्यालय	रु. 3000-100-3500-125-	प्रबलग केंद्रीय सेवा, राजप्रदेश	सामू. नहीं सामू. नहीं सामू. नहीं सामू. नहीं	सामू. नहीं सामू. नहीं सामू. नहीं सामू. नहीं	सामू. नहीं सामू. नहीं सामू. नहीं सामू. नहीं	

परिवीक्षा	भर्ती-पद्धति :	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा	यदि विभागीय प्रोन्नति	भर्ती करते समय किम
की प्रवधि	सीधी भर्ती द्वारा या	भर्ती की दशा में के श्रेणियों जिनसे	समिति है जो उसकी संरचना	परिस्थितियों में
यदि कोई	पदोन्नति द्वारा या	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया		संघ लोक सेवा
हो	प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण	जाएगा		आयोग से परामर्श

द्वारा और विभिन्न
पदतियों द्वारा भरी
जाने वाली रिक्तियों
की प्रतिशतता

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं	<p>पदोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर अस्पता- बधि संविदा समेत प्रति- नियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।</p> <p>पदोन्नति :</p> <p>उपनिदेशक (भाषा) के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद निष्प्रसित वेतनमात्र में 2 वर्ष की सेवा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पायणि संविदा समेत) :</p> <p>केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्ता संगठनों (विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थाओं समेत) के अधीन ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क) (i) जो नियमित आवार पर सदृश पद धारक हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने रुपये 3000-4500 या समकक्ष वेतनमात्र के पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा की है; या</p> <p>(iii) जिन्होंने रुपये 2200-4000 या समकक्ष वेतनमात्र के पद पर 7 वर्ष की नियमित सेवा की है, और</p> <p>(क्ष) निम्नलिखित अर्हताओं और अनुभव वाले व्यक्ति :</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विद्य- विद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिप्लोमा या समकक्ष या</p> <p>किसी मास्टराइज़ेट विद्य- विद्यालय से संस्कृत में मास्टर डिप्लोमा या समकक्ष के साथ हिन्दी या मास्टर स्तर पर हिन्दी ग्रन्थयन का क्रियम रहा हो;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथा विज्ञान में मास्टर डिप्लोमा या समकक्ष के साथ हिन्दी या मास्टर स्तर पर हिन्दी ग्रन्थयन का क्रियम रहा हो।</p> <p>(ii) 3 वर्ष के प्रशालनिक अनुभव समेत हिन्दी/संस्कृत/भाषा विज्ञान/कोश विज्ञान में 7 वर्ष का अनुसंधान का अनुभव।</p> <p>फीडर कर्म के वे विभागीय अधिकारी जो पदो- न्नति के लिए सीधे हुक्मदार हैं उन्हें प्रति- नियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए कोश नहीं माना जाएगा।</p>	<p>मुफ 'ए' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष/सदस्य—संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 3. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय—सदस्य 3. संयुक्त सचिव/संयुक्त- शिक्षा सलाहकार (भाषा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय—सदस्य 4. अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग/निदेशक, केंद्रीय हिन्दी निदेशालय—सदस्य 	<p>किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/संविदा पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p>	

(1.2)

उसी प्रकार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्तों को पात्र नहीं माना जाएगा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धार्मिक किसी अन्य संवर्ग व्याहृति पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है, मामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा समेत) द्वारा नियुक्ति करने पर अधिकतम आयु-सीमा उम्मीदवारों से श्रावेदन-पत्र प्राप्त होने की अनिम तिथि के बिन 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. उप- निदेशक (भाषाएं) @कार्यभार के	06@ 1995	साधारण केंद्रीय सेवा,	₹. 3000-100- 3500-125-	प्रबंधन भूप 'ए'	लागू नहीं 4500	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(10)	(11)	(12)
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर अल्पावधि संविदा समेत प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण	पदोन्नति : सहायक निदेशक (भाषाएं) के पद पर नियमित नियुक्ति के बाव निर्धारित वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा।
		प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा समेत) केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठनों (विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं समेत) के अधीन ऐसे अधिकारी :
		(क) (i) जो नियमित आधार पर स्वृष्ट पद धारक हैं; या (ii) जिन्होंने रुपये 2200-4000 या समकक्ष वेतनमान के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने रुपये 2000-3500 या समकक्ष वेतनमान के पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा की है, और (ख) निस्तंत्रित अहंताओं और अनुभव वाले व्यक्ति :
		(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिप्री या समकक्ष ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत में मास्टर डिप्री या समकक्ष के साथ डिप्री या मास्टर स्तर पर हिंदी अध्ययन का विषय रखा हो ; या

12

किसी ग्रन्थनां प्राप्त विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में मास्टर डिप्लोमा समकक्ष के साथ इयरी या मास्टर स्तर पर हिंदी अध्ययन का विषय रहा हो।

(2) 3 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव समेत हिंदी/संस्कृत/भाषा विज्ञान/कोश विज्ञान में 5 वर्ष का अनुसंधान का अनुभव।

फीडर वर्ग के बे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के लिए सीधे छूटकार हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

उसी प्रकार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्तियों को पात्र नहीं माना जाएगा। (प्रतिनियुक्ति का अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य नगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य गंभीर वात्य पश पर प्रतिनियुक्ति की अवधि समिलित है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होती। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा समेत) द्वारा नियुक्ति करने पर अधिकतम आयु सीमा उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम-तिथि के दिन 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए)

(13)

(14)

ग्रुप 'ए' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)

1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष
2. गविय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय—सदस्य
3. मंत्र्युक्त मंत्रिय/संयुक्त शिक्षा भवानहकार (भाषा),
मानव संसाधन विकास मंत्रालय—सदस्य
4. अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग/
निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय—सदस्य

किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/संविदा पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. उप- निदेशक (विषय)	02 th 1995 *कार्यभार के शाधार पर परिवर्तन हो सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, राजगत्रित	रु. 3000-100- 3500-125- 4500	प्रवरण	वाग् नहीं वाग् नहीं वाग् नहीं			

(10) (11)

(12)

पदोन्नति द्वारा और ऐसा न
होने पर अल्पावधि मंत्रिय
समेत प्रतिनियुक्ति पर
स्थानांतरण द्वारा।

पदोन्नति :
महायक निदेशक (विषय) के पद पर नियमित नियुक्ति के नाव निर्धारित वेतनमात्र
में 5 वर्ष की सेवा

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि मंत्रिय समेत)
केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त यंगठनों (विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थाओं
समेत) के अधीन ऐसे अधिकारी :
(क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण हैं; या

- (2) जिन्हें रुपये 2200-4000 या समकक्ष वेतनमान के पद पर 5 वर्ष की नियमित मेवा की है; या
- (3) जिन्हें 2000-3500 या समकक्ष वेतनमान के पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा की है, और
- (4) निम्नलिखित ग्रहनों और अनुभव बाले व्यवस्था :
- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय आ समकक्ष में संबंधित विषय में मास्टर हिंगे
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इंजीनियरी, कृषि या चिकित्सा यांत्र, यथा जी शार्ट एम एस/शी ए एस एस में विद्या या फार्मसी/आयूर्वेद में डिप्लोमा या समकक्ष।
- (2) सैकेंडरी स्तर तक अंग्रेजी और हिंदी विषयों का प्रध्ययन।
- (3) डिप्लोमा/डिप्लोमा कक्षाओं के शिक्षण/प्रकारीकी लेखों या पुस्तकों के लेखन और/या अनुसाद या दोनों से संबंधित शब्दावली कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव।

(13)

प्रृष्ठ 'प' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)

1. अध्यक्ष/सदस्य—संघ लोक मेवा आयोग—अध्यक्ष
2. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय—सदस्य
3. संयुक्त मंत्रिव/संयुक्त शिक्षा मलाहकार (भाषा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय—सदस्य
4. अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग/निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय—सदस्य

(14)

किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर म्यां-तांत्रण/संविदा पर नियुक्ति करने समम संघ लोक मेवा आयोग से परामर्श ग्राहणयक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

4. सहायक निदेशक (भाषाएँ)	15* 1995 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	माध्यारण केंद्रीय सेवा, रुप 'ए' राजपत्रित श्रियिक वर्गीय	रु. 2200-75- 2800-द.रो.- 100-4000	प्रब्रण	35 वर्ष से अधिक नहीं*
--------------------------------	---	--	---	---------	-----------------------

*(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए नियोगों या आदिगों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष की सूट दी जाएगी)।

टिप्पणी :—आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों ने आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम-तिथि को माना जाएगा (न कि उस अंतिम तिथि को जो असम, बेंगलुरु, असामाजिक प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिक्रोजम जम्म एवं काशीर का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिला और चंडीगढ़ का पांची सब-डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या सक्रीय के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई है)।

(7)

(8)

(9)

(10)

मही

ग्रनिकायः :

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या संस्कृत में मास्टर डिप्लोमा या समकक्ष भाषा विज्ञान में मास्टर डिप्लोमा के साथ डिप्लोमा स्तर पर हिंदी साहित्य का विषय के रूप में अध्ययन।

(2) डिप्लोमा स्तर पर अंग्रेजी भाषा का अध्ययन।

(3) डिप्लोमा कक्षाओं के जिम्बर्जन/तकनीकी लेखों या पुस्तकों में लेखन और/या अनुवाद या दोनों में संवधित शब्दावली कार्य का 3 वर्ष का अनुभव।

वांछनीयः :

(1) हिंदी भाषा के उपयोग में संबंधित कांश विज्ञान कार्य का अनुभव।

(2) हिंदी को छाइकर कम से कम एक आष्ट्रामिक भागतीय भाषा और अंग्रेजी को छाइकर कम-से-कम एक विदेशी भाषा का ज्ञान।

टिप्पणी :

1. अन्य प्रकार से योग्य उम्मीदवारों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की इच्छा में अहंताओं में छूट दी जा सकती है।

2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग अनुभव के बारे में अहंता के लिए छूट दे सकता है। यदि चयन की किसी भी अवस्था पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि इन समुदायों के अधिकारियों के अनुसूचित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार, उनके लिए सुरक्षित किए गए स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त सम्भवा में उपलब्ध नहीं होंगे।

नहीं

सीधी भर्ती वालों के लिए एक वर्ष और पदोन्नतों के लिए दो वर्ष।

(11)

(12)

7.5 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा

ऐसा न होने पर अल्पावधि संविदा समेत प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।

दोनों प्रकार से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

2.5 प्रतिशत अल्पावधि संविदा समेत प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति :

महाप्रक शिक्षा अधिकारी (भाषा) के पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात् निर्धारित वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा समेत)

कोई ग्रन्थ सरकार/स्वायत्त भंगठनों (विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थाओं समेत) के अधीन एम्स अधिकारी :

(क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारक हैं; या

(2) जिन्होंने रुपये 2000-3200 या समकक्ष वेतनमान के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की है; या

(3) जिन्होंने रुपये 1640-2900 या समकक्ष वेतनमान के पद पर 7 वर्ष की नियमित सेवा की है, और

(द) कांलम 8 में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अहंताएं और अनुभव रखने वाले फीडर वर्ग के वे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के लिए सीधी हकदार हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

उम्री प्रकार पद्मनीत आवि नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्ति को पाने नहीं माना जाएगा।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि ग्रिसरों केंद्रीय नश्कार के उसी या किसी अन्य गंगडन/विभाग में इस नियुक्ति से शुरू पहले धारण किसी अन्य वर्ग नालू पर प्रतिनियुक्ति की अवधि समिक्षित है सामान्यतः तीन वर्ष से प्रधिक नहीं होती। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अन्यावधि समिदा समेत) द्वारा नियुक्ति करने पर अधिकतम आयु सीमा उम्रीदिवांगों से आषेदन-पत्र प्राप्त होने वी अंतिम-तिथि के दिन 56 बारे में अधिक नहीं होती चाहिए।)

(13)

(14)

ग्रुप 'ए' विभागीय प्रोन्ति समिति (प्रोन्ति पर विचार करने के लिए)।

1. अध्यक्ष/सदस्य—संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष
2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव (भाषा)/संयुक्त शिक्षा सलाहकार (भाषाएं), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)—सदस्य
3. अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग/निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय—सदस्य
4. निदेशक (भाषा)/उप सचिव (भाषाएं)/उप शिक्षा सलाहकार (भाषाएं), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)—सदस्य

ग्रुप 'ए' विभागीय प्रोन्ति समिति (स्थायोकरण के विचार के लिए)

1. अपर सचिव/संयुक्त सचिव (भाषाएं)/संयुक्त शिक्षा सलाहकार (भाषाएं), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)—अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग/निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय—सदस्य
3. निदेशक (भाषाएं) उपसचिव (भाषाएं)/उप शिक्षा सलाहकार (भाषाएं), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)—गदस्य

टिप्पणी : सीधी भर्तों वाले अधिकारियों के स्थायोकरण में संबंधित विभागीय प्रोन्ति समिति के कार्यवृत्त अनुमोदन के लिए आयोग को भेजे जाएंगे। यदि, इन पर आयोग अनुमोदन नहीं देता है तो संघ लोक सेवा आयोग के पाण्यत मा उस के सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्ति गमिति की एक और बैठक बुलाई जाएगी।

1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. सहायक निवेशक (विषय)	11* * 1095	सामारण कंपनी सेवा सुप 'ए'	₹. 2200-7-5- 2800-इ. रु.-	प्रगति 100-4000	35 अर्थ से अधिक नहीं* (केन्द्रीय भवकार द्वारा आई किए गए निवेशों या आवेशों के मनु- सार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी)	नहीं

गफता है।

टिप्पणी :—ग्राम-सीमा के निवारण के लिए नियमिक लिविंग्स में उम्मीदवारों से प्रावेदन-पत्र प्राप्त होने की अनियमितियाँ को माना जाएगा (त कि उस अनियमिति को जो भवसम, भेषालय, प्रलग्नाज्ञान, प्रदेश, मिओरम, मणिपुर, नागालैंड, किंगुरा, त्रिपुरा, अस्सी पर्व कवचीर का लदाख इत्यीजन हिमाचल प्रदेश के स्वीति जिला और चुम्बा जिला का पार्वा सद-शिखीजन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या असमीय के उम्मीदवारों के निवारण की गई है।)

टिप्पणी :

1. अन्य प्रकार के बांधकांड-बारों के संबंध में संघ द्वारा सेवा आयोग की इच्छा में प्रहृताजीवे लृदशी जा सकती है।

2. अनुसूचित जातिवी और अनुसूचित जनजातियों से भविष्यत उम्मीदवारों के भावसम में संघ द्वारा सेवा आयोग अनुबंध के बारे में जहांता के लिए कृष्ट देतकता है। वहि बदल की विधी भी अस्त्रो पर संघ द्वारा सेवा आयोग का यह भूत हो कि इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार, उनके लिए कृतज्ञता किए गए स्थानों को भरने के लिए प्रतित सज्जा में उपलब्ध नहीं होंगे।

(8)

(9)

(10)

अनियमित :

(1) किंगी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय गे संविधित विषय में
मान्यदर डिप्लोमा या गमकक्ष

या

दिल्ली मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय/बोर्ड से इंजीनियरी, कॉर्चिया या
चिकित्सा शास्त्र यथा वी आई एम एम/की ए प्रॅक्टिस में डिप्लोमा या
या फार्मेसी/आयुर्वेद में डिप्लोमा या समकक्ष।

(2) सैक्योडी ल्लर पर अंग्रेजी और डिप्लोमा विषयों का प्राप्तवयन

(3) डिप्लोमा/डिप्लोमा काक्षालयों के शिक्षण/तकनीकी लेखों या पुस्तकों
के लेखन और/या अनुयाद या दानों में संबंधित
प्रश्नोत्तरी कार्यों का 3 यर्थों का अनुभव।

बाठनीय :

(1) इसी लाइसेंस से संबंधित कोण विज्ञान कार्य वा
अनुभव।

सीधी भतीजों के लिए एक यर्थ और
प्रोफेशन के लिए दो यर्थ

(8)

- (2) हिंदी को छोड़कर कम से कम एक आधुनिक भारतीय भाषा और अंग्रेजी को छोड़कर कम से कम एक विदेशी भाषा का ज्ञान।

(11)

५० प्रतिशत पदोन्नति द्वारा देसा न तोने पर प्रल्पावधि संविदा अमेत प्रतिनिधि-
नियम पर स्थानांतरण द्वारा।
दोनों प्रकार से न द्वाने वार सीधी भर्ती द्वारा।

५१ प्रतिशत प्रल्पावधि संविदा अमेत प्रतिनिधि-नियम पर स्थानांतरण द्वारा देसा न
होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(12)

पदोन्नति :
सहायक शिक्षा अधिकारी (विषय) के पर पर नियमित नियुक्ति के
पश्चात् निर्धारित बेतनमात्र में ५ वर्ष की देवा।

प्रतिनिधि-नियमित पर स्थानांतरण (आव्यावधि संविदा अमेत)
केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठनों (विद्यविद्यालय और अनुसंधान
संस्थाओं समेत) के अधीन देसे अधिकारी :-

- (क) (1) जो नियमित आवाह पर सदृश पद धारक है; या
- (2) जिन्होंने वये २०००--३२०० या समकल बेतनमात्र के वर्ष
पर ५ वर्ष की नियमित देवा की है; या
- (3) जिन्होंने वये १६४०--२८०० या समकल बेतनमात्र के वर्ष
पर २ वर्ष की नियमित सेवा की है, और
- (ज) कलिम ४ में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित प्रहसाएं और
अनुभव रखते हों।

फिर वर्ष के विभागीय अधिकारी वो पदोन्नति के लिए सीधी
इकाई है उन्हें प्रतिनिधि-नियुक्ति के लिए पात्र महीं
बना जाएगा।

उसी प्रकार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए प्रतिनिधि-नियमितों का पात्र
नहीं बना जाएगा।

(प्रतिनिधि-नियमित की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी
विषय संगठन/विभाग में इन नियुक्ति से ऊपर पहुंचे आरित किसी
विषय संबंध वाह्य पद पर प्रतिनिधि-नियमित की अवधि सम्मिश्रित है,
यद्यपि वर्ष में जटिल महीं होगी। प्रतिनिधि-नियमित पर स्थानांतरण
(आव्यावधि संविदा अमेत) द्वारा नियुक्ति फरने पर अधिकतम
आधुनिक उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अतिम-
तिथि के दिम ५८ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।)

(13)

- बुप 'ए' विभागीय प्रोफ्रेसि नमिसि (प्रोफ्रेसि पर विचार करने के लिए)
1. अध्यक्ष/सदस्य—सेवा भाषीय
2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव भाषाएं)/संयुक्त शिक्षा सलाहकार
(भाषाएं), मानव संसाधन विकास अंतरालय (शिक्षा विभाग) --सदस्य
3. अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी अव्यावसी आधोग/निदेशक,
केन्द्रीय हिंदी निदेशालय
4. निदेशक (आधोग/उप सचिव (आधोग)/उप शिक्षा सलाहकार
(आधोग) मानव संसाधन विकास अंतरालय (शिक्षा विभाग) --सदस्य

बुप 'ए' विभागीय प्रोफ्रेसि समिति (स्वार्वीकरण के लिए)

- 1. अपर सचिव/संयुक्त सचिव (आधोग/संयुक्त शिक्षा सलाहकार
(आधोग), मानव संसाधन विकास अंतरालय (शिक्षा विभाग) --अध्यक्ष
- 2. अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी अव्यावसी आधोग/निदेशक,
केन्द्रीय हिंदी निदेशालय --सदस्य
- 3. निदेशक (आधोग) उप सचिव (आधोग/उप शिक्षा सलाहकार
(आधोग) मानव संसाधन विकास अंतरालय (शिक्षा विभाग) --सदस्य

(14)

प्रत्येक नियुक्ति के समव सब लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक
है।

(1 3) -

टिप्पणी :-—सीधी सर्त वाले भविकारियों के स्थायीकरण से संबंधित विभागीय प्रोत्स्थि भवित्व के कार्यकूल घनस्तोत्रम् के लिए आवोग को भेजे जाएं। यदि इन पर आवोग अमुदादन नहीं देता तो उच्च सीधे सेवा आवोग के अध्यक्ष या उसके सदस्य को अधिकाता में विभागीय प्रोत्स्थि भवित्व की एक और बैठक मुलायी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
६. सहायक लिखा घटिकारी (भावा)	२३*	माहारण केन्द्रीय सेवा मुप 'भी' राज्यवित्त आवार पर परिवर्तन हो मकान है।	स. २०००-६०- २३००-६०-१० ७५-३२००	प्रमधरण	लागू नहीं	नहीं
(8)		(9)			(10)	
लागू नहीं		नहीं			लागू नहीं	
(11)					(12)	

पदोन्नति द्वारा और दैवतों द्वारा द्वारा होते परं प्राप्तिवाचि संविदा मन्मह प्रतिनिष्ठुकित धर
स्थानांतरण द्वारा

पर्याप्ति :
अनुसंधान सहायक (हिन्दी) अनुसंधान सहायक (कोशीय भाषाएँ)
मूल्यांकक (प्राचीन पाठ्यक्रम) और मूल्यांकक
(थ्रेशोव भाषाएँ) के पद पर नियुक्ति के बावजूद नियारित वेदानुसंधान
में दो वर्ष की सेवा।

टिप्पणी :—पदोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारी द्वारा भर्तव्यत
बेतनमान/पद के लिए निर्धारित ग्रहणक्षेत्र पूरी करने की निर्धा
के मार्ग में वैज्ञान की जगाए !

प्रातिपिण्डि वर स्वानांतरण (अन्वाधिभविदा समेत) केन्द्रीय/राज्य मरकार/स्वावृत्त संगठनों (यिष्विद्वायथ और अनुसंधान संस्थाओं समेत) के मध्येन पैदे प्रधिकारी:

- (क) (१) जो नियमित भाषार पर सदृश पद द्वारक है; या
 (२) जिन्होंने उपरे 1640-2900 या सभकथा बैतंगाल के पद
 पर 2 वर्ष की नियमित सेवा की है; या

(३) जिन्होंने उपरे 1400—2300/2600 या सभकथा बैतंगाल
 के पद पर 7 वर्ष की नियमित सेवा की है; और

(ख) निम्नलिखित अर्द्धताओं और अमुमन वा व्यक्ति :

(१) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में हिन्दी या संस्कृत में मास्टर
 डिप्लोमा या सभकथा
 या

भाषा विज्ञान में मास्टर डिप्लोमा और उसके साथ हिन्दी स्तर पर
 हिन्दी साहित्य का विषय के रूप में प्रधायन।

(२) डिप्लोमा स्तर पर प्रधायी का विषय के रूप में प्रधायन।

(३) हिन्दी/डिप्लोमा कक्षाओं के शिक्षण तकनीकी सेवाओं या पुस्तकों
 के लेखन और/या अन्याय या दोषों से संबंधित शास्त्रावली
 पार्थ का 2 वर्ष का भ्रमण।

फीहर वर्ग के बड़े विभागीय अशिकारी जो व्याप्रति के लिए सीधे हकदार हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति द्वारा सिस्टम के लिए धान नहीं माना जाएगा।

(12)

उसी प्रकार विभिन्न दाय नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्तियों को पास नहीं जाना जाएगा।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय गरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति में ठीक पहले घारित किसी अन्य संबंध बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है, तो सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि भविता भवेत्) द्वारा नियुक्ति करने पर अधिकारम आपु भीमा उमीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अनिवार्यता के दिवं 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(13)

(14)

दूसरे 'बी' विभागीय प्रोविन्सि समिति (परोक्षति के लिए)

1. अध्यात्म, वैज्ञानिक तथा तकनीकी अव्यावसी प्रायोग/निवेशक, केन्द्रीय हिन्दी निवेशसमिति

—अध्यात्म

2. निवेशक (भाषाएं) उच्च सचिव (भाषाएं)/उच्च विभागीय समिति विभाग या उनका उपयुक्त उच्च भाषा नियमित

—तदस्य

3. सचिव, वैज्ञानिक तथा तकनीकी अव्यावसी प्रायोग/प्रबाल हृषीकेश नियमित हिन्दी निवेशसमिति

—सदस्य

किसी विभिन्नार्थी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/संविधा पर नियुक्ति करने से सम्बन्ध सोक सेवा प्रायोग से परामर्श आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. सहायक विभागीय विभिन्नार्थी (विषय) क्रमांक परिवर्तन ही मकान है।	68* (1995)	साथारण केन्द्रीय विभागीय 'बी' कार्यभार के आवार वर परिवर्तन ही मकान है।	व. 2600-60- नेवा प्रूप 'बी' ग्रामपत्रित ग्रामपत्रित	अप्रवरण 2300-व. रो.- 75-3200	लागू नहीं	लागू

(8)

(9)

(10)

लागू नहीं

नहीं

लागू नहीं

(11)

(12)

परोक्षति द्वारा और देश में होने पर अस्यावधि भविता भवेत् प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण होता

पदोन्नति :

अन्यसंबंधीय सहायक (विषय) के पद पर विभिन्न के भाव विवरित वेसनमान में वीर्य की सेवा।

ट्रिप्पली :—परोक्षति के लिए पात्रता सूची अधिकारी द्वारा संबंधित वेसनमान पद के लिए निर्धारित अर्हक गेवा पूरी करने की विधि के मध्यमे से सैयार की जाएगी।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि भविता भवेत्)

केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्कावल संगठनों (विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थाओं समेत) के ग्रामीण ऐसे विभिन्नार्थी :

(क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारक हैं; या

(2) जिन्होंने लग्ज 1640—2900 वा समकक्ष वेसनमान के पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा की है; या

(3) जिन्होंने लग्ज 1400—2300/2600 वा समकक्ष वेसनमान के पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा की है, और

(12)

(क) रिम्लिंगित प्रहंताओं और अनुभव याने व्यक्ति :—

(1) किसी भाष्यना प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में भास्टर डिप्लोमा ग्रहन करना।

कियी भाव्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/वोर्ड में हजारिन्हरी, कृपि या
त्रिक्षणा गाव्य, या वी भार्तीय प्रभुवी ए अस एन इंडिया
ए फार्मेसीशार्ट्स्टोले दें चिनोमोगा ए लग्गद

भागा विज्ञान में साइटर डिप्री और उसके साथ डिप्री स्पर पर हिन्दी साइंस ला विग्यान के स्पष्ट में व्याप्ति।

(३) इसी स्तर पर अंग्रेजी का विषय के रूप में अध्ययन।

(1) दिग्गी/डिल्लीमा कथाओं के शिखण्/तकरीबि लेखों या पुस्तकों के नियन्त्रण शीर्ष/या अनुवाद या डीनों में संबंधित गवाहाचली कार्यों पर उचित वा अनुमति।

फीरने वाले के देव विमानीय अधिकारी जो पदोन्नति के लिए भीते हुए दावा हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति द्वारा नियमित में लिये जाते रहेंगे।

उसी प्रकार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए प्रशिक्षित की जाती है।

(प्रतिनियुक्ति की शब्दियि जिसमें केंद्रीय मन्त्रालय के उसी पर किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी भव्य संबंधी बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की शब्दियि सम्मिलित भावान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होती। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (प्रत्यावर्ति संविदा समेत) द्वारा नियुक्ति करने पर अधिकतम प्राप्त सीदा उम्मीदवारों से भावेन्द्रन-पत्र प्राप्त होते की अंतिम नियिके दिन 56 वर्ष से प्रधिक नहीं होती चाहिए।)

(13)

(14)

ग्रुप 'सी' विभागीय प्रोक्षणि समिति (पदोक्षणि के लिए) :

- प्रध्याद, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का प्रयोग निर्देशक, केन्द्रीय हिंदी निवेशालय - प्रध्याद
 - निर्देशक(भाषाएं)/उप सचिव (भाषाएं)/उप प्रियां भलाहकार (भाषाएं), शिक्षा विभाग या उनका उपर्युक्त पद कानून नियमित - मतस्थ
 - यन्त्रित, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली प्रायोग प्रधान संपादक केन्द्रीय हिंदी निवेशालय - संपादक

किसी भ्रष्टाचारी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानीयतरण/संविदा पर नियुक्ति
परने मध्ये संघ लोक सेवा आयोग से परमार्थी आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. मूल्यांकक (पत्र चार पाठ्यक्रम)	27* 1995	साधारण केन्द्रीय सेवा यूप 'बी' अराजपत्रित आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	रु. 1640-60- 2600-रु. 20.- 75-2900 प्रान्तिकवर्गीय	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं / केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए सारेंगों या निवेदों के प्रत्युत्तर सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष की कृद दी जाएगी)	महीं

(8)

(9)

(10)

प्रभावीय :

- (i) किसी माध्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर विषय
या समकक्ष के साथ हिन्दी स्तर पर अंग्रेजी का विषय के
रूप में प्रश्नावली।

या

किसी माध्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में मास्टर
विषय या समकक्ष के साथ हिन्दी स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी
का विषयों के रूप में प्रश्नावली।

- (ii) द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दीशिक्षण का कल-से कम दो
वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

- (i) हिन्दी के अतिरिक्त किसी प्राचुर्यिक भारतीय भाषा का
ज्ञान
- (ii) किसी माध्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भिक्षा में हिन्दी या
एल्लोमा या समकक्ष
- (iii) किसी माध्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित
भाषा विज्ञान/भाषा विज्ञान प्रशिक्षण में प्रशिक्षण या भागी-
दारी।

टिप्पणी :

- अन्य प्रकार से योग्य उम्मीदवारों के संबंध में संघ नोक
सेवा आयोग की इच्छा से अंहृताओं से छूट दी जा सकती है।
- अनुभुवित अंतिमों और अनुभुवित अनुआतियों से संबंधित
उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग अनुभव के
बारे में अंहृता के लिए छूट दे सकता है। यदि अयम् की किसी
भी अधिकारी पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो
कि इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार,
उनके लिए मुरक्कित किए गए स्थानों को भरने के लिए
पर्याप्त संक्षय में उपलब्ध नहीं होते।

(11)

(12)

सीधी भर्ती :

माग, नहीं

टिप्पणी :

एक वर्ष या अधिक अवधि तक पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर
स्थानांतरण या लंबी बीमारी या मध्यवाहार्य सूखी या
अन्य परिस्थितियों के कारण बुए रिक्त पदों को नियुक्ति
प्रधिकारी प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के आधार पर
केंद्रीय सरकार के रूप से प्रधिकारियों में से भर सकता है:

- (क) जो नियमित आधार पर सदूषयदधारक हैं या रु. 1400-
2300/2600 या समकक्ष लेनदेन में 5 वर्ष भी नियमित
सेवा पूरी कर चुके हैं; और
- (ख) जो कालम 8 में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अंहृताएं
और अनुभव रखते हों।

टिप्पणी :—प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति करने के
लिए अधिक आयु सीमा उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त होने
की अंतिम तिथि के दिन 56 वर्ष से अधिक नहीं होती जाहिं।

टिप्पणी :—आयु सीमा के निर्णायक के लिए निर्णायक तिथि भारत
में उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को
माना जाएगा (न की उम्मीदवारों की अंतिम तिथि को जो अंतर्मुक्त,

ग्रहणात्मक प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, विपुरा, सिक्खिम, अस्सी एवं कश्मीर का लक्ष्य इवीजन, हिमाचल प्रदेश का स्तीति जिला और चम्बा जिला का पांची सब इवीजन, अस्सी न और निकोबार हीपसमूह या लक्ष्यीय के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई।

(13)

उप 'बी' विभागीय प्रोफ्रेशन/समिति (स्थायीकरण के लिए)

1. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय —प्रधान
2. निदेशक (भाषाएं)/उप सचिव (भाषाएं), मानव संसाधन विकास मंत्रालय या उपयुक्त पर वाला उनका नामिति —मंत्री
3. प्रधान सम्पादक केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय —सदस्य
4. अनुसूचि जाति/अनुसूचित जनजातियों समुदाय का अपूर्ण प्रधिकारी —सदस्य

टिप्पणी :—सीधी भर्ती वाले अधिकारियों के स्थायीकरण से संबंधित विभागीय प्रोफ्रेशन समिति के कार्यवृत्त अनुमोदन के लिए आयोग को भेजे जाएंगे। यदि इन पर आयोग अनुमोदन नहीं देता है तो संघ सोक सेवा आयोग के प्रधानमंत्री सदस्य की प्रध्येशता में विभागीय प्रोफ्रेशन समिति की एक और बैठक और अनुसार जाएगी।

(14)

संघ सोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त करता है।

सं. एफ. 2-16 88— प्रका.
जे. एस. सहगल, उप निदेशक (भाषाएं)

श्रनुत्पन्नक

वे भर्ती नियम जिनका अतिक्रमण किया जाना है

1. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, प्रधान संपादक भर्ती नियम-1961।
2. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय/वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, उपनिदेशक (उपनिदेशक प्रशासन को छोड़कर) भर्ती नियम 1977।
3. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, उपनिदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम) भर्ती नियम, 1980।
4. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, शेवीय अधिकारी भर्ती नियम, 1986।
5. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय/वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, सहायक निदेशक भर्ती नियम, 1977।
6. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय/वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक अधिकारी (इंजीनियर) भर्ती नियम, 1976।
7. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, सहायक शिक्षा अधिकारी (सामान्य) भर्ती नियम 1976।
8. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, सहायक शिक्षा अधिकारी एवं मूल्यांकक (पत्राचार (पाठ्यक्रम)) भर्ती नियम, 1976।
9. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, सहायक शिक्षा अधिकारी एवं मूल्यांकक (शेवीय भाषाएं) भर्ती नियम, 1982।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

New Delhi, the 30th August, 1995

G.S.R. 430.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in super session of the Recruitment Rules mentioned in the Annexure enclosed hereto except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group (A) and Group (B) Gazetted and Non-Gazetted posts. The Central Hindi Directorate/Commission for Scientific and Technical Terminology, namely :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology Group (A) and Group (B) Gazetted and Non-Gazetted posts Recruitment Rules, 1995.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Scale of Pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, and qualifications.—The method of recruitment of the said posts, age limit educational qualification and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No Person ,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—If the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

NOTE :

The Principal Rules of the following posts were Notified and Published in the Government of India Gazette as under:

(i) Evaluator (Correspondence Course) vide GSR No. 206 dated 10-02-1979 and amended vide GSR No. 345 dated 05-04-82.

(ii) Assistant Education Officer (Regional Languages) vide GSR No. 710 dated 03-06-1978 and amended vide GSR No. 721 dated 28-08-82 and GSR No. 859 dated 13/14-10-1988.

(iii) Assistant Education Officer (Correspondence Course) Vide GSR No. 887 dated 19-06-76 and amended vide GSR No. 225 dated 11-02-1978.

(iv) Assistant Education Officer (General) vide GSR No. 53 dated 10-01-1976.

(v) Scientific Officer vide GSR No. 50 dated 10-01-76.

(vi) Assistant Director vide GSR No. 298 dated 05-03-1977 and amended vide GSR No. 675 dated 07-08-82, GSR No. 690, dated 17-09-83 and GSR No. 64 dated 28-11-84.

(vii) Regional Officer vide GSR No. 119 dated 08-01-1963 and amended vide GSR No. 379 dated 13-04-86.

(viii) Dy. Director (Correspondence Course) vide GSR No. 917 dated 06-09-80.

(ix) Dy. Director vide GSR No. 462 dated 02-04-1977 and amended vide GSR No. 205 dated 10-02-79, GSR No. 500 dated 28-05-81 and GSR No. 797 dated 28-07-84.

(x) General Editor vide GSR No. 410 dated 13-03-1961.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits
--------------	----------------	----------------	--------------	---	-------------------------------	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
1. General Editor (Hindi)	01	General Central Services Group A, Gazetted	Rs. 3000-100-3500-125-5000	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

*1995 Subject to variation dependent on workload

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by Promotion/Deputation/Transfer, Grades from which Promotion/Deputation/Transfer to be made
---	----------------------------	---	---

9	10	11	12
Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by transfer on deputation including short-term contract.	Promotion: Deputy Director (Language) with 2 years regular service in the Grade. Transfer on deputation (Including short term contract)

Officers under the Central/State Government/Autonomous Organisations (including Universities and Research Institutions):

- (a) (i) Holding analogous post on regular basis; or
- (ii) With 2 years regular service in posts in Scale of Pay of Rs. 3000-4500 or equivalent; or
- (iii) With 7 years regular service in posts in Scale of Pay of Rs. 2200-4000 or equivalent, and
- (b) Possessing following qualifications and experience:

- (i) Master's Degree in Hindi from a recognised university or equivalent

OR

Master's Degree in Sanskrit with Hindi as one of the subjects of study at Degree or Master's level from a recognised university or equivalent.

OR

Master's Degree in Linguistics with Hindi as subjects of study at degree or Master's Level from a recognised university or equivalent.

- (ii) Seven years experience of research in Hindi/Sanskrit/Linguistics/Lexicography including three years Administrative Experience

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition? Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.

13

14

GROUP 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion)	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on transfer on deputation/contract.
1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman.	
2. Secretary, M/O Human Resource Development—Member.	
3. Joint Secreary/Joint Education Advisor (Language) M/O Human Resource Development—Member	
4. Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology/ Director, Central Hindi Directorate—Member.	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

2. Deputy Director @06 (Languages)	General Central Services Group A. Gazetted	Rs. 3000- 100-3500- 125-4500	Selection	Not applic- able	Not applic- able	Not applic- able
---------------------------------------	--	------------------------------------	-----------	---------------------	---------------------	---------------------

@1995

Subject to variation dependent on workload.

9	10	11	12
---	----	----	----

Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by transfer on deputation including short term contract.	Promotion: Assistant Director (Languages) with five years regular service in the grade. Transfer on deputation (Including short-term contract) Officers under the Central/State Government/Autonomous Organisations (including Universities and Research Institutions): (a) (i) Holding analogous post on regular basis; or (ii) With 5 years regular service in posts in Scale of Pay of Rs. 2200-4000 or equivalent; or (iii) With 8 years regular service in posts in Scale of Pay of Rs. 2000-3500 or equivalent; and (b) Possessing following qualifications and experience:
----------------	----------------	--	--

(i) Master's Degree in Hindi from a recognised university or equivalent.

OR

Master's Degree in Sanskrit with Hindi as one of the subjects of study at Degree or Master's level from a recognised university or equivalent.

OR

Master's Degree in Linguistics with Hindi as subjects of study at degree of Master's Level from a recognised university or equivalent.

(ii) 5 years experience of research in Hindi/Sanskrit/Linguistics/Lexicography including three years Administrative Experience.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).

GROUP 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion)

1. Chairman/Member-Union Public Service Commission—Chairman.
2. Secretary, M/O Human Resource Development— Member
3. Joint Secretary/Joint Education Advisor (Language) M/O Human Resource Development —Member
4. Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology/ Director, Central Hindi Directorate—Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on transfer on deputation/contract.

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

3. Deputy Director (Subjects)	02@ @(1995)	General Central Subject to variation dependent on workload.	Rs. 3000- 100-3500- 125-4500	Selection	Not applic- able	Not applic- able	Not applic- able
----------------------------------	----------------	--	------------------------------------	-----------	---------------------	---------------------	---------------------

9	10	11	12
---	----	----	----

Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by transfer on deputation including short term contract.	<p>Promotion:</p> <p>Assistant Director (Subjects) with five years regular service in the grade.</p> <p>Transfer on deputation (Including short term contract)</p> <p>Officers under the Central/State Government/Autonomous Organisations (including Universities and Research Institutions):</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) With 5 years regular service in posts in Scale of Pay of Rs. 2200-4000 or equivalent; or (iii) With 8 years regular service in posts in the Scale of Pay of Rs. 2000-3500 or equivalent; and (b) Possessing following qualifications and experience; <p>(i) Master's Degree in the subject concerned from a recognised university or equivalent</p>
----------------	----------------	--	---

OR

Degree in Engg. Agriculture or Medicine i.e. BIMS/ BAMS or Diploma in Pharmacy/Ayurveda from a recognised university/ board or equivalent.

- (ii) English and Hindi as subjects of study at Secondary Level.
- (iii) 5 years experience of Teaching degree/Diploma classes) Terminological work on writing technical articles or books and/or translation of both.

GROUP 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) :

1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman
2. Secretary, M/O Human Resource Development—Member
3. Joint Secretary/Joint Education Adviser (Language) M/O Human Resource Development—Member
4. Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology/ Director, Central Hindi Directorate—Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on transfer on deputation contract.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Assistant Director (Languages)	15* 1995 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group A, 2800-EB-100-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2200-75-	Selection	Not exceeding 35 yrs. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note : The Crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands of Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
No	<p>Essential :</p> <p>(i) Master's Degree in Hindi or Sanskrit of a recognised university or equivalent OR Master's degree in Linguistics with Hindi Literature as one of the subjects at Degree Level.</p> <p>(ii) English as one of the subjects of study at Degree Level.</p> <p>(iii) 3 years experience of Teaching Degree/Diploma classes/Terminological work on writing technical articles of Books and/or Translation or both.</p> <p>Desirable :</p> <p>(i) Experience of Lexicographical work involving use of Hindi.</p>	No	<p>1 year for direct recruits & 2 years for promoted.</p>	<p>75.00% promotion failing which by transfer on deputation including short term contract). Failing both by direct recrt. 25.00% transfer on deputation including short term contract failing which by direct recruitment.</p>

(8)

(ii) Knowledge of atleast one modern Indian Language other than Hindi and one Foreign Language other than English.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to all the vacancies received from them.

(12)

(13)

(14)

Promotion :

Assistant Education Officer (Language) with five years regular service in the grade.

Transfer on deputation (including short term contract).

Officers under the Central/State Government/ Autonomous Organisations (including Universities and Research Institutions):

(a) (i) Holding analogous post on regular basis; or

(ii) With 5 years regular service in posts in Scale of Pay of Rs. 2000-3200 or equivalent; or

(iii) With 7 years regular service in posts in Scale of Pay of Rs. 1640-2900 or equivalent; and

(b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/

Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion):

1. Chairman/Member—Union Public Service Commission—Chairman.
2. Additional Secretary/Joint Secretary (Languages)/ Joint Educational Advisor (Language) Ministry of Human Resource Development (Department of Education)—Member.
3. Chairman, Commission for Scientific & Technical Terminology/Director, Central Hindi Directorate—Member
4. Director (Languages)/Deputy Secretary (Languages)/ Deputy Educational Advisor (Languages), Ministry of Human Resources Development (Department of Education)—Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary each occasion.

Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering confirmation):

1. Additional Secretary/Joint Secretary (Languages)/ Joint Educational Advisor (Languages) Ministry of Human Resource Development (Department of Education)—Chairman
2. Chairman, Commission for Scientific & Technical Terminology/Director, Central Hindi Directorate—Member
3. Director (Languages)/Deputy Secretary (Languages)/ Deputy Educational Adviser (Languages), Ministry

(12)

(13)

department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer or deputation (including short-term contract) shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.

of Human Resource Development (Department of Education)—Member

"Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held."

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Director (Subjects)	11* 1995 *Subject to variation dependent on workload	General Central Services Group A, 2800-EH-100- Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2200-75- 4000.	Selection	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note : The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
No	Essential : (i) Master's Degree in Subject concerned from a recognised university or equivalent. OR Degree in Engg., Agriculture or Medicine i.e. BIMS/BAMS or Diploma in Pharmacy/Ayurveda from recognised university/ board or equivalent (ii) English and Hindi as subjects of study at Secondary Level. (iii) 3 years experience of Teaching Degree/Diploma classes/Terminological work on writing technical articles or Books and/or Translation or both. Desirable : (i) Experience of Lexicographical work involving use of Hindi.	No	1 year for direct recruits & 2 years for promoted.	50.00% Promotion failing which by transfer or deputation (including short term contract) Failing both by direct rec'tt. 50.00% Transfer on deputation including short term contract failing which by direct recruitment.

(8)

(ii) Knowledge of atleast one modern Indian Language other than Hindi and one Foreign Language other than English.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to all the vacancies received from them.

(12)

(13)

(14)

Promotion:

Assistant Education Officer (Subjects) with five years regular service in the grade.

Transfer on deputation (including short-term contract)

Officers under the Central/State Government/ Autonomous Organisations (including Universities and Research Institutions) :

(a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or

(ii) With 5 years regular service in posts in Scale of Pay of Rs. 2000-3200 or equivalent; or

(iii) With 7 years regular service in posts in Scale of Pay of Rs. 1640-2900 or equivalent; and

(b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract) shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).

Group A Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :

1. Chairman/Member—Union Public Service Commission—Chairman

2. Additional Secretary/Joint Secretary (Languages)/ Joint Educational Advisor (Language) Ministry of Human Resource Development (Department of Education).—Member

3. Chairman, Commission for Scientific & Technical Terminology/Director, Central Hindi Directorate— Member

4. Director (Languages)/ Deputy Secretary (Languages)/ Deputy Educational Adviser (Languages), Ministry of Human Resources Development (Department of Education)—Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary each occasion.

Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering confirmation):

1. Additional Secretary/Joint Secretary (Languages)/ Joint Educational Advisor (Languages) Ministry of Resource Development, Department of Education) Chairman.

2. Chairman, Commission for Scientific & Technical Terminology/Director Central Hindi Directorate— Member.

3. Director (Languages)/Deputy Secretary (Languages)/ Deputy Educational Advisor (Languages), Ministry of Human Resources Development (Department of Education)—Member.

"Note: The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be over by the Chairman or a Member" of the Union Public Service Commission shall be held.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Assistant Education Officer (Languages)	22* (1995) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200	Non-Selection	Not applicable
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
No	Not applicable	No	Not applicable	Promotion failing which by transfer on deputation including short term contract.	
(12)	(13)	(14)			
Promotion: Research Assistant (Hindi), Research, Assistant (Regional Languages), Evaluator (Correspondence Courses) and Evaluator (Regional Languages) with two years regular service in the grade. Note: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective Grade/ Post. Transfer on deputation (including short term contract): Officers under the Central/State Government/Autonomous Organisations (including Universities and Research Institutions):	Group 'B' Departmental Promotion Committee (For promotion): 1. Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology/Director, Central Hindi Directorate—Chairman 2. Director (Languages)/Deputy Secretary (Languages)/Deputy Educational Adviser (Languages), Department of Education or his nominee of appropriate status—Member 3. Secretary, Commission for Scientific and Technical Terminology/General Editor, Central Hindi Directorate—Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on transfer on deputation/ contract.			
(a) (i) Holding analogous post on regular basis; or (ii) With 2 years' regular service in posts in Scale of Pay of Rs. 1640-2900 or equivalent; or (iii) With 7 years' regular service in posts in Scale of Pay of Rs. 1400-2300/2600 or equivalent; and					
(b) Possessing following qualifications and experience: (i) Master's Degree in Hindi or Sanskrit of a recognised university or equivalent OR Master's Degree in Linguistics with Hindi Literature as one of the subjects at Degree Level. (ii) English as one of the subjects of study at Degree Level. (iii) 2 years' experience of Teaching degree/Diploma classes/Terminological work on writing teaching articles or books and/or translation or both.					
The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.					
Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.					
(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Assistant Education Officer (Subjects)	8* 1995 *Subject to variation dependent on workload	General Central Services Group B. Gazetted	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200	Non-Selection	Not applicable
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
No	Not applicable	No	Not applicable	Promotion failing which by transfer on deputation including short term contract.	
(12)	(13)			(14)	
Promotion : Research Assistant (Subjects) with two years regular service in the grade. Transfer on deputation (including short term contract) Officers under the Central/State Government/ Autonomous Organisation (including Universities and Research Institutions) : (a) (i) Holding, analogous post on regular basis; or (ii) With 2 years regular service in posts in the Scale of Pay of Rs. 1640—2900 or equivalent; or (iii) With 7 years regular service in posts in the Scale of Pay of Rs. 1400—2300/2600 or equivalent, and (b) Possessing following qualifications and experience: (i) Master's Degree in the subject concerned from a recognised university or equivalent OR Degree in engineering, Agriculture or Medicine i.e. BIMS/BAMS or Diploma in Pharmacy/Ayurveda from a recognised university or equivalent. OR Master's Degree in Linguistics with Hindi Literature as one of the subjects at degree level. (ii) English as one of the subjects of study at degree level. (iii) 2 years experience of Teaching degree/ Diploma classes/Terminological work on writing teaching articles or books and/or translation or both. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) 1. Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology/Director, Central Hindi Directorate—Chairman 2. Director (Languages)/Deputy Secretary (Languages)/ Deputy Educational Advisor (Languages), Department of Education or his nominee of appropriate status—Member 3. Secretary, Commission for Scientific and Technical Terminology/General Editor, Central Hindi Directorate—Member			Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on transfer or deputation/contract.	

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Evaluator (Correspondence Courses)	27* 1995 *Subject to variation dependent on workload	General Central Services Group B, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900	Not applicable	Not Exceeding 35 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
No	Essential : (i) Master's Degree in Hindi with English as a subject of study at Degree Level from a recognised university or equivalent. OR Master's Degree in Linguistics with Hindi and English as subject of study at Degree Level from a recognised university or equivalent. (ii) At least 2 years experience of teaching Hindi as a second language. Desirable : (i) Knowledge of any Modern Indian Language other than Hindi.	No	2 years	Direct recruitment. Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on Deputation or Long illness or Study Leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation basis by the appointing authority from officers of Central Government: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis, or with 5 years Regular Service in posts in the scale of Rs. 1400—2300/2600; and (b) Possessing the qualification & experience prescribed for Direct recruits under column 8. Note : The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State/district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

(8)

- (ii) Degree or Diploma of a recognised university or equivalent in Education with specialisation in Hindi Teaching
- (iii) Training or Participation in Linguistics/Language Teaching Training conducted by a recognised Institute/university.

Note : 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note : 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to all the vacancies received from them.

(12)

(13)

(14)

Not applicable

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) :

1. Director Central Hindi Directorate—Chairman.
2. Director (Languages)/Deputy Secretary (Languages) Ministry of Human Resources Development or his nominee of appropriate status—Member
3. General Editor, Central Hindi Directorate—Member
4. Group 'A' officer belonging to Scheduled cast/Scheduled tribe Community—Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary.

"Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held."

ANNEXURE

- The Recruitment Rules sought to be superseded:—
1. Central Hindi Directorate General Editor Recruitment Rules, 1961.
 2. Central Hindi Directorate/Commission for Scientific and Technical Terminology Recruitment Rules for the post of Deputy Director (other than Deputy Director Administration) 1977.
 3. Central Hindi Directorate Recruitment Rules for Deputy Director (correspondence Courses) 1980.
 4. Central Hindi Directorate Regional officer Recruitment Rules, 1986.
 5. Central Hindi Directorate/Commission for Scientific and Technical Terminology Assistant Director Recruitment Rules, 1977.
 6. Central Hindi Directorate/Commission for Scientific and Technical Terminology Scientific officer (Engineering) Recruitment Rules, 1976.
 7. Central Hindi Directorate, Assistant Education officer (General) Recruitment Rules, 1976.
 8. Central Hindi Directorate Assistant Education officer and Evaluators (Correspondence Courses) Recruitment Rules, 1976.
 9. Central Hindi Directorate Assistant Education officer and Evaluators' (Regional Language) Recruitment Rules, 1982.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1995

मा०का०नि० 431.—जबकि कर्मचारी राज्य शीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उपधारा (1) के अधीन यथा-अपेक्षित कर्मचारी राज्य शीमा नियम (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1993 नामक कठिपथ मसौदा नियम भारत के राजपत्र दिनांक 19 नवम्बर, 1994 के भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (1) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय सं. मा०का०नि० 575 दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 की अधिसूचना के साथ इनसे प्रभावित होने वाले सम्भावित किसी भी व्यक्ति से शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से पैंतीसिस दिन के अंदर आपत्तियां अथवा सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे।

और जबकि, उक्त मसौदा नियम शासकीय राजपत्र में 19 नवम्बर, 1994 को प्रकाशित किए गए थे।

और जबकि, मसौदा नियम की राजपत्र प्रतियां, जिनमें वे प्रकाशित किए गए थे, 19 नवम्बर, 1994 को जनता को उपलब्ध कराई गई थी।

और जबकि, इनसे प्रभावित होने वाले किसी भी सम्भावित व्यक्ति से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए और कर्मचारी राज्य शीमा नियम (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1973 के अधिक्रमण

में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों अथवा करते से से रह गए कार्यों के सिवाए, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य शीमा नियम के परामर्श के उपरान्त एतत्वाता निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:—

प्रारंभिक:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी राज्य शीमा नियम (सामान्य भविष्य निधि) नियमावली, 1995 है।
2. ये नियम इनके सरकारी गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त ममझे जाएंगे।
3. परिभाषाएँ—(1) इन नियमों में जब तक कि संबंध से अन्यथा अपेक्षित न हो—
 - (क) "लेखा अधिकारी" से अभिप्रेत है वित्त आयुक्त, कर्मचारी राज्य शीमा नियम या अन्य ऐसा अधिकारी जिसे इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए।
 - (ख) "अधिनियम" से अभिप्रेत है कर्मचारी राज्य शीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34);
 - (ग) "नियम" से अभिप्रेत है, कर्मचारी राज्य शीमा नियम।
 - (घ) "परिलिंग्यों" से अभिप्रेत है मूल नियमों में पथ-परिभाषित वेतन, छुट्टी वेतन या निवाह अनुदान और इसमें वेतन, छुट्टी वेतन या निवाह अनुदान के अनुरूप महंगाई वेतन यदि स्वीकार्य हो और प्रतिनियुक्ति के संबंध में प्राप्त वेतन की प्रकृति का कोई अन्य पारिश्रमिक भी शामिल है।
 - (इ) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त-व्यक्तियों के अतिरिक्त नियम द्वारा नियुक्त किया गया था नियम के स्टाफ के संबंध का कोई अवक्ति;
 - (ज) "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है:—
 - (i) पुरुष अभिदाता की बशा में, पत्नी या पत्नियां, माता-पिता, संतानें, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृतक पुत्र की विधवा और संतानें और जहां अभिदाता के माता-पिता जीवित नहीं हैं वहां उसके माता-पिता के पितामह या पितामही या मातामह या मातामही :

परन्तु यदि अभिदाता यह सावित कर देता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक हो गई है या वह उस समुदाय की जिसकी वह है, रुक्षजन्य विधि के अधीन उससे भरण-पोषण प्राप्त करने के हकदार नहीं रह गई है तो उसे, तब से अब सक कि अभिदाता लेखा अधिकारी को बाद में लिखित रूप में यह सूचित स करे।

कि उसे उस स्वरूप में जाना जाता रहेगा कि वह उम मामलों में जिसका संबंध इन नियमों से है, अभिदाता के कुटुम्ब की सदस्य नहीं रह गई है।

(ii) स्त्री अभिदाता की दशा में पति, माता-पिता, सन्नाने, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृतक पुत्र की विधवा और सन्नाने और जहां अभिदाता के माता-पिता जीवित न हों वहां उसके माता-पिता के पितामह या पितामही या मातामह या मातामही।

परन्तु यदि अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करके अपने कुटुम्ब से अपने पति को अपवर्चित करने की इच्छा व्यक्त करती है तो पति को जब तक कि अभिदाता बावध में ऐसी सूचना को लिखित रूप में रहने कर दे, यह समझा जाएगा कि वह उन मामलों में, जिनका संबंध इन नियमों से है अभिदाता के कुटुम्ब का सदस्य नहीं रह गया है।

स्पष्टीकरण : इस खंड में संतान में अभिप्रेत धर्मज सन्तान है और जहां अभिशाता पर लागू स्वीय विधि दसक पुत्र ग्रहण को मान्यता देती है वहां इसमें दसक संतान भी शामिल है:

- (अ) "निधि" से कर्मचारी राज्य बीमा निगम सामान्य भविष्य निधि अभिप्रेत है;
- (आ) "छट्टी" से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी-वृन्द तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 1959 द्वारा मान्य कोई भी छट्टी अभिप्रेत है;
- (इ) "सेवा" से निगम के अधीन सेवा अभिप्रेत है;
- (अ) "वर्ष" से वित्त वर्ष अभिप्रेत है।

इन नियमों में प्रयुक्त किसी अन्य पद का, जो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 या मूल नियम में परिभाषित है, उसी अर्थ में प्रयोग किया जाता है जिस अर्थ में वह उसमें परिभाषित है परन्तु इसमें परिभाषित न की गई अभिव्यक्ति का अर्थ क्रमशः भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्रीय) नियम, 1950 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारीवृन्द तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 1959 या व्यास्थित मूल नियमों में व्याप-परिभाषित होता।

3. इन नियमों की कोई बात इस प्रकार में प्रभावी नहीं समझी जाएगी जिससे कि इससे पूर्व विद्यमान भविष्य निधि की विधिमानता समाप्त होती है या कोई नई विधि गठित होती है।

3. निधि रूपदों में रखी जाएगी :

- (1) निधि रूपदों में रखी जाएगी।
- (2) इन नियमों के अधीन निधि में अदा की गई सभी राशियां "कर्मचारी राज्य बीमा निगम सामान्य भविष्य निधि"—नामक निधि में जमा की जाएगी। ऐसी राशियां जिनकी अदायगी इन नियमों के अधीन उनके देश हो जाने के पश्चात छः मास के भीतर प्राप्त नहीं कर सकी गई हैं, वर्ष के अंत में जमा लेखा को अन्तरित कर दी जाएगी और उनके संबंध में कार्रवाई जमा राशियों में संबंधित सामान्य नियमों के अधीन की जाएगी।

4. लेखा अधिकारी द्वारा निधि का संचालन :

निधि का संचालन लेखा अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे इसके द्वारा इन नियमों के अधीन की जाने वाली सभी अदायगियों की व्यवस्था के लिए प्राधिकृत किया जा रहा है।

5. निवेश

निधि से संबंधित सभी घनराशि का निवेश कर्मचारी राज्य बीमा निधि से संबंधित घनराशि के निवेश के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

6. पात्रता की शर्तें :

सभी अस्थाई कर्मचारी एक वर्ष की निरंतर सेवा के पश्चात् सभी पुनर्नियोजित पेंजनमोगी (उनमें भिन्न जो अभिदायी भविष्य निधि की मद्दत्यान के पात्र हैं) और सभी स्थायी कर्मचारी निधि में अभिशान करेंगे।

परन्तु ऐसा कोई कर्मचारी जिससे अभिदायी भविष्य निधि में अभिशान करने की अपेक्षा की गई है या जिसे ऐसा करने की अनुमति दी गई है, निधि में सम्मिलित होने या अभिदाता के रूप में बने रहने का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी निधि में अभिशान करने के अपने अधिकार को प्रतिधारित रखता है।

परन्तु यह और कि ऐसा अस्थाई कर्मचारी जो 31 मार्च, 1960 से पहले एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुका है, प्रथम अप्रैल, 1960 से पहले की किसी तारीख से निधि में अभिशान नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण :—ऐसा कोई अस्थाई कर्मचारी जो किसी मास के किसी दिन एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करता है उसके पश्चात्वर्ती मास से निधि में अभिशान करेगा।

टिप्पणी 1 :—इस नियम के प्रयोजन के लिए शिक्षुओं और परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को अस्थाई कर्मचारी माना जाएगा।

टिप्पणी 2 :—ऐसा अस्थाई कर्मचारी जो किसी मास के बीच में एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करता है उसके पश्चात्वर्ती मास से निधि में अभिशान करेगा।

टिप्पणी 3 :—ऐसे अस्थाई कर्मचारी जिनमें शिळू और परिवीक्षाधीन व्यक्ति भी शामिल हैं। जो नियमित रिक्तियों पर नियुक्त किए गए हैं और जिनके एक वर्ष में अधिक तक बने रहने की संभावना है एक वर्ष की भेज़ी पूर्ण करने में पूर्व किसी भी समय मामान्य अधिकारी निधि में अभिदाता कर सकते हैं।

7. नाम निर्देशन

(1) निधि में सम्मिलित होने के समय अभिदाता लेखा अधिकारी को एक नामांकन भेजेगा जिसके द्वारा निधि में उसके नाम जमा रकम उस रकम के देय होने में पूर्व अधिकारी देय होने पर अवायगी किए जाने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में प्राप्त करने का अधिकार किसी एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा।

परन्तु यदि अभिदाता अवधक है तो उससे नामनिर्देशन करने की आवश्यकता की आयु प्राप्त करने पर की जाएगी।

परन्तु यह और कि वह अभिदाता जिसका मामनिर्देशन करने के समय कोई कुटुम्ब है ऐसा नामनिर्देशन अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य या किसी सदस्यों के पक्ष में करेगा।

परन्तु यह भी कि अभिदाता द्वारा किसी अन्य भविष्य निधि की धावत किया गया कोई नामनिर्देशन जिसमें वह निधि में सम्मिलित होने से पूर्व अभिदाता कर रहा था में उसके नाम में जमा रकम यदि ऐसी अन्य निधि में उसके ज्ञाने में अंतरित कर दी गई है तो तब तक इस नियम के अधीन किया गया विधिवत् नामनिर्देशन समझा जाएगा जब तक कि वह इस नियम के अनुसार नामनिर्देशन नहीं कर देता।

2. यदि अभिदाता उप नियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करता है तो वह नामांकन में वह रकम या अंश जो प्रत्येक नामनिर्देशिती को देय होगी इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अन्तर्गत निधि में उसके नाम किसी समय जमा सम्पूर्ण रकम आ जाए।

3. प्रत्येक नामनिर्देशन इन नियमों के साथ सलग्न अनुसूची-1 में घोषित प्राप्त होने में किया जाएगा।

4. अभिदाता किसी भी समय लेखा अधिकारी को लिखित सूचना भेजकर उस द्वारा किए गए नामनिर्देशन को रद्द कर सकता है। अभिदाता ऐसी सूचना के साथ या पृथक् स्पष्ट में इस नियम के उपबंधों के अनुसार नया नामनिर्देशन भेजेगा।

5. अभिदाता नामनिर्देशन में—

(क) यह अवधक हो सकता है कि यदि उसकी मृत्यु अभिदाता की मृत्यु से पूर्व हो जाए तो विनिर्दिष्ट नामनिर्देशिती की प्रश्न अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को जिन्हें नामनिर्देशन में निर्दिष्ट किया जाए अन्तरिक्ष हो जाएगा।

परन्तु यदि अभिदाता के कुटुम्ब का अस्त्र कोई सदस्य है तो ऐसे या ऐसे अन्य व्यक्ति उसके कुटुम्ब का ऐसा अन्य सदस्य या ऐसे अन्य सदस्य होने आहिए। परन्तु जहां अभिदाता इस खंड के अधीन एक में अधिक व्यक्तियों को ऐसा अधिकार प्रदान करता है वह ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक को देय रकम या अंश इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अन्तर्गत नामनिर्देशिती को देय सम्पूर्ण रकम आ जाए।

(ख) यह अवधक हो सकता है कि नामनिर्देशन उसमें विनिर्दिष्ट किसी आकस्मिकता के घटने की धूश में अविधिमान्य हो जाएगा।

परन्तु यदि नामनिर्देशन करते समय अभिदाता के कुटुम्ब में केवल एक सदस्य है तो वह नामनिर्देशन में यह अवधक होने के बावजूद अधिकार उसके कुटुम्ब में अन्य सदस्यों के आ जाने पर अविधिमान्य हो जाएगा।

(ग) ऐसे नामनिर्देशिती की मृत्यु हो जाने के तुरंत पश्चात जिसके संबंध में नामनिर्देशन में उपनियम (5) के खंड (क) के अधीन कोई विशेष अवधक होने नहीं की गई है या कोई ऐसी घटना घट जाने पर जिसके कारण नामनिर्देशन उपनियम (5) के खंड (घ) या उसके परन्तुके के अनुभग में अविधिमान्य हो जाता अभिदाता नामनिर्देशनों को रद्द करते हुए लेखा अधिकारी को लिखित सूचना देगा और उसके साथ इस नियम के उपबंधों के अनुसार एक नया नामनिर्देशन भेजेगा।

(ज) अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन और अभिदाता द्वारा किए गए रद्दकरण की प्रत्येक सूचना वहां तक जहां तक कि वह विधिमान्य है उस तारीख से प्रभावी होगी जिसके लिए नामनिर्देशन भूतान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत सचिव या उस निधि के अन्य प्रणाली के न्याय के माध्यम में किया जा सकता है।

8. अभिदाता का लेखा

निम्नलिखित दर्शने के लिए प्रत्येक अभिदाता के नाम में एक खाला खोला जाएगा :—

1. उसके अभिदाता

2. अभिदातों पर नियम 13 में यथा-उपर्युक्त व्याज,

3. निधि में अधिम लेना और रकम निकालना।

9. अभिदातों की शर्तें और दरें :

(1) अभिदाता उस अवधि के सिवाय जब यदि निलंबित हो, निधि में प्रतिमास अभिवान करेगा।

परन्तु कुछ अवधि तक निलंबित रहने के पश्चात् बहाल किए जाने पर अभिदाता को उक्त अवधि के लिए देय अभिदान की बकाया रकम की अदायगी एक मुश्त या किसी से में करने का विकल्प दिया जाएगा परन्तु यह राशि उस देय अभिदान की बकाया रकम की अधिकतम राशि से ऊपर नहीं होगी।

परन्तु यह और कि अभिदाता को अपने विकल्पानुसार ऐसी छूटी के दौरान अभिदान न करने की छूट होगी जिसके लिए छूटी बेतन न हो या जिसका छूटी बेतन आधे बेतन या आधे औसत बेतन से कम हो।

टिप्पणी-1

किसी स्थापना में मौसमी पद के पदधारी द्वारा नियोजन की अवधि के दौरान अभिदान किया जाना आवश्यक नहीं है।

टिप्पणी-2

अभिदाता को छूट दिवस के रूप में समझी जाने वली अवधि के दौरान अभिदान करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) अभिदाता उप नियम (1) के द्वितीय परन्तुक में निर्दिष्ट छूटी के दौरान अभिदान न करने के विकल्प की सूचना निम्नलिखित रीति से देगा।

(क) यदि वह ऐसा अधिकारी है जो अपना बेतन बिल स्वयं बनाता है तो छूटी पर जाने के पश्चात् अपने प्रथम बेतन बिल में अभिदान के कारण कटौती न करके;

(ख) यदि वह ऐसा अधिकारी है जो अपना बेतन बिल स्वयं नहीं बनाता तो छूटी पर जाने से पहले अपने कार्यालय के प्रधान को लिखित सूचना विधिवत् और समय पर नहीं दी जाएगी तो यह समझा जाएगा कि अभिदान करने का विकल्प दिया है।

टिप्पणी:-

इस उप नियम के अन्तर्गत सूचित किया गया अभिदाता का विकल्प अंतिम होगा।

(3) ऐसा अभिदाता जिसने निधि में अपने नाम जमा रकम को नियम-33 के अधीन निकाल लिया है ऐसी रकम निकालने के पश्चात् तब तक निधि में अभिदान नहीं करेगा जब तक कि वह इयूटी से वापस नहीं आ जाता।

4. उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी उस मास के लिए जिसमें वह सेवा छोड़ता है निधि में अभिदान तब तक नहीं करेगा जब तक वह उक्त मास के आरंभ से पूर्व कार्यालय के प्रधान को उक्त मास के लिए अभिदान करने के अपने विकल्प की लिखित सूचना नहीं देता।

10. अभिदान की दरें:-

(1) निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अभिदान की दर अभिदाता द्वारा स्वयं नियत की जाएगी, अर्थात्

(क) यह पूर्ण रूपयों में की जाएगी।

(ख) इस प्रकार दी गई दर कोई भी ऐसी राशि हो सकती है जो उसकी परिलिखियों के 6 प्रतिशत में कम न हो और उसकी कुल परिलिखियों से अधिक न शो।

परन्तु ऐसे अभिदाता के मामले में जो कर्मचारी राज्य बीमा नियम अंशदायी भविष्य निधि में 8-1/3 प्रतिशत की उच्च दर से अभिदान करता रहा है अभिदान की दर हम प्रकार से दी गई ऐसी राशि हो सकती है जो उसकी परिलिखियों के 8-1/3 प्रतिशत से कम न हो और उसकी कुल परिलिखियों से अधिक न हो।

(ग) जब कोई कर्मचारी यथा स्थिति, 6 प्रतिशत या 8-1/3 प्रतिशत की व्यूनतम दर में अभिदान करने का विकल्प देता है तब अभिदान को निकटतम पूर्ण रूपयों में पूर्णांकित किया जाएगा और ऐसा करते समय 50 पैसे तथा इससे अधिक को निकटतम पूर्ण रूपयों के स्तर से गिना जाएगा।

(2) उप नियम (1) के प्रयोग के लिए अभिदाता की परिलिखियां:—

(क) ऐसे अभिदाता के मामले में जो पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को सेवा में था वही उपलिखियां होंगी जिनका वह उस तारीख को हकदार था,

परन्तु:—

(1) यदि अभिदाता उक्त तारीख को अर्द्ध बेतन छूटी पर था और उसने ऐसी छूटी के दौरान अभिदान न करने का विकल्प दिया था अथवा उक्त तारीख को वह निलंबित था तो उसकी परिलिखियां वे परिलिखियां होंगी जिनका वह इयूटी पर लौटने के बाद वह उस तारीख को हकदार था;

(2) यदि अभिदाता उक्त तारीख को, भारत के बाहर प्रतिनियुक्त पर था अथवा उक्त तारीख को अर्द्ध बेतन छूटी पर था और छूटी पर रहता है तो उसने ऐसी छूटी के दौरान अभिदान करने का विकल्प दिया है तो उसकी परिलिखियां वे परिलिखियां होंगी जिनका वह निधि में सम्मिलित होने की तारीख को हकदार था;

(ख) ऐसे अभिदाता के मामले में जो पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को सेवा में नहीं था उसकी परिलिखियां वे होंगी जिनका वह निधि में सम्मिलित होने की तारीख को हकदार था।

(3) अभिदाता प्रत्येक वर्ष अपने भासिक अभिदान की रकम नियत करने की सूचना निम्नलिखित रीति से देगा, अर्थात्:—

(क) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को इयूटी पर था तो ऐसी कटौती द्वारा जो वह उस मास के अपने बेतन बिल से इस नियत मा ऐसा करने के लिए करता है;

(क) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी पर था और उसने ऐसी अर्द्ध वेतन छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का विकल्प दिया था या ऐसी तारीख को वह निलंबित था तो ऐसी कटौती द्वारा जो वह इयूटी पर वापस आने के बाद अपने प्रथम वेतन बिल में से इस निमित्त करता है ;

(ग) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी पर था और अर्द्ध वेतन छुट्टी पर चलता रहता है और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान करने का विकल्प दिया है तो ऐसी कटौती द्वारा जो उस मास के लिए अपने वेतन बिल से इस निमित्त करवाना पड़ता है या करवाता है ;

(घ) यदि उसने वर्ष के दौरान प्रथम बार लेवा में प्रवेश किया है तो ऐसी कटौती द्वारा जो वह उस मास के वेतन बिल से जिस मास से वह निधि में सम्मिलित हुआ है, इस निमित्त करवाना पड़ता है या करता है ।

(4) इस प्रकार नियत की गई अभिदान की रकम ।—

(क) वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार घटाई जा सकती है ;

(ख) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाई जा सकती है ;

(ग) यथापूर्वोक्त घटाई या बढ़ाई जा सकती है ।

परन्तु यदि अभिदान की रकम उस प्रकार घटाई जाती है तो वह उप नियम (1) में विहित न्यूनतम से कम नहीं होगी ।

परन्तु यह और यदि अभिदान किसी केन्द्रपाल मास के किसी भाग में वेतन बिना छुट्टी या अर्द्धवेतन या अर्द्धवेतन छुट्टी पर है और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का विकल्प दिया है तो अभिदान को देय रकम काम करने के बिना की संस्था जिसमें उस पर निर्दिष्ट छुट्टियों से भिन्न छुट्टी यदि कोई है, सम्मिलित है, के अनुपात में होगी ।

11. सरकारी या किसी अन्य संगठन या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति के अधीन किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ।

यदि अभिदान का स्थानांतरण कर दिया जाता है या उसे भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो वह उसी रीति से निधि के नियमों के अधीन रहेगा मानो उसका स्थानांतरण न हुआ हो या उसे प्रतिनियुक्ति पर न भेजा गया हो ।

12. अभिदानों की वसूली

(1) यदि परिलिखियाँ निधि में ली जाती हैं तो अभिदान की वसूली तथा निधि में से किसी प्रकार की अप्रिम के मूल तथा व्याज की वसूली परिलिखियों में से ही जाएगी ।

(2) यदि परिलिखियाँ किसी अन्य स्वीकृत से ली जाती हैं तो अभिदान अपनी देय रकम प्रतिमास लेवा अधिकारी को भेजेगा ।

परन्तु सरकार के स्वामिकार्धीन या उसके नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय में प्रतिनियुक्त अभिदान के मासमें अभिदानों की वसूली ऐसे निकाय द्वारा की जाएगी और वह लेवा अधिकारी को भेजी जाएगी ।

(3) यदि कोई अभिदान उस नारीक में जिसको निधि में सम्मिलित होते की उससे अपेक्षा भी गई है, अभिदान नहीं करता या किसी वर्ष के दौरान किसी मास अथवा कई मासों में नियम-9 में उपबन्धित में भिन्न स्थिति में अभिदान करने में चुकना है तो अगिदान की बकाया मद्देन निधि में देय कुल रकम नियम-13 में उपबन्धित दर से व्याज सहित अभिदान अविस्तर निधि में अदा की जाएगी या चूकने पर लेवा अधिकारी उस रकम को अभिदान की परिलिखियों में में किसी में अथवा अन्यथा जैसाकि वह प्राधिकारी, जो ऐसी अप्रिम की मंजूरी देने के लिए सक्षम है, जिसकी मंजूरी के लिए नियम-14 के उपनियम (2) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित है, निर्देश करे, कटौती करके वसूली करने के आदेश देंगा ।

परन्तु उन अभिदानों में, जिनकी निधि में जमा गणियों पर कोई व्याज नहीं दिया जाता है, कोई व्याज अदा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

13. व्याज

(1) उपनियम (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निगम अभिदान के खाते में व्याज ऐसी दर से जमा करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए समान्य भविष्य निधि के संबंध में प्रनेपक वर्ष के लिए निर्धारित की जाए ।

परन्तु यदि किसी वर्ष के लिए अवधारित व्याज की दर चार प्रतिशत से कम है तो जिस वर्ष के लिए व्याज की दर प्रथम बार चार प्रतिशत से कम नियत की गई है, उस वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में निधि के सभी अभिदानों को चार प्रतिशत की दर से व्याज दिया जाएगा ।

परन्तु यह और कि उस अभिदान को भी, जो पहले केन्द्रीय सरकार की किसी अन्य भविष्य निधि में अभिदान कर रहा था और जिसके अभिदान उन पर व्याज सहित नियम-26 के अधीन इस निधि में उसके लेवों में अन्तर्गत कर दिए गए हैं, चार प्रतिशत की दर से व्याज दिया जाएगा । यदि वह इस नियम के प्रथम परन्तुक के समान किसी उपबन्ध के अधीन ऐसी अन्य निधि के नियमों के अन्तर्गत उस दर पर व्याज प्राप्त कर रहा था ।

(2) व्याज प्रत्येक वर्ष के अन्तिम दिन में निम्नलिखित रीति से जमा किया जाएगा :—

(1) पूर्ववर्ती वर्ष के अस्तिम दिस अभिदाता के जमा खाते रकम पर, उसमें चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि को घटाकर बाक़ह मास के लिए ब्याज ;

(2) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि पर चालू वर्ष के आरंभ से रकम निकालने के मास के पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन तक के लिए ब्याज ;

(3) पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम दिन के बाद अभिदाता के लेखे में जमा की गई सभी राशियों पर जमा करने की तारीख से चालू वर्ष के अन्त तक के लिए ब्याज ;

(4) ब्याज की कुल रकम निकटतम रुपये में पूर्णांकित की जाएगी (पचास पैसे और इससे अधिक को अलग एक रुपया गिना जाएगा) ।

परन्तु जब किसी अभिदाता के खाते में जमा रकम देय हो जाती है तो इस नियम के अधीन ब्याज, यथास्थिति केवल चालू वर्ष के आरंभ से या जमा करने की तारीख से उस तारीख तक जिसको अभिदाता के लेखे में जमा रकम देय हो जाए, जमा किया जाएगा ।

(3) इस नियम में परिलिखियों में से वसूली के मामले में जमा की तारीख उस मास का प्रथम दिन समझी जाएगी जिसमें उसकी वसूली की जाती है और अभिदाता द्वारा भेजी जाने वाली रकम के मामले में उस मास का प्रथम दिन समझी जाएगी जिसमें अभिदान प्राप्त किया गया है, यदि वह उस मास के पांचवें दिन के पूर्व लेखा अधिकारी को प्राप्त हो जाता है, किन्तु यदि वह मास के पांचवें दिन या उसके पश्चात् प्राप्त होता है तो ठीक अगले मास का प्रथम दिन समझी जाएगी ।

परन्तु जहाँ अभिदाता के बेतन या छुट्टी बेतन और भत्ते लेने में विलम्ब हुआ है और परिणामस्वरूप निधि के संबंध में उसके अभिदान की वसूली में भी विलम्ब हुआ है वहाँ ऐसे अभिदान पर ब्याज उस मास से देय होगा जिसमें अभिदाता का बेतन या छुट्टी बेतन नियमों के अधीन देय था भले ही वह वस्तुतः किसी भी मास में क्यों न लिया गया हो ।

परन्तु यह और कि नियम-12 के उपनियम (2) के परन्तुक के अनुमार भेजी गई रकम के मामले में, यदि वह मास के पन्द्रहवें दिन से पूर्व लेखा अधिकारी को प्राप्त हो जाती है तो जमा करने की तारीख मास का प्रथम दिन समझी जाएगी ।

परन्तु यह भी कि जहाँ मास की परिलिखियाँ उसी मास के अन्तिम कार्यदिवस को ली और संवितरित की जाती हैं, वहाँ अभिदाता के अभिदान की वसूली के मामले में जमा की तारीख आगामी मास का प्रथम दिन समझी जाएगी ।

(4) नियम-20, 21 या 22 के अधीन संदर्भ के जाने वाली किसी रकम के अतिरिक्त उस पर ब्याज उग मास के जिसमें संदर्भ किए जाए, पूर्ववर्ती मास के अन्त तक या जिस मास में रकम देय हुई हो उसके पश्चात् छठे मास

के अन्त तक, इन दोनों अवधियों में से भी कम हो, उस व्यक्ति को देय होगी जिसे ऐसी रकम अदा की जाती है ;

परन्तु जहाँ लेखा अधिकारी ने उस व्यक्ति (या उसके अभिनवता) को कोई ऐसी तारीख सूचित कर दी है जिस तारीख को वह नक्क अदायगी करने के लिए तैयार है अथवा अदायगी के लिए उस व्यक्ति को चैक ब्रेज दिया है तो यथास्थिति ब्याज इस प्रकार सूचित तारीख या चैक भेजने की तारीख के पूर्ववर्ती मास के अन्त तक ही देय होगा ।

परन्तु यह और कि जहाँ अभिदाता सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय या सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वायत्त संगठन में प्रतिनियुक्त को किसी पूर्व प्रभावी तारीख से ऐसे निगमित निकाय या संगठन में आमेलित कर लिया जाता है तो अभिदाता की निधि में संचरों पर देय ब्याज की गणना के प्रयोजनों के लिए आमेलन की बाबत आदेश जारी किए जाने की तारीख वह तारीख समझी जाएगी जिसको अभिदाता के नाम जमा रकम देय हो गई हो, बशर्ते कि आमेलन की तारीख से आरंभ होने वाली और आमेलन के आदेश जारी किए जाने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान अभिदान के रूप में वसूल की गई रकम इस उप नियम के अधीन केवल ब्याज दिए जाने के प्रयोजन के लिए निधि में अभिदान समझी जाएगी ।

(5) यदि अभिदाता लेखा अधिकारी को सूचित कर देता है कि वह ब्याज नहीं लेना चाहता तो उसके खाते में ब्याज जमा नहीं किया जाएगा किन्तु यदि वह बाद में ब्याज मांगता है तो उस वर्ष के प्रथम दिन से जिसमें वह ब्याज की मांग करता है ब्याज उसके खाते में जमा किया जाएगा ।

(6) ऐसी रकमों पर जो नियम 12 के उपनियम (3), नियम 20 या नियम 21 के अधीन निधि में अभिदाता के जमा खाते में प्रतिस्थापित की जाती है, ब्याज की गणना ऐसी दरों से की जाएगी जो नियम के उप नियम (3) के अधीन उत्तरोत्तर विहित की जाए और जहाँ तक हो सके ऐसी रीति से जो इस नियम में विहित है ।

(7) यदि यह पाया जाता है कि अभिदाता ने निकासी की तारीख को अपने खाते में जमा राशि से अधिक राशि निधि से निकाली है तो अधिक निकाली गई राशि, इस बात का ध्यान किए बिना कि अधिक निकाली गई राशि अग्रिम है या निकासी है या निधि से अस्तिम संदाय है, ब्याज सहित उसके द्वारा इसकी एकमुश्त अदायगी की जाएगी या राशि लौटाने में असफल होने पर अभिदान की परिलिखियों से एकमुश्त कटौती करके वसूल करने का आदेश जारी किया जाएगा । यदि वसूल की जाने वाली राशि अभिदाता की कुल भासिक परिलिखियों के आधे में अधिक हो भी वसूली, ब्याज भीतर सम्पूर्ण राशि वसूली होने तक की उसकी परिलिखियों के अद्वायी की भासिक रिक्षणों में की जाएगी । इस उपनियम के लिए अधिक निकाली गई राशि पर ली जाने वाली ब्याज की दर उपनियम (1) के अधीन अनिवार्य

“प्रिया शिखि ॥” भास्मांग वर के $2\frac{1}{2}\%$ प्रतिशत होगी । अधिक निकाली गई राशि पर बसूल किया गया व्याज “0.49—व्याज प्राप्तियां निगम की अन्य व्याज प्राप्तियां, अन्य प्राप्तियां जीर्ण के अन्तर्गत, भविष्य निधि से निकाली गई राशि पर व्याज उम शीर्ष के अधीन निगम के खाने में जमा किया जाएगा ।

14. निधि से अग्रिम :—

(1) महानिदेशक या इस संबंध में उन द्वारा प्राप्तिकृत कोई अन्य अधिकारी किसी अभिदाता को निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिए ऐसी राशि के अग्रिम की अदायगी की अनुसूची-2 में यथा-विनिर्दिष्ट विहित रूप में मंजूरी दे सकता है जो पूर्ण रूपयों में होगी और अभिदाता के तीन मास के बेतन की रकम से या निधि में उसके नाम जमा रकम के आधे से, दोनों में से जो भी कम हो अधिक नहीं होगी अर्थात् :—

(क) अभिदाता उसके कुटुम्ब के सदस्यों या उम पर वस्तुः आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी, प्रसवास्था या निःशक्तता की बाबत व्यय का जिसमें जहाँ आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी शामिल है अदायगी के लिए;

(ख) अभिदाता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों का उम पर वस्तुः आश्रित किसी व्यक्ति की उच्चतर शिक्षा के खर्च की बाबत जिसमें जहाँ आवश्यक हो यात्रा व्यय भी शामिल है निम्नलिखित दशाओं में पूरा करने के लिए अर्थात् :—

(1) भारत में बाहर स्थाई स्कूल स्तर से ऊपर किसी शैक्षिक तकनीकी वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए; और

(2) भारत में हाई स्कूल स्तर के ऊपर के किसी विकिस्तीय इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए परन्तु यह तब जबकि पाठ्यक्रम तीन वर्ष की कानूनावधि से कम न हो ।

(ग) अभिदाता की हैसियत के अनुसार समुचित स्तर के किसी अनिवार्य व्यय के संदाय के लिए जो व्यय अभिदाता की रुकुनित प्रथा के कारण उसके सार्वाई या विवाह अन्येन्ट या अन्य संस्कारों के संबंध में व्यय करना पड़े ।

(घ) अभिदाता उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या उम पर वस्तुः आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों के खर्च बहन के लिए इस मामले में अग्रिम किसी अन्य सरकारी स्त्रोत से इसी प्रयोजन के लिए ग्राह्य किसी अन्य अग्रिम के अतिरिक्त उपलब्ध होगा ।

(ङ) जहाँ अभिदाता अपने विरुद्ध किसी अभिकथित शासकीय कदाचार की बाबत जांच में अपनी प्रतिरक्षा के लिए किसी विधि व्यवसायी को नियुक्त करता है वहाँ उसकी प्रतिरक्षा का व्यय बहन करने के लिए ।

(च) अपने निवास के लिए भूखंड या गृह या फ्लैट के निर्माण की लागत बहन करने के लिए या विल्सो विकास प्राधिकरण या किसी राज्य आवास बोर्ड अथवा किसी गृह

नियांग महाराष्ट्री लोअरहाई इलाय या फ्लैट के प्राप्तिकृत कोई अदायगी करने के लिए ।

(2) महानिदेशक विशेष परिस्थितियों में किसी अभिदाता को अग्रिम की अदायगी की मंजूरी दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाए कि संबंधित अभिदाता को उपनियम (1) में उल्लिखित कारणों में भिन्न कारणों से अग्रिम की आवश्यकता है ।

(3) किसी अभिदाता को उपनियम (1) में अभिकथित सीमा से अधिक अग्रिम या जब तक कि किसी पूर्ववर्ती अग्रिम की अन्तिम किश्त की अदायगी नहीं कर दी जाती है तब तक कोई अग्रिम विशेष कारणों से ही जो लेखबद्ध किए जाएंगे मंजूर किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

(4) जब उपनियम (3) के अधीन कोई अग्रिम किसी पूर्ववर्ती अग्रिम की अन्तिम किश्त वी अदायगी होने से पहले मंजूर कर दिया जाता है तो किसी पूर्ववर्ती अग्रिम के बसूल न किए गए अतिशेषों की इस प्रकार मंजूर किए गए अग्रिम में जोड़ दिया जाएगा और वसूली के लिए किश्तें ऐसी समेवित रकम के मंदर्भ में निश्चित की जाएंगी ।

(5) अग्रिम मंजूर करने के पश्चात् रकम ऐसे मामलों में जिसमें ग्रन्ति संदाय के लिए आवेदन नियम-25 के उपनियम (3) के खंड (2) के अधीन लेखा अधिकारी को भेजा गया हो, लेखा अधिकारी द्वारा प्राप्तिकृत किए जाने पर ही ली जाएंगी ।

टिप्पणी :—1

इस नियम के प्रयोजन के लिए बेतन में जहाँ स्वीकार्य हो मंहगाई बेतन भी आता है ।

टिप्पणी :—2

अभिदाता को नियम-14 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन अग्रिम लेने की अनुमति प्रत्येक छह मास में एक बाद दी जाएगी ।

15. अग्रिम की अमूली :—

(1) अभिदाता से अग्रिम की वसूली उतनी समान मासिक किश्तों में की जाएगी जो मंजूरी प्राप्तिकारी निर्दिष्ट करे किन्तु किश्तों की संख्या 12 से कम तब तक नहीं होगी जब तक अभिदाता व्यवहार के दें और किसी भी वर्ष में 24 से अग्रिम नहीं होगी । विशेष मामलों में जहाँ अग्रिम की रकम, नियम 14 के उपनियम (2) के अधीन अभिदाता के तीन मास के बेतन से अधिक हो, वहाँ मंजूरी प्राप्तिकारी 24 से अधिक किश्तों तिथि कर सकता है किन्तु किसी भी वर्ष में 36 से अधिक किश्तों तिथि नहीं कर सकता है । अभिदाता अपनी इच्छानुसार किसी मास में एक में अधिक किश्तों का प्रतिमंदाय कर सकता है । प्रत्येक किश्त पूर्ण रूपयों में होनी चाहिए और ऐसी किश्तें नियन्त्रित करने के लिए अग्रिम की रकम को यदि आवश्यक हो बढ़ाया या घटाया जा सकता है ।

(2) वसूली नियम 12 में अधिग्राहने की वसूली के लिए विनिर्दिष्ट रीति से की जाएगी और जिस मास में अग्रिम दिया जाता है उसके ठीक बाद वाले मास के वेतन में आरंभ होगी। जब अभिदाता निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा है या किसी कैलेण्डर मास में दस या अधिक दिन के लिए ऐसी छुट्टी पर है जिसके लिए कोई छुट्टी वेतन नहीं मिलता अथवा अद्वेतन या अद्वं औसत वेतन के समतुल्य या उससे कम छुट्टी वेतन मिलता है तब उसकी सहमति के बिना वसूली नहीं की जाएगी। अभिदाता के लिखित निवेदन पर मंजूरी प्राधिकारी अभिदाता को मंजूर किए गए अग्रिम वेतन की वसूली के दौरान वसूलियाँ को स्थापित कर सकता है।

(3) यदि अभिदाता को अग्रिम मंजूर कर दिया गया है वह उसे ले जा चुका है तथा अग्रिम बाद में अदायगी पूरी होने से पूर्व नामंजूर कर दिया जाता है तो ली गई कुल रकम या उसका अतिशेष का अभिदाता द्वारा निधि में सुरक्षा भुगतान कर दिया जाएगा अथवा व्यतिक्रम की दशा में लेखा अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किए जाने पर अभिदाता की परिनिर्धियों में से लेखा अधिकारी के निर्देशानुसार एकमुक्त अथवा उसनी मासिक किश्तों में जो बाहर से अधिक न हो कठोरी करके वसूल करने का आदेश देगा।

परन्तु ऐसा अग्रिम नामंजूर करने से पहले अभिदाता को पत्र की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर लिखित में मंजूरी प्राधिकारी को यह स्पष्ट करने का उपयुक्त अवसर दिया जाएगा कि अदायगी नागृ क्यों न की जाए और यदि स्पष्टीकरण अभिदाता द्वारा पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर भेज दिया जाता है तो इसे निर्णय के लिए महानिवेशक को भेजा जाएगा और यदि स्पष्टीकरण अभिदाता द्वारा पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर स्पष्टीकरण नहीं भेजा है तो अग्रिम की वसूली उप नियम में विहित रीति से लागू की जाएगी।

(4) इस नियम के अधीन की गई वसूलियाँ अभिदाता के खाने में जमा कर दी जाएंगी।

16. अग्रिम का मदोष उपयोग :

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी यदि मंजूरी प्राधिकारी के लिए यह संदेह करने का कारण हो कि नियम 14 के अधीन निधि में गे अग्रिम के रूप में लिए गए धन का उपयोग उस प्रयोजन से विश्व प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए ऐसे धन का लिया जाना मंजूर किया गया था तो वह अभिदाता को अपने संदेह का कारण सूचित करेगा और उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि ऐसी सूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर लिखित में यह स्पष्ट करें कि क्या अग्रिम का प्रयोग उमी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए धन का लिया जाना मंजूर किया गया था। यदि पन्द्रह दिन की उस अवधि के भीतर अभिदाता द्वारा भेजे गए स्पष्टीकरण में मंजूरी प्राधिकारी का समाधान नहीं होता है तो मंजूरी प्राधिकारी [अभिदाता को संबंधित रकम निधि में सत्काल अदा करने के लिए निश्चय देगा या व्यनिक्रम की दशा में अभिदाता की परिनिर्धियाँ में से चाहे

वह छुट्टी पर ही क्यों भ हो, उसकी एक मुश्त कठोरी करने का आदेश दिया जाएगा। परन्तु अदायगी की कुल रकम अभिदाता की परिलिंग्धियों के आधे से अधिक है तो वसूलियाँ उसकी परिलिंग्धियों के अद्वीतीय की मासिक किश्तों में तब तक की जाएगी जब तक कि उसके द्वारा मम्पुर्ण रकम की अदायगी नहीं कर दी जाती है।

टिप्पणी—इस नियम में परिलिंग्धियाँ शास्त्र में निर्वाह अनुदान सम्मिलित नहीं हैं।

17. निधि से आहरण:

(1) इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उन प्राधिकारियों द्वारा जो नियम 14 के उप नियम (2) के अधीन किसी भी समय विशेष कारणों के लिये नियमानुसार अग्रिम मंजूर करने में सक्षम है, अनुसूची-2 में यथा-विनिर्दिष्ट विहित रूप में अभिदाता को रकम निकालने की मंजूरी दी जा सकती है। अभिदाता की 20 वर्ष की सेवा (जिसमें खंडित मेवाकाल भी, यदि कोई हो, सम्मिलित है) पूरी होने के पश्चात् यह अधिवर्धिता पर उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व 10 वर्ष के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, निधि में उसके नाम जमा रकम में से अभिदाता को नियमानुसारित प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिये आहरण की अनुमति दी जा सकती है, अर्थात्—

(क) अभिदाता या अभिदाता की किसी मन्तान की उच्चतम गिराव का खर्च, जिसमें जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी सम्मिलित है, नियमानुसारित मामलों में बहन करने के लिये अर्थात्—

(i) भारत में बाहर हाई स्कूल से ऊपर शैक्षिक, तकनीकी, बूलिका या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए, और

(ii) भारत में हाई स्कूल स्तर से ऊपर विकिसीय इंजीनियरी या अन्य तकनीकी अवश्य विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये।

(ख) अभिदाता या उसके पुत्र या पुत्रियों और उस पर वस्तुतः आश्रित किसी अन्य स्त्री नातेदार की सगाई/विवाह में संबंधित व्यय बहन करने के लिये;

(ग) अभिदाता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी के संबंध में व्यय, जिसमें जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी सम्मिलित है, बहन करने के लिये;

(2) अभिदाता की 10 वर्ष की सेवा (जिसमें खंडित सेवाकाल भी, यदि कोई हो, सम्मिलित है) पूरी होने के पश्चात् या अधिवर्धिता की तारीख से पूर्व 10 वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके नाम जमा रकम में से अभिदाता को नियमानुसारित प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिये आहरण की अनुमति दी जा सकती है, अर्थात्—

- (i) अपने निवास के लिये उपयुक्त गृह का निर्माण करना या उसे अंजित करना या निर्मित फ्लैट अंजित करना जिसमें स्थल की तागा भी समिक्षित हो;
- (ii) अपने निवास के लिये उपयुक्त गृह निर्माण या उसे अंजित करने जथा निर्मित फ्लैट अंजित करने के लिये अपट चूर्पे में लिये गए उदाहरण के बायाँ बकाया रकम भी प्रदायनी करना;
- (iii) किसी गृहस्थल का अपने निवास के लिये इस पर गृह निर्माण के लिये खरीद करना या इस प्रयोजन के लिये माट रूप से लिये गये उधार के बायाँ बकाया रकम की अदायगी करना;
- (iv) पहले से ही अभिदाता के स्वामिन्वाधीन या उसके द्वारा अंजित गृह अथवा फ्लैट का पुनर्निर्माण करना या उसमें बृद्धि अथवा परिवर्तन करना;
- (v) इयूटी के स्थान में भिन्न स्थान पर पैनुक गृह या इयूटी के स्थान से भिन्न स्थान पर सरकार में लिये गए शृण की सहायता में निर्मित गृह का नवीकरण, उसमें बृद्धि या परिवर्तन करना या उसे ठीक-ठाक रखना;
- (vi) खण्ड (iii) के अधीन खरीदे गए स्थल पर गृह का निर्माण करना;
- (vii) अभिदाता की सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व छह मास के भीतर निधि में उसके नाम जमा रकम में क्रूप्य या कारबाहर परिसर या दोनों को अंजित करने के प्रयोजन के लिये दी जा सकती है;
- (viii) विस्तीर्ण वर्ष के दौरान एक वर्ष के अभिदाता के बराबर गणि पाक बार अभिदाता द्वारा स्वयं बिन पोषित नथा अंगदायी अथवा पर निगम कर्मचारी समूह बीमा योजना के लिये संदर्भ की जायेगी।

टिप्पणी :—

वह अभिदाता जिसने गृह निर्माण के प्रयोजनों के अंगम मंजूर करने के लिए गहरी विकास मंसालय की योजना के अधीन अधिकार का लाभ उठाया है या जिसे इस संबंध में किसी अन्य सरकारी स्वीकृत से सहायता दी गई है, उप नियम के उप-खंड (i), (iii), (iv), और (vi) के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये और उपयुक्त योजना के अधीन लिये गये शृण की अदायगी के प्रयोजनों के लिये भी, नियम 18 के उपनियम (1) के परन्तु में विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन रहते हुए अंतिम रूप से रकम निकालने के मंजूरी का हकदार होगा।

यदि किसी अभिदाता के पास अपने इयूटी के स्थान से भिन्न स्थान पर पैनुक गृह है या उसने सरकार से लिये गए शृण की सहायता से गृह का निर्माण किया है तो वह अपने इयूटी के स्थान पर गृह स्थल खरीदने के लिये या दूसरे, गृह के निर्माण के लिये या निर्मित फ्लैट अंजित करने के लिये

उप नियम (2) के खंड (i), (iii), और (iv) के अधीन अंतिम रूप से रकम निकालने के मंजूरी के लिये हकदार होगा।

टिप्पणी 2:—उप नियम (2) के खंड (i), (iii), (iv) या (vi) के अधीन रकम का निकाला जाना अभिदाता द्वारा निर्मित किये जाने वाले गृह या की जाने वाली बृद्धि अथवा किये जाने वाले परिवर्तनों या उम्मेद के जहाँ स्थान या गृह स्थित है, स्थानीय नगरपालिका निकाय द्वारा अनुमोदित रेखांचित्र प्रस्तृत वर्द्धियों के पासात् वी मंजूर किया जायेगा जो उन्हीं सम्पत्तियों में मंजूर किया जायेगा जिनमें रेखांचित्र वाल्वर में अनुमोदित कराया जाता है।

टिप्पणी 3:—उप नियम (2) के खंड (ii) के अधीन मंजूर की गई आहरण की रकम, खंड (1) के अधीन पिछले आहरण को रकम सहित, उसमें में पिछले आहरण की रकम को घटाकर आवेदन की तारीख को ब्रकाया तीन चौथाई से अधिक नहीं होगी जिस मुक्त का पालन किया जाता है वह यह है—[उम नार्त्व का बकाया तथा भवित्वत गृह के लिये पिछले आहरण (आहरणों) की रकम से तीन चौथाई से पिछले आहरण (आहरणों) की रकम को घटा दे]।

टिप्पणी 4:—उप नियम (2) के खंड (i) या (iv) के अधीन रकम निकालने की अनुमति वहाँ भी दी जायेगी जहाँ गृह स्थल या गृह पत्ती या पति के नाम पर है परन्तु यह तब जबकि वह अभिदाता द्वारा किये गये नाम निर्देशन में भविष्य निधि में भन प्राप्त करने के लिये प्रथम नाम निर्वैशिती हो।

टिप्पणी 5:—इस नियम के अधीन एक प्रयोजन के लिये केवल एक बार रकम निकालने की अनुमति दी जायेगी किन्तु विभिन्न संतान के विवाह या शिक्षा अथवा विभिन्न अवसरों पर बोमारियों या उस क्षेत्र के, जहाँ गृह या फ्लैट स्थित है, स्थानीय नगर पालिका निकाय द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित नये रेखांचित्र के अन्तर्गत आने वाले गृह या फ्लैट में अतिरिक्त बृद्धि या परिवर्तन को एक ही प्रयोजन नहीं समझा जायेगा। किसी गृह को पूरा करने के लिये उप नियम (2) के खंड (i) या (vi) के अधीन दूसरा या उसके बाद रकम निकालने की अनुमति टिप्पण 3 के अधीन निर्धारित भीमा तक दी जायेगी।

टिप्पणी 6:—यदि उसी प्रयोजन के लिये और उसी समय पर नियम 14 के अधीन अप्रियम मंजूर किया जा रहा है तो इस नियम के अधीन रकम निकालने की मंजूरी नहीं दी जायेगी।

(3) रकम निकालने की गंजूरी देने के पश्चात् ऐसे मामलों में, जिनमें अंतिम भुगतान के लिये आवेदन नियम 25 के उप नियम (3) के खंड (ii) के अधीन लेखा अधिकारी को भेजा गया था, रकम लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकार दिये जाने पर ली जायेगी।

18. रकम निकालने की शर्तेः

- (1) अभिदाता द्वारा निधि में अपने द्वासे में जम रकम से नियम 17 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक

प्रयोजनों के लिये, एक समय पर निकाली गई कोई राशि सामान्यतया ऐसी रकम के आधे या छह मास के बेतन, दोनों में से जो कम हो, अधिक नहीं होगी। परन्तु मंजूरी प्राप्तिकारी इस सीमा से अधिक रकम का निकालना, जो निधि में उसके खाते में जगा अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है, (1) उस उद्देश्य को, जिसके लिये रकम निकाली जा रही है, (2) अभिदाता को हैरिंगत को और (3) निधि में उसके खाते में जगा रकम को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए मंजूर कर सकता है।

परन्तु नियम 17 के (घ) के उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये निकाली जाने वाली अधिकतम रकम गृह निर्माण प्रयोजनों के लिए अग्रिम मंजूर करने के लिये शहरी विकास मंत्रालय की योजना के नियम 2(क) और 3(ब्र) के अधीन ममता-समय पर विहित अधिकतम सीमा से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह और कि किसी अभिदाता के मामलों में जिसने गृह निर्माण प्रयोजनों की बाबत अग्रिम के अनुदान के लिये शहरी विकास मंत्रालय की योजना के अधीन कोई अग्रिम लिया है या किसी जिसे अन्य सरकारी स्वातंत्र से इस बारे में कोई सहायता दी गई है, इस उपनियम के अधीन निकाली गई राशि और उपर्युक्त योजना के अधीन दिये गये अग्रिम या किसी अन्य सरकारी स्वातंत्र से दी गई सहायता की राशि मिलकर उपर्युक्त योजना के नियम 2(क) और 3(ब्र) के अधीन समय-समय पर विहित को गई अधिकतम राशि में अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 1:—नियम 17 के उप नियम (2) के खंड (1) के अधीन अभिदाता को मंजूर की गई आहरण की राशि किसी में निकाली जा सकती है और किसी की अन्या मंजूरी की तारीख में बारह महीने के कैलेंडर की अवधि में आर से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2:—उन मामलों में जिनमें अभिदाता को खरीदै गए स्थल या गृह अथवा फ्लैट या विल्ली विकास प्राप्तिकरण या किसी राज्य आवास बोई अथवा गृह निर्माण गहकारी सोसाइटी के माम्रम से निर्मित मकान या फ्लैट के लिये भुगतान किसी में करना है, उसे तब-तब रकम निकालने की अनुमति दी जायेगी जब जब उसमें ऐसी किसी का भुगतान करने के लिये कठा जायेगा। ऐसा प्रत्येक भुगतान नियम 16 के लिये पृथक प्रयोजन के लिये भुगतान माना जायेगा।

(2) यह अभिदाता जिसे नियम 17 के अधीन निधि में से धन निकालने की अनुमति दी गई है, मंजूरी प्राप्तिकारी का ऐसे यशोचित समय के भीतर जो ऐसे प्राप्तिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, यह समाधान करेगा कि धन का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए निकाला गया था और यदि वह ऐसा करने में चूक जाता है तो इस प्रकार निकाली गई कुल राशि अथवा उसके जतने भाग को जो उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह निकाला गया था,

उपयोग में जहाँ लाया गया है, अभिदाता द्वारा तुरन्त निधि में एकमुश्ति सोटाया जाएगा और ऐसा भुगतान करने में चूक होने की स्थिति में मंजूरी प्राप्तिकारी उस रकम को उसकी परिलक्षित रूप से ध्यान में रखते हुए भुगतान करने का आदेश देगा।

परन्तु इस नियम के अधीन आहरण को धन वापसी लागू करने से पहले अभिदाता को पत्र की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर लिखित में यह स्पष्ट करने का उपयक्ता अवभार दिया जाएगा कि अदायगी को लागू करने न किया जाए और यदि मंजूरी प्राप्तिकारी स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है अथवा अभिदाता द्वारा पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर स्पष्टीकरण नहीं भेजा जाता है तो मंजूरी प्राप्तिकारी इस उप नियम के अधीन विहित रीति से अदायगी करवाएगा।

(3) (क) वह अभिदाता जिसे नियम 17 के उप नियम (2) के खंड (1), खंड (i) और (iii) के अधीन निधि में अपने नाम जमा रकम निकालने की अनुमति दी गई है, इस प्रकार निकाले गए धन में निर्मित या अर्जित गृह या खर्चे गए गृह स्थल का कब्जा विक्रय बंधक (महानिदेशक के नाम में बंधक से भिन्न) दाना या विनियम द्वारा अन्यथा किसी स्थल में, महानिदेशक को पूर्व अनुमति के बिना नहीं देगा।

परन्तु ऐसी प्रत्युमति किसी ऐसी अवधि के लिए गृह या गृह स्थल को पट्टे पर देने के लिए

(1) जो तीन वर्ष से अधिक न हो, या

(2) उसे किसी आवास बोर्ड, गार्डीयर्कून वैक, जीवन बीमा निगम या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के पक्ष में जिसने नये गृह के निर्माण के लिए या विद्यमान गृह में वृद्धि या परिवर्तन के लिए कोई क्रृद्ध देता हो, बंधक रखने के लिए, आवश्यक नहीं होगी।

(ख) अभिदाता प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस आशय को एक धोपणा प्रस्तुत करेगा, कि, व्यास्त्यव्याप्ति, गृह या गृह स्थल उसके कब्जे में ही है प्रथमा वह पूर्वोक्त के अनुसार बंधक रख दिया गया है अथवा अन्याय अनारंभ पर दिया गया है या पट्टे पर देया गया है और यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो मंजूरी प्राप्तिकारी के समक्ष ऐसे प्राप्तिकारी द्वारा इस निर्मित विनिर्दिष्ट नारीब की या उससे पूर्व वह मूल विक्रा, बंधक या पट्टा विनेक तथा ऐसे अन्य राशिकों भी जिन पर सम्पत्ति पर उसका हूँ आधारित है, प्रस्तुत करेगा।

(ग) यदि अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व किसी गमय अभिदाता महानिदेशक की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना गृह या गृह स्थल का कब्जा त्याग देता है तो वह तुरन्त अपने द्वारा निकाली गई राशि का निधि में एकमुश्ति भुगतान करेगा और ऐसा भुगतान करने में चूक की स्थिति में मंजूरी प्राप्तिकारी, अभिदाता को इस विषय में अस्थानेदम करने का उपयुक्त अवभार देने के पश्चात् उक्त राशि की अभिदाता की परिलक्षित में न हो जा तो एकमुश्ति अथवा उसकी मासिक किसी में जो उसके द्वारा अवधारित की जाए, दसूल कराएगा।

टिप्पणी : उस अभिदाता भैं जिसने कर्मचारी राज्य वीमा नियम से ऋण लिया है और उसके बदले में गृह या गृह स्थल नियम को बंधक रख दिया है, निम्नलिखित आशय का एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी, अर्थात् :—

घोषणा

“मैं प्रमाणित करता हूँ कि जिस गृह या गृह स्थल के निर्माण के लिए या अर्जन के लिए मैंने भविष्य निधि से धन निकाला था वह भेरे कबजे में ही है किन्तु नियम के पास बंधक रख दिया गया है।”

19. अग्रिम का “आहरण” में परिवर्तन :

वह अभिदाता जिसने नियम 14 के अधीन उक्त नियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए अग्रिम लिया है अथवा भविष्य में ने मकान है, नियम 17 और 18 में निर्धारित शर्तों को पूरा कर देने पर स्वविवेकानुसार और मंजुरी प्राप्तिकारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को संबंधित लिखित निवेदन करके अग्रिम के बकाया अतिशेय को अनिम आहरण में परिवर्तित कर सकता है।

टिप्पण 1. : प्रशासनिक अधिकारी अराजपत्रित अभिदानाओं के मामले में कार्यालय के प्रधान से और राजपत्रित अभिदानाओं के मामले में संबंधित खजाना अधिकारी को वेतन विलों में से वसूलियां रोकने के लिए, तब कह सकता है जब ऐसे परिवर्तन के लिए आवेदन ऐसे प्राप्तिकारी द्वारा लेखा अधिकारी को भेज दिया जाता है प्रशासनिक प्राप्तिकारी अभिदाता को सूचना भेजने वाले पत्र की एक प्रति उस खजाना अधिकारी को भेजेगा जिससे वह अभिदाता अपना वेतन प्राप्त करता है ताकि आगे वसूलियां रोकने की अनुमति दी जा सके।

टिप्पण 2. : नियम 18 के उप नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, परिवर्तन के समय खाते में अभिदाता के नाम जमा रकम या अभिदान तथा उस पर ब्याज और अग्रिम की बकाया रकम को अनिशेष माना जाएगा। अत्येक रकम का निकालना पूर्ण रकम का निकालना माना जाएगा और एक से परिवर्तनों की स्थिति में वही सिद्धांत लागू होगा।

20. निधि में से संचयों का अन्तिम रूप में आहरण :

जब अभिदाता सेवा छोड़ दे तब निधि में उसके नाम जमा रकम उसे देय हो जाएगी :

परन्तु वह अभिदाता जिसे सेवा से पदब्ध्यत कर दिया गया है और बाद में सेवा में बहाल कर दिया गया है यदि महानिर्देशक गैरिकों की अपेक्षा करें तो वह इस नियम के अनुमरण में निधि में से उगे भुगतान की गई रकम का नियम 13 के उपबन्धित दर से ब्याज के माथ, नियम 21 के परन्तुक में विहित रीति से भुगतान करेगा। इग प्रकार भुगतान की गई रकम निधि में उसके खाते में जमा कर दी जाएगी। स्पष्टीकरण 1 :—संविदा पर नियुक्त किए गए अभिदाता से अथवा उस अभिदाता से, जो गोपा में नियुक्त हो गया है, जिस बाद में सेवा के व्यवधान के साथ या उसके बिना पुनः नियोजित

किया गया है, भिन्न अभिदाता के बारे में उस दशा में यह नहीं समझा जाएगा कि उसने सेवा छोड़ दी है। जब उसे सेवा में व्यवधान बिना राज्य सरकार के अधीन अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी दूसरे किसी दूसरे विभाग के अधीन (जिसमें वह किसी अन्य भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित होता है) किसी अन्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और उसका अपने पूर्व पद से कोई संबंध नहीं रह जाता। ऐसे मामले में उससे अभिदाय व्याज सहित :—

(क) यदि नया पद केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग में है तो अन्य निधि में उसे निधि के नियमों के अनुसार अंतरित कर दिए जाएंगे, या

(ख) यदि नया पद किसी राज्य सरकार के अधीन है और वह राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अभिदानों और व्याज के ऐसे अंतरण के लिए सहमति दे देती है तो संबंधित राज्य सरकार के अधीन नये लेखे में अंतरित कर दिए जाएंगे।

टिप्पणी :—स्थानांतरण के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में या राज्य सरकार के अधीन सेवा में व्यवधान के बिना और केन्द्रीय सरकार की समुचित आशा से कोई नियुक्ति ग्रहण करने के लिए उप त्याग के मामले आयेंगे। ऐसे मामलों में जिस सेवा में व्यवधान हो जाता है उसमें व्यवधान केवल भिन्न स्थानांतरण के लिए दी गई पदग्रहण अवधि तक सीमित होगा।

यही उपबंध ऐसे मामलों पर भी लागू होंगे जिनमें छठनी पष्ठात् तुरन्त उसी या भिन्न सरकार के अधीन नियोजन प्राप्त हो जाता है।

स्पष्टीकरण 2 :—संविदा पर नियुक्त किए गए अभिदाता से भिन्न अभिदाता, जो सेवा निवृत हो चुका है और जिसे बाद में, सेवा में व्यवधान के बिना, किसी ऐसे नियमित निकाय, जो सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन है अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वशासी संगठन में पुनः नियोजित अथवा स्थानांतरित किया जाता है, तो अभिदानों की रकम का उस पर ब्याज सहित उसे भुगतान नहीं किया जाएगा, अपितु वे उस निकाय की सहमति से उस निकाय के अधीन नये भविष्य निधि लेख में अंतरित कर दी जाएंगी।

स्थानांतरण के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्वाधीन या मियन्ट्रणाधीन किसी नियमित निकाय या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वशासी संगठन के अधीन सेवा में व्यवधान के बिना और केन्द्रीय सरकार की यथोचित अनुमति से पदग्रहण करने के लिए सेवा में पदब्ध्यत के मामले भी आते हैं। नये पद का भार ग्रहण करने में लगने वाले समय को, याद वह समय सरकारी कर्मचारी की एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण के लिए स्वीकार्य पद ग्रहण अवधि से अधिक नहीं है तो, सेवा में नहीं माना जाएगा।

परन्तु किसी लोक उद्यम के अधीन सेवा के लिए विकल्प देने वाले अभिदाता के अभिदाता की रकम और उस पर व्याज यदि अभिदाता ऐसा चाहता है और यदि संबंधित उद्यम में अंतरण के लिए सहमत हो जाता है तो, ऐसे उद्यम के अधीन उसके नये भविष्य निधि लेखे को अंतरित कर दिया जाएगा। लेकिन यदि अभिदाता ऐसे अंतरण की इच्छा नहीं करता है या संबंधित उद्यम की कोई भविष्य निधि नहीं है तो उपरोक्त रकम अभिदाता को बापस कर दी जाएगी।

21. अभिदाता की सेवानिवृत्ति :

जब

(क) अभिदाता सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है या यदि वह किसी अवकाश विभाग में नियोजित है तो जब वह अवकाश के साथ सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है, या

(ख) अभिदाता को छुट्टी पर रहने के दोगन सेवा निवृत्ति होने की अनुमति दी गई है यानि मध्यम विकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे और सेवा करने के अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तब नियि में उसके नाम जमा रकम, उसके द्वारा इस नियम लेखा अधिकारी को आवेदन किए जाने पर अभिदाता को संदेय हो जाएगी :

परन्तु यदि अभिदाता इन्हीं पर बापस आ जाता है तो महानिदेशक द्वारा ऐसी अपेक्षा करने पर इस नियम के अनुसरण में निधि से उसे भुगतान की गई रकम का उस पर नियम 13 में उपबंधित दर से व्याज के साथ नकद या प्रतिमूलियों के रूप में किए जाने में या अन्यथा उसकी परिलक्षियों में से यस्ती द्वारा उस अधिकारी के निदेशानुसार जो ऐसे अधिम की मंजूरी देने के लिए सक्षम हैं और जिसकी मंजूरी देने के लिए नियम 14 के उपनियम (2) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित है अपने खाते में जमा कर किए जाने के लिए निधि में भुगतान करेगा।

22. अभिदाता की मृत्यु होने पर प्रक्रिया :

निधि में 'अभिदाता' के नाम जमा रकम के देय हो जाने से पूर्व या जहां रकम देय हो गई है वहां भुगतान किए जाने के पूर्व अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर:

(1) जहां अभिदाता कुटुम्ब छोड़ जाता है:—

(क) यदि नियम 2 के उपबंधों के अनुसरण में व्यथवा इसके पूर्व तत्समान किसी नियम के अनुसार अभिदाता द्वारा किया गया नामनिर्देशन कुटुम्ब के किसी मध्यम या किन्हीं सदस्यों के पक्ष में है तो निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम या उसका वह भाग जिसने नामनिर्देशन संबंधित है अभिदाता के नामनिर्देशी या नामनिर्देशितों को नामनिर्देशन में विनिर्दित अनुपात में देय हो जाएगा।

में नामनिर्देशन किया गया है, अभिदाता के नामनिर्देशितों या नामनिर्देशितों के नाम निर्देशन में विनिर्दित अनुपात में देय हो जाएगा,

(ख) यदि अभिदाता के कुटुम्ब के किसी मध्यम या किन्हीं सदस्यों के पक्ष में ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं है व्यथवा याद ऐसा नामनिर्देशन निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम के केवल कुछ भाग के संबंध में है तो, वथा निधि, संपूर्ण रकम या उसका वह भाग जिसके संबंध में नामनिर्देशन नहीं है, इस बात के होते हुए भी कि अभिदाता के कुटुम्ब के किसी मध्यम या किन्हीं सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में कोई नामनिर्देशन नापर्याप्त है, उसके कुटुम्ब के सदस्यों के बीच ममान अंशों में से देय होगा।

परन्तु ऐसा कोई अंश

(1) उन पुत्रों को जो वयस्क हो चुके हैं;

(2) मृत पुत्र के उन पुत्रों को जो वयस्क हो चुके हैं;

(3) उन विवाहित पुत्रियों को जिनके पति जीवित हैं;

(4) मृत पुत्र की उन विवाहित पुत्रियों को जिनके पति जीवित हैं, देय नहीं होगा;

(ग) यदि खंड (1), (2), (3) और (4) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न कुटुम्ब का कोई सदस्य है।

परन्तु यह और कि मृत पुत्र की विधवा या विधवाओं और संतान को आपस में ममान भागों में केवल वह अंश प्राप्त होगा जो उस पुत्र को यदि वह अभिदाता का उत्तरजीवी होता तथा प्रथम परन्तुके खंड (1) के उपबंधों में छुट प्राप्त होती ना प्राप्त होता।

(2) यदि अभिदाता अपना कोई कुटुम्ब नहीं छोड़ता है, तब यदि नियम 1 के उपबंधों या इसमें पूर्व प्रवृत्त नहमान किसी नियम के उपबंधों के अनुसार अभिदाता द्वारा किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में किया गया कोई नामनिर्देशन अनिवार्य में है, तो निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम या उसका वह भाग जिसने नामनिर्देशन संबंधित है अभिदाता के नामनिर्देशी या नामनिर्देशितों को नामनिर्देशन में विनिर्दित अनुपात में देय हो जाएगा।

23. जमा राशि—भवद्वय वीमा योजना—

30 मितम्बर, 1991 को या उससे पूर्व अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर तथा जिम्पर नियम 24 लागू नहीं होता है अभिदाता के नाम जमा रकम प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति वा जेंडर अधिकारी ऐसे अभिदाता की मृत्यु से तीन तीन वर्ष पूर्व के बीच खाते में आमत अनिश्चय के ब्रावर अनिश्चित रकम इस गर्त के अधीन देगा कि—

(क) ऐसे अभिदाता के नाम जमा अनिश्चय उसकी मृत्यु के मास पूर्व तीन वर्ष के दौरान किसी भी समय निम्नलिखित में कम हो—

(1) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया जिसका परिणोधन पूर्व वेतनमान का अधिकतम वेतन 1300 या उसे अधिक है— 4000 रु.

(2) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसका परिणोधन पूर्व वेतनमान का अधिकतम वेतन 900 रुपये या उससे अधिक है किन्तु 1300 रुपये से कम है— 2500 रुपये

(3) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसका परिणोधन पूर्व वेतनमान का अधिकतम वेतन 291 रुपये या उससे अधिक है किन्तु 900 रुपये से कम है— 1500 रुपये।

(4) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसका परिणोधन पूर्व वेतनमान का वेतन 291 रुपये से कम है।— 1000 रुपये।

(ख) इस नियम के अधीन देव अनिश्चित रकम दस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो।

टिप्पणी:—1

आमत अनिश्चय की गणना उस मास से जिसमें मृत्यु हुई है पूर्व 36 मास में से प्रत्येक मास के अंत में अभिदाता के नाम जमा अनिश्चय के आधार पर की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए और ऊपर

विहित व्यक्तिमात्र अनिश्चय की जाच करने के लिए भी—

(क) मार्च के अंत के अनिश्चय में नियम 13 के नियंत्रणों के ग्रन्थालय जमा किया गया वार्षिक व्याज भी सम्मिलित होगा,

(ख) यदि उपर्युक्त 36 मासों में से अंतिम भाल मार्च नहीं होता, उक्त अंतिम मास के अंत के अनिश्चय में उस विनियम वर्ष के प्रारंभ से, जिसमें मृत्यु हुई है, उक्त अंतिम मास के अंत तक की अवधि की बाबत व्याज भी सम्मिलित होगा।

टिप्पणी:—2

इस योजना के अवधीन भगवान् पूर्ण रूपयों में होना चाहिए। यदि किसी देव रकम में रुपये का कोई भाग सम्मिलित है तो उसे निकटतम रूपये में पूर्ण-कित कर दिया जाना चाहिए। पचास पैसे की गणना एक और रूपया के रूप में की जाएगी।

टिप्पणी:—3

इस योजना के अवधीन देव प्रत्यार्थी वीमा धन के किसी भी है और इसलिये भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की लागू 3 डारा दिया गया कानूनी संरक्षण इस योजना के अधीन देव धत्तराणि पर लागू नहीं होता।

टिप्पणी:—4

यह योजना निधि के उन अभिदाताओं पर भी लागू होती है जिन्हें किसी सरकारी विभाग को स्वयंसी संगठन में परिवर्तित कर दिए जाने के परिणामस्वरूप ऐसे निकाय को स्थानान्तरित कर दिया गया है और जिन्होंने ऐसा स्थानान्तरण होने पर अपने वो दिए गए विकल्प के नियंत्रणों के अनुसार इन नियमों के अनुसार इस निधि में अभिदान करने का विकल्प दिया है।

टिप्पणी:—5

(क) ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जिसे नियम 26 या नियम 27 के अधीन निधि के फावदों में शामिल किया गया है, किन्तु जिसकी मृत्यु यथास्थिति निधि में उसके शामिल होने की तारीख से तीन वर्ष की सेवा या पांच वर्ष की सेवा पूरी होने से पूर्व हो जाती है, पूर्ववर्ती नियोजक के अधीन उसकी सेवा की वह अवधि, जिसकी बाबत उसके अभिदातों की रकम और नियोजक का अभिदान, यदि कोई हो, व्याज सहित प्राप्त हो गया है, इस नियम के खंड (क) और खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी।

(ख) आवधिक आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के मामले में और पुनर्नियोजित पेशनभोगी व्यक्तियों के मामले में, यथास्थिति ऐसी नियुक्ति या ऐसे पुनर्नियोजन की तारीख से की गई भेना ही इस नियम पर प्रयोजन के लिए गिनी जाएगी।

(ग) यह योजना संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी।

टिप्पणी-6

इस योजना की बाबत व्यय के बजट प्राक्कलन निधि के लेखा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी लेखा अधिकारी द्वारा व्यय के रूप को ध्यान में रखते हुए उसी रीति में तैयार किए जाएंगे जिस प्रकार अन्य सेवानिवृति कायदों के लिए प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं।

24. जमा राशि-सहन बीमा परिशोधित योजना :—

अभिवाता की मूल्य पर अभिवाता के माम जमा रकम प्राप्त करने के हुक्मार व्यक्ति को लेखा अधिकारी ऐसे अभिवाता की मूल्य से टीक तीन वर्ष पूर्व के दौरान खाते भी औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त रकम इस शर्त के अधीन देगा कि—

(क) ऐसे अभिवाता के नाम जमा अतिशेष उसकी मूल्य के मास से पूर्व तीन वर्ष के दौरान किसी भी समय निम्नलिखित से कम न हो—

(1) ऐसे अभिवाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 4000 रुपये या उससे अधिक है—12,000 रुपये;

(2) ऐसे अभिवाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 2900 रुपये या उससे अधिक है किन्तु 4000 रुपये से कम है—7500 रुपये;

(3) ऐसे अभिवाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 1,151 रुपये या उससे अधिक है किन्तु 2,900 रुपये से कम है—4500 रुपये।

(4) ऐसे अभिवाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में, ऐसा पद धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 1,151 रुपये से कम है—3000 रुपये।

(ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त रकम 30,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

(ग) अभिवाता ने अपनी मूल्य के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो।

टिप्पणी—1 औसत अतिशेष की गणना उस मास से, जिसमें मृत्यु हुई है, पूर्व 36 मास में से प्रत्येक मास के अन्त में अभिवाता के नाम जमा अतिशेष के आधार पर की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए और ऊपर विहित न्यूनतम अतिशेष की जांच करने के लिए थी—

(क) मार्च के अन्त के अतिशेष में नियम 13 के निवंधनों के अनुसार जमा किया गया वार्षिक व्याज भी सम्मिलित होगा;

(ख) यदि उपर्युक्त 36 मासों में से अतिम मास मार्च नहीं है, तो उक्त अन्तिम मास के अन्त के अतिशेष में उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से, जिसमें मृत्यु हुई है, उक्त अन्तिम मास के अंत तक की अवधि की बावजूद व्याज भी सम्मिलित होगा।

टिप्पणी—2 इस योजना के अधीन भुगतान पूर्ण रूपयों में होगा। यदि किसी देव रकम में रुपये का कोई भाग सम्मिलित है तो उसे निकटतम रुपये में पूर्णकित कर दिया जाना चाहिए। प्राप्त वैसे की गणना एक रुपये के रूप में भी जाएगी।

टिप्पणी—3 इस योजना के अधीन देय धनराशि बीमा धन के किसी की है और इसलिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 2 हारा दिया गया कानूनी संरचना इस योजना के अधीन देय धन-राशि पर लागू नहीं होता।

टिप्पणी—4 यह योजना निधि के उन अभिवाताओं पर भी लागू होती है जिन्हें किसी सरकारी विभाग को स्वशासी संगठन में परिवर्तित कर दिए जाने के परिणामस्वरूप ऐसे निकाय को स्थानांतरित कर दिया गया है और जिन्होंने ऐसा स्थानांतरण होने पर अपने को दिए गए विकल्प के निवंधनों के अनुसार इन नियमों के अनुसार इस निधि में अभिदान करने का विकल्प दिया है।

टिप्पणी—5(क) : ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जिसे नियम 26 या नियम 27 के अधीन निधि के कायदों में जामिल किया गया है, किन्तु जिसकी मूल्य, वथा स्थिति निधि में उसके जामिल होने की तारीख से तीन वर्ष की सेवा या पांच वर्ष की सेवा पूरी होने से पूर्व हो जाती है, पूर्ववर्ती नियोजक के अधीन उसकी सेवा की वह अवधि, जिसकी वावत उसके अभिवाताओं की रकम और नियोजक का अभिदान, यदि कोई हो, व्याज सहित प्राप्त हो गया है, इस नियम के खंड (क) और (ग) के प्रयोजन के लिए गिनी जाएगी।

(ख) अवधिक आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के मामले में और पुनर्नियोजित पंथनभोगी व्यक्तियों के मामले में, वथास्थिति, ऐसी नियुक्त या ऐसे पुनर्नियोजित की तारीख से की गई सेवा ही इस नियम के प्रयोजन के लिए गिनी जाएगी।

(ग) वह योजना अधिकार के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी।

टिप्पण 6:—इस गोपनीयता की शाब्दिक अर्थ के अनुच्छेद प्राककलन निधि के लेखा को उत्तर रखने के लिए उत्तरदाती लेखा अधिकारी द्वारा व्यक्त के दब्ज को अन्त में रखो तो उसी गीति से नैयार किए जाएँगे जिस प्रकार अन्य सेवा निवृत्ति फारमों के लिए प्राककलन सैयर किए जाते हैं।

25. निधि में रकम को अदायगी की गीति:—

- (1) जब निधि में अभिवाता के नाम जमा रकम देय हो जानी है तो लेखा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उपनियम (3) में जैसा उपबंधित है उसके अनुसार इस निमित्त लिखित आवेदन प्राप्त होने पर उसकी अदायगी करेगा।
- (2) यदि वह व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन कोई रकम या पालिभी मंदन समनुदेशित, या परिदित की जानी है, पागल है और सम्पदा के लिए पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का 4) के अधीन इस निमित्त वोई प्रबन्धक नियुक्त किया गया है तो ऐसी अदायगी या पुनः गमनुदेशन या परिदाम ऐसे प्रबन्धक को किया जाएगा, उस पागल को नहीं।

परन्तु यदि कोई प्रबन्धक नियुक्त नहीं किया गया है और वह व्यक्ति जिसे गण देय है मजिस्ट्रेट द्वारा पागल प्रमाणित कर दिया जाता है तो अदायगी पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का 4) की धारा 93 की उपधारा (1) के अनुसार कलवटर के आदेश में उस व्यक्ति को की जाएगी जिसकी देव-रेख में ऐसा पागल व्यक्ति है और लेखा अधिकारी केवल उत्तरी रकम उसे भुगतान करेगा जो वह उस व्यक्ति को जिसकी देव-रेख में ऐसा पागलपन है, इना ठीक नम्बर तथा अतिशेष, यदि कोई ही अथवा उसका उतना भाग, जितना लेखा अधिकारी ठीक समझे, ऐसे पागल व्यक्ति के कुटुम्ब के ऐसे सदस्यों के भण्ण-नोपण के लिए भुगतान किया जाएगा जो ऐसे पागल व्यक्ति पर भण्ण-पोषण के लिए आवश्यक है।

- (3) निकाली गई रकम का भुगतान केवल भाग्य में किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को रकम देय है उन्हें रकम को भारत में प्राप्त करने के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी। अभिवाता द्वारा भुगतान का दावा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी अर्थात्:—

- (1) अभिवाता को निधि से रकम निकालने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए कार्यालय का प्रधान प्रत्येक अभिवाता को आधशक्त प्रलेप (फार्म) या नो उसकी अधिवर्धिता पर गेत्रा निवृत्ति की आग पूर्ण होने की तारीख से एक वर्ष पूर्व या यदि उसकी प्रत्याशित सेवा निवृत्ति की तारीख

पूर्वीतर हो तो उसकी प्रत्याशित सेवा निवृत्ति यी तारीख से पूर्व हरा अनुदेश के सापे भीजेगा कि उन प्रारूपों को सम्पूर्ण रूप से पूरा करने के पश्चात अभिवाता प्रारूप प्राप्त होने की तारीख में एक माह के भीतर वापस कर दे। अभिवाता अपने कार्यालय या विभाग के प्रधान के माध्यम से लेखा अधिकारी के समक्ष निधि की रकम के भुगतान के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

आवेदन:—

- (क) निधि में उसके नाम जमा उत्तरी रकम के के लिए किया जाएगा जितनी उसकी अधिवर्धिता पर सेवा निवृत्ति की तारीख है अथवा सेवा निवृत्ति का प्रत्याशित तारीख से एक वर्ष पूर्व समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखा विवरण में उपदर्शित किया गया हो, अथवा
- (ख) यदि अभिवाता को लेखा विवरण प्राप्त नहीं हुआ है तो उत्तरी रकम के लिए किया जाएगा तो खाना वही में उपदर्शित है।
- (ii) कार्यालय अथवा विभाग का प्रधान आवेदन को, लिए गए अग्रिमों और नाम उन अग्रिमों के कारण जो अभी आलू हों, की गई वसूलियों तथा प्रत्येक अग्रिम के संबंध में वसूल की जाने वाली किश्तों की संख्या उपदर्शित करने हुए लेखा अधिकारी को भेजेगा और इसमें लेखा अधिकारी द्वारा भेजी गई अभिवाता के पिछले लेखा विवरण में सम्मिलित अवधि के पश्चात की गई रकम की निकासियां भी प्रदर्शित की जाएंगी।
- (iii) लेखा अधिकारी खाना वही से सत्यापन करने के पश्चात अधिवापित की तारीख से कम से कम एक मास पूर्व किन्तु अधिवर्धिता की तारीख पर देय उस रकम का प्राधिकार जारी करेगा जो आवेदन में उपदर्शित की गई है।
- (iv) खंड (iii) में उल्लिखित प्राधिकारी भुगतान की प्रथम किश्त होगी। भुगतान के लिए विशेष प्राधिकारी अधिवर्धिता के पश्चात वयासंभव शीघ्र जारी किया जाएगा। उसका संबंध उस अभिवाय से होगा जो अभिवाता

द्वारा यंत्र (i) के अधीन प्रमुख जिए गए आवेदन में उल्लिखित रकम के पश्चात किया जाए और इसमें प्रथम आवेदन के समय चालू अधिकारों के प्रति किश्तों का भुगतान भी होगा।

(v) अनिम भुगतान के लिए आवेदन लेखा अधिकारी को भेजने के पश्चात अधिक रकम का निकालना मंजूर किया जा सकता है, किन्तु अधिक/रकम निकाली की रकम मंजूरीप्रति लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकार दिए जाने पर नी जाएगी और लेखा अधिकारी इसकी व्यवस्था मंजूरी प्राधिकारों की ओपचारिक मंजूरी उस प्राप्त होने पर यथाणीय करेगा।

टिप्पणी : —जब नियम 20, 21 और 22 के अधीन अभिभावता के नाम जमा रकम देय हो जाए तो लेखा अधिकारी उपनियम (3) में उपलिखित रीति द्वारा रकम के तत्परता से भुगतान के लिए प्राधिकार जारी करेगा।

26. सरकारी कर्मचारी के एक विभाग में दूसरे विभाग में स्थानांतरण पर प्रक्रिया :

(क) यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जो केंद्रीय सरकार की या किसी राज्य सरकार की किसी अन्य अभिभावती भविष्य निधि का अभिभावता है, केंद्रीय सरकार के किसी विभाग में पेशन योग्य सेवा में स्थाई रूप से स्थानांतरित कर दिया जाता है जिसमें वह इन नियमों से शासित होता है तो स्थानांतरण की तारीख तभी ऐसी अन्य निधि में उसके नाम जमा अभिभावतों की रकम, उस पर व्याज सहित, निधि में उसके जमा खाते में अन्तरित कर दी जाएगी।

परन्तु जहाँ अभिभावता किसी राज्य सरकारी की अभिभावती भविष्य निधि में अभिभावत कर रहा था वहाँ उस सरकार की सहमति प्राप्त की जाएगी।

(ख) यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जो राज्य रेल अभिष्य निधि या केंद्रीय सरकार की किसी अन्य अभिभावती भविष्य निधि या राज्य अभिभावती भविष्य निधि का अभिभावता है, केंद्रीय सरकार के किसी विभाग में पेशन योग्य सेवा में स्थाई रूप से स्थानांतरित कर दिया जाता है जिसमें वह इन नियमों से शासित होता है और जर नक अभिभावता ऐसी निधि के नियमों से शासित होते रहने का चयन नहीं करता है, जबकि ऐसा विकल्प दिया गया है:-

(1) स्थानांतरण की तारीख को ऐसी अभिभावती भविष्य निधि में दर्जे नाम जमा अभिभावतों की रकम, उस पर व्याज सहित अन्य सरकार को, यदि

कोई हो, तो उसकी सहमति से निधि में उसके खाते में अन्तरित कर दी जाएगी;

- (2) ऐसी अभिभावती भविष्य निधि में उसके नाम जमा सरकारी अभिभावतों की रकम, उस पर व्याज सहित, अन्य सरकार की, यदि कोई हो, तो उसकी सहमति से केंद्रीय राजस्व (सिविल) में जमा करा दी जाएगी;
- (3) अभिभावता स्थाई स्थानांतरण की तारीख से पूर्व उसके द्वारा की गई सेवा की गणना के संबंध में जहाँ तक सुसंगत पेशन नियमों के अधीन अनुशेय विस्तार है, पेशन के लिए हकदार होगा।

टिप्पणी 1 : इस नियम के उपबंध ऐसे अभिभावता पर लागू नहीं होते जो सेवानिवृत्त हो गया है और बाद में सेवा में व्यवधान के साथ या उसके बिना पुनःनियोजित किया गया है और उस अभिभावता पर लागू नहीं होता जिसकी पिछली नियुक्ति संविदा के आधार पर थी।

टिप्पणी 2 : परन्तु इस नियम के उपबंध उन व्यक्तियों पर लागू होंगे जिन्हें सेवा में व्यवधान के बिना चाहे अस्थाई रूप से या स्थाई रूप से, सेवा में त्यागपत्र के पश्चात अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्रीय सरकार के अन्य विभाग के अधीन या राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद पर नियुक्त किया जाता है।

27. स्थानांतरण पर प्रक्रिया :

किसी व्यक्ति को सरकार के स्थानांतरण या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय या सोमाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वशासी संगठन से सरकारी सेवा में स्थानांतरित किए जाने पर प्रक्रिया—यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जिसे निधि के फायदे दिए जाने लगे हैं, पहले सरकार के स्थानांतरण या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय अथवा सोमाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वशासी संगठन की किसी भविष्य निधि में अभिभावता था तो उसके अभिभावतों और नियोजकों के अधिदायों की रकम, यदि कोई हो, उन पर व्याज सहित, ऐसे निकाय की सहमति से निधि में उसके लेखे में अन्तरित कर दी जाएगी।

28. अंशदावी भविष्य निधि (भारत) में राज्य का स्थानांतरण :

यदि निधि के किसी अभिभावता को बाद में अभिभावती भविष्य निधि (भारत) के फायदे दिए जाने लगे हैं तो उसके अभिभावतों की रकम, उस पर व्याज सहित, अभिभावती भविष्य निधि (भारत) में उसके जमा लेवे में अन्तरित कर दी जाएगी।

टिप्पणी : —इस नियम के उपबंध उस अभिभावता पर लागू नहीं होते जो संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है या जो सेवा से निवृत्त हो गया है और जिसे बाद में सेवा में व्यवधान के साथ या उसके बिना किसी अन्य पद

पर, जिसमें अभिदाती भविष्य निधि के फायदे प्राप्त होने हैं, पुनः नियोजित किया गया है।

29. अधिक सामलों में नियमों के उपबंधों में छूट :

यदि स्थाई समिति का यह समाधान हो जाना है कि इन नियमों में से किसी के प्रवर्तन में अभिदाता को भावी कठिनाई होती है या होने की संभावना है तो वह, इन नियमों में किसी बात के होने हए भी, ऐमो करने के कारणों का उल्लेख करने के पश्चात् ऐसे अभिदाता के सामले का निपटारा ऐसी गिरि में करेगा जो उन्हें विधिगृह्ण और आम्यपूर्ण प्रतीत हो।

30. अभिदाता के भगतान के समय लेखा संस्था का उद्भव किया जाना। —

भारत में अभिदाता का भगतान करने समय चाहे वह परिलक्षितों में से कटीर्नी द्वारा हो या नकद हो अभिदाता निधि की लेखा संस्था सूचित करेगा जो लेखा अधिकारी द्वारा उसे सूचित की जाएगी। संस्था में होने वाला परिवर्तन लेखा अधिकारी द्वारा उर्मा प्रकार अभिदाता को सूचित किया जाएगा।

31. अभिदाता को वार्षिक लेखा विवरण दिया जाना :

(1) लेखा अधिकारी प्रत्येक वर्ष के अन्त के पश्चात् यथासंभव शीघ्र प्रत्येक अभिदाता को निधि में उसके लेखे का विवरण भेजेगा जिसमें वर्ष के 1 अप्रैल को उसका अर्थात् अनिश्चित, वर्ष के दौरान जमा की गई या

नागे डाली गई कुल रकम वर्ष के 31 मार्च को जमा की गई व्याज की कुल रकम तथा उस तारीख की अंतिम अनिश्चित उपदण्डित किया जाएगा। लेखा अधिकारी, लेखा विवरण के समय यह पूछताल संतुलन करेगा कि क्या :

(क) अभिदाता नियम 7 या इसमें पूर्व प्रवृत्त तत्समान नियम के अधीन किया गया किसी नामितदेशन में कोई परिवर्तन करना चाहता है;

(ख) उन सामलों में जिसमें अभिदाता के नियम 7 के उप नियम (1) के परन्तुके के अधीन अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के पश्च में कोई नामितदेशन नहीं किया है, क्या अभिदाता को कोई कुटुम्ब हो गया है।

(2) अभिदाताओं को वार्षिक विवरण को शुद्धता के संबंध में अपना समाधान कर लेना चाहिए और तुटिया विवरण प्राप्त होने की तारीख के पश्चात् नीति साम के भीतर लेखा अधिकारी को सूचित कर दी जानी चाहिए।

(3) यदि अभिदाता द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो लेखा अधिकारी वर्ष में एक बार किन्तु एक से अधिक बार नहीं अभिदाता को उग अनिश्चित साम की समाप्ति पर जिसकी बाबत लेखा लिखा जा चुका है, निधि में उसके नाम जमा कुल रकम सूचित करेगा।

32. निर्वचन :

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो वह केन्द्रीय सरकार, अम मंडलप का निर्दिष्ट किया जाएगा जो उसका निर्णय करेगा।

अनुसूची-1 [नियम 7 (3) देखें]

नामांकन प्रमाण

लेखा संस्था

मेरे नामे उन्निवेश निधि में मेरे नाम जमा रकम के देय होने से पूर्व अर्थवा ऐसी घटना में वह वह देय हो जाती है, किन्तु उसकी अदायगी न होई हो मेरी मृत्यु हो जाने पर उक्त रकम प्राप्त करने के लिए नीति वर्गीकरण (अक्षितों) को, नियम 2 में यथा परिभायित मेरे कुटुम्ब का/के सदस्य है/हैं/मेरे कुटुम्ब का/के सदस्य नहीं है/हैं, नामित करना है।

नामांकन प्रमाण

(नियम-2)

नामिती (नामितियों) का/के नाम और पर्याप्त पाता/पुरे पते	अभिदाता के साथ नामितार्ग	नामिती (नामितियों) की आवश्यकता	प्रत्येक ऐसी नामिती को देय भाग	आकस्मिकतार्ग जिसके होने पर नामांकन अविधि मान्य हो जाएगा	ऐसा/ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों), यदि कोई हो/ हो के नाम पर्याप्त और नामेदारी जिसको/जिनको नामिती का अधिकारी उस प्रस्तुति में मिल जाएगा जब उसकी मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाए	जीमा वि. नियम 2 में परिभायित है, उसके अनुसार यदि नामिती कुटुम्ब का/ सदस्य नहीं है तो कारण बसा।
---	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

तारीख..... 19..... को स्थान पर
दो माध्यियों के हस्ताक्षर, नाम तथा पते

.....
.....

अभिदाता के हस्ताक्षर.....

स्पष्ट अक्षरों में नाम.....

पदनाम.....

हस्ताक्षर.....

1.....

2.....

कार्यालय प्रधान/वेतन और लेखा कार्यालय के उपयोग के लिए स्थान

श्री/श्रीमती/कुमारी..... द्वारा नामकन, पदनाम.....
नामकन प्राप्त होने की तारीख.....

कार्यालय प्रधान/लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम.....

तारीख.....

अभिदाता के लिए अनुदेण :—

(क) अपना नाम लिखिए।

(ख) निधि के नाम को उपयुक्त रूप से पूरा किया जाए।

(ग) सामान्य भविष्य निधि (फैद्रीय सेवा) नियम, 1960 में दी गई कुटुम्ब की परिभाषा पृष्ठ: नीचे दी जाती है, परिवार से अभिन्न है :—

(1) पुरुष अभिदाता की दशा में पत्नी या पत्निया, माता पिता, सन्ताने, अवयस्क भाई अविवाहित बहने, मृतक पुत्र वंशीय विधवा तथा सन्तानों और जहाँ अभिदाता के माता पिता जीवित नहीं हैं वहाँ उसके माता पिता के पितामह या पितामही या मातामह या मातामही :

परन्तु यदि अभिदाता यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक हो गई है या वह उस समुदाय की जिसकी वह है, रुढ़ी जन्य विधि के अधीन उससे भरण पोषण प्राप्त करने के लिए हक्कार नहीं रह गई है तो उसे तब ये जब तक कि अभिदाता लेखा अधिकारी को बाद में लिखित रूप में यह सूचित न करे कि उसे उस जन्य में जन्म जाता रहेगा। यह समझा जाएगा कि वह उस मामलों में जिनका संबंध इन नियमों से है अभिदाता के कुटुम्ब की सदस्य नहीं रह गई है।

(2) स्त्री अभिदाता की दशा में पति, माता पिता, सन्ताने, अवयस्क भाई, अविवाहित वहने, मृतक पुत्र की विद्वा तथा सन्तानों और जहाँ अभिदाता के माता पिता जीवित न हों वहाँ उसके माता पिता के पितामह या पितामही या मातामह या मातामही :

परन्तु यदि अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप से सूचित करके अपने कुटुम्ब से अपने पति को उपायित करने वाली व्यक्ति करती है तो पति का तब से जब तक कि अभिदाता बाद में ऐसी सूचना को लिखित रूप से रह न कर दें यह समझा जाएगा कि वह उन मामलों में जिनका संबंध इन नियमों से है अभिदाता के कुटुम्ब का सदस्य नहीं रह गया है।

टिप्पणी :—सन्तान से धर्मज सन्तान अभिन्न है और उसके अन्तर्गत जहाँ अभिदाता को शासित करने वाली स्थिति विधि द्वारा दत्तक को मान्यता प्राप्त है दत्तक सन्तान आती है।

(घ) कालम 4 ग्रन्ति के बाल एक ही व्यक्ति को नामित किया जाता है तो उस नामिती के सामने “सम्पूर्ण” लिखा जाएगा। यदि एक से अधिक व्यक्तियों को देय भाग इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिससे भविष्य निधि की पूरी रकम उनके अन्तर्गत आ जाए।

(इ) कालम 5—इस कालम में नामिती (नामितों) की पृष्ठ को आकस्मिकताओं के रूप में वर्णित नहीं किया जाएगा।

(च) कालम 6—अपना नाम न लिखें।

(छ) अन्तिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान में एक रेखा खींच दें जिसमें आपके हस्ताक्षर फरने के बाद उस स्थान में कोई नाम न लिखा जा सके।

अनुसूची 2

[नियम 14(1) और 17(1) देखें]

मामान्य भविष्य निति से अग्रिम/राशि निकासी के लिए आवेदन पत्र

1. अभिदाता का नाम
2. लेखा संख्या
3. पदनाम
4. (1) वेतन रूपये
(2) मासिक अभिदान रूपये
5. निकासी के मामले में
(1) जन्म तिथि
(2) नियुक्ति की तारीख
(3) सेवा निवृत्ति की तारीख

आवेदन को तारीख को अभिदाता के खाते में कुल राशि निम्न प्रकार है—

1. वर्ष 199.....	के लेखा विवरण के अनुसार
.....	अतिशेष है।
2. दिनांक..... से तक तक	रुपये
मासिक अभिदान से कुल जमा राशि	रूपये
3. अग्रिम राशि की वापसी
4. दिनांक..... से से तक की अवधि के दौरान निकासित रूपये
.....
5. के नाम बकाया निवल धन राशि रूपये
6. अग्रिम की बकाया राशि, यदि कोई है, तथा सी गई राशि का प्रयोजन
.....	ली गई राशि रूपये
की तारीख को.....	शेष बकाया राशि रु
7. मांगे गए अग्रिम की राशि रूपये
8. क. किस प्रयोजन के लिए अग्रिम चाहिए
ख. नियम जिनके अन्तर्गत आवेदन अधिमान्य होता है
ग. यदि भवन निर्माण आदि के प्रयोजन के लिए अग्रिम मांगा जाता है तो निम्नलिखित सूचना दी जाएः—
(1) प्लाट स्प्ल तथा उसकी पैमाइश
(2) क्या यह प्लाट पूर्ण स्वामित्व में है अथवा पढ़टे पर
(3) निर्माण का नक्शा
(4) यदि फ्लैट अथवा प्लाट हाऊस बिल्डिंग समिति से खरीदा जा रहा है तो उस समिति का नाम
फ्लैट अथवा प्लाट तथा उसकी पैमाइश आदि

- (5) निर्माण की लागत.
- (6) यदि पन्ट दिवाना विकास प्राधिकारण अथवा किसी हाउसिंग बोर्ड ने खरीदा जाता है तो उसके स्थान, परिमाण आदि का उल्लेख किया जाए।
- (अ) यदि अग्रिम संतान गिरणप्रवीजन के लिए मांगा जाए तो निम्नलिखित विवरण दिया जाए—
- (1) पुत्र/पुत्री का नाम
 - (2) कभी तथा मंस्थान/कवित्र जहाँ अध्ययन कर रहा/रही है
 - (3) क्या वह दिवालाल है अथवा छावात्राम में रहता है
- (इ) यदि अग्रिम परिवार के किसी रोगी के उत्तरार्थ के लिए मांगा जाए तो निम्नलिखित विवरण दिया जाए—
- (1) रोगी का नाम तथा उसके साथ संबंध
 - (2) अस्पताल/औषधालय/उम डाक्टर का नाम जहाँ रोगी का इवाज चल रहा है
 - (3) यदि बढ़िरंग अथवा अन्तर्गत रोगी है
 - (4) क्या प्रतिभूति डाक्टर है अथवा नहीं

टिप्पणी— 8(ग) रे 8(इ) के अवधीन मामले में किसी प्रमाण पत्र वा शस्त्रवेशी माल्य वा आवश्यकता महा होगी।

9. संबंधित अग्रिम की रागि (मद 6 और 7) तथा मासिक किसी की मंदिर जिसमें गमेकिन अग्रिम रागि राये का किसी में जीडान का प्रसाद है।

10. अधिकारी को आकार पर्याप्ततयों के पूर्ण व्यौर्य जिसमें अग्रिम के लिए आवेदन पत्र को उचित अद्यता जा सकता है।

मैं प्रभागित करता हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी और विषयमें हॉर्ट शिए गए व्यारोग महा हैं तथा इसमें कोई भी तथ्य नहीं डिगार गया है।

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अनुभाग

हस्ताक्षर

पदनाम

[पाइल सं. एस 65012/1/90-एसएस-1]

जे.पी.शुक्ला, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 6th September, 1995

G.S.R. 431.—Whereas certain draft rules namely the Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules, 1993 were published as required under sub-section (i) of Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. GSR 575 dated the 27th October, 1994 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 19th November, 1994 inviting objections or suggestions from any persons likely to be affected thereby within forty-five days from the date of its publication in the official Gazette.

And whereas, the said draft Rules were published in the Official Gazette on the 19th November, 1994.

And whereas the Gazette copies of the draft rules in which they were published were made available to the public on 19th November, 1994.

And whereas, no objections or suggestions have been received from any person likely to be affected thereby.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 95 of the said Act, and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules, 1973, except as respects things done or omitted

to be done before such supersession, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules, 1995.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions : (1) In these rules unless the context otherwise requires—
- (a) "Accounts Officer" means the Financial Commissioner of the Employees' State Insurance Corporation or such other officer as may be specified in this behalf;
- (b) "Act" means the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948);
- (c) "Corporation" means Employees' State Insurance Corporation;
- (d) "emoluments" means pay, leave salary or subsistence grant if admissible and any remuneration of the nature of pay received in respect of deputations;
- (e) "employee" means a person appointed to or born on the cadre of the staff of the Corporation, other than persons on deputation;

(i) "Family" means—

- (a) In the case of a male-subscriber the wife or wives, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a paternal grandparent :

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance, she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate, unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Accounts Officer that he shall continue to be so regarded;

- (b) In the case of a female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children where no parent of the subscriber is alive, a paternal grandparent :

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Accounts Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

Explanation—In this clause, child means legitimate child and includes an adopted child, where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber;

- (c) 'Fund' means the Employees State Insurance Corporation General Provident Fund;
- (d) 'Leave' means any kind of leave recognised by the Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1959;
- (e) 'Service' means service under the Corporation;
- (f) 'Year' means a financial year.
- (g) Any other expressions used in these rules which is defined either in the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) or Employees State Insurance Act, 1948 or in the Fundamental Rules, is used in the sense thereto defined but no defined herein shall have the meaning respectively assigned to them in the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) the Employees' State Insurance Corporation (Central) Rules, 1950, Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1959 or the Fundamental Rules, as the case may be.
- (h) Nothing in these rules shall be deemed to have the effect of terminating the existence of the General Provident Funds as heretofore existing or of constituting any new fund.

3. Constitution of the Fund—(1) The Fund shall be maintained in Rupees.

(2) All sums paid into the Fund under these rules shall be credited to a Fund called 'The Employees' State Insurance Corporation General Provident Fund'. Sums of which payment has not been taken within six months after they become payable under these rules shall be transferred to the Deposit Account at the end of the year and treated under the ordinary rules relating to deposits.

4. Operation of Fund by the Accounts Officer—The Fund shall be operated upon by the Accounts Officer who is hereby authorised to arrange for all payments required to be made under these rules.

5. Investments—All monies belonging to the Fund shall be invested in the manner specified in the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, for investment of monies belonging to the Employees' State Insurance Fund.

6. Conditions of eligibility—All temporary employees after a continuous service of one year, all re-employed pensioners (other than those eligible for admission to CPF) and all permanent employees shall subscribe to the Fund :

Provided that no such employee as has been required or permitted to subscribe to a Contributory Provident Fund shall be eligible to join or continue as a subscriber to the Fund while he retains his right to subscribe to such a Fund :

Provided further that such of the temporary employees who have completed continuous service of one year before the 31st March, 1960 shall not subscribe to the Fund from a date earlier than the 1st April, 1960.

Explanation—A temporary employee who completes one year of continuous service on any day of a month shall subscribe to the fund with effect from the subsequent month.

Note-1—Apprentices and Probationers shall be treated as temporary employees for the purpose of this rule.

Note-2—A temporary employee who completes one year of continuous service during the middle of a month shall subscribe to the Fund from the subsequent month.

Note-3—Temporary employee (including Apprentices and Probationers) who have been appointed against regular vacancies and are likely to continue for more than a year may subscribe to the General Provident Fund any time before completion of one year's service.

7. Nominations—(1) A subscriber shall, at the time of joining the Fund, send to the Accounts Officer a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund in the event of his death, before that amount has become payable or having become payable has not been paid :

Provided that where a subscriber is a minor he shall be required to make the nomination only on his attaining the age of majority :

Provided further that a subscriber who has a family at the time of making the nomination shall make nomination only in favour of a member or members of his family :

Provided also that the nomination made by the subscriber in respect of any other provident fund to which he was subscribing before joining the Fund shall if the amount to his credit in such other fund has been transferred to his credit in the Fund, be deemed to be a nomination in accordance with this rule.

If a subscriber nominates more than one person under sub-rule (1) he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees, in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time.

(2) Every nomination shall be made in the Forms set forth in the Schedule I appended to these rules.

(3) A subscriber may at any time cancel a nomination made by him by sending a notice in writing to the Accounts Officer. The subscriber shall alongwith such notice or separately send a fresh nomination made in accordance with the provision of this rule.

(4) A subscriber may provide in a nomination—

(a) That in the event of his predeceasing the subscriber the right conferred upon the specified nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination :

Provided that such other person or persons shall, if the subscriber has any other members in his family, be such member or members of the family :

Provided further that where the subscriber confers the right under this clause on more than one person, he shall specify the amount or share payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee.

(b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein.

Provided that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of his family he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under clause (a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause (a) of sub-rule (5) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (b) of sub-rule (5) or the proviso thereto the subscriber send a notice in writing to the Accounts Officer cancelling the nomination, together with the fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

(7) Every nomination made, and every notice of cancellation given, by a subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Accounts Officer.

Note : In this rule, unless the context otherwise requires 'person' or 'persons' shall include a company or association or body of individuals, whether incorporated or not. It shall also include a Fund such as the Prime Minister's National Relief Fund or any Charitable or other Trust or Fund, to which nomination may be made through the Secretary or other executive of the said Funds or Trust authorised to receive payments.

8. Subscriber's Account : An account shall be opened in the name of each subscriber to show—

- (i) his subscriptions;
- (ii) interest, as provided in rule 13 on subscriptions;
- (iii) advances and withdrawals from the Fund.

9. Conditions and rates of subscriptions : (1) A subscriber shall subscribe to the Fund every month except during the period when he is under suspension.

Provided that a subscriber on reinstatement after a period of suspension shall be allowed the option of paying in one lumpsum or in instalments any sum not exceeding the maximum amount of arrear of subscription payable in respect of the said period.

Provided further that subscriber may, at his option not subscribe during any period of leave which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay.

Note 1.—The holder of a seasonal post in an establishment need not subscribe to the Fund, during the period of his employment.

Note 2.—A subscriber need not subscribe during a period treated as dies non.

(2) The subscriber shall intimate his option not to subscribe during leave referred to in the second proviso to sub-rule (1) in the following manner :—

- (a) If he is an officer who draws his own pay bills, by making no deduction on account of subscription in his first pay bill drawn after proceeding on leave.
- (b) If he is not an officer who draws his own pay bills, by written communication to the head of office before he proceeds on leave. On failure to make due and timely intimation shall be deemed to constitute an option to subscribe.

Note.—The option of a subscriber once intimated under this sub-rule shall be final.

(3) A subscriber who has under rule 17 withdrawn the amount standing to his credit in the Fund shall not subscribe to the Fund after such withdrawal unless he returns to duty.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) a subscriber shall not subscribe to the Fund for the month in which he quits service unless, before the commencement of the said month, he communicates to the Head of Office in writing his option to subscribe for the said month.

10. Rates of subscription—(1) The amount of subscription shall be fixed by the subscriber himself, subject to the following conditions, namely—

- (a) It shall be expressed in whole rupees.
- (b) It may be any sum, so expressed which shall not be less than 6 per cent of his emoluments and not more than his total emoluments :

Provided that in the case of a subscriber who has previously been subscribing to the Employees' State Insurance Corporation Contributory Provident Fund at the higher rate of 8-1/3%, it may be any sum so expressed shall not be less than 8-1/3% of his total emoluments and not more than his total emoluments.

- (c) When an employee opt to subscribe at the minimum rate of 6%, or 8-1/3 per cent, as the case may be, the subscription shall be rounded to the nearest whole rupee and for this purpose, 50 paise and more shall be rounded to the next higher rupee.

(2) For the purpose of sub-rule (1) the emoluments of a subscriber shall be—

- (a) in the case of subscriber who was in service on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on that date ; provided that—
 - (i) if the subscriber was on half day leave on the said date and opted not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty;
 - (ii) if the subscriber was on deputation out of India on the said date or was on half pay leave on the said date and continues to be on leave and has opted to subscribe during such leave, his emoluments to which he would have been entitled had he been on duty or on duty in India as the case may be;
- (b) in the case of a subscriber who was not in service on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on the day he joins the Fund.

(3) The subscriber shall intimate the fixation of the amount of his monthly subscription in each year in the following manner, namely :—

- (a) if he was on the 31st March of the preceding year, by the deduction which be causes to be made in this behalf from his pay bill for that month ;
- (b) if he was on leave on the 31st March of the preceding year and opted not to subscribe during such half pay leave or was under suspension on that date, by the deduction which he makes in this behalf from his first pay bill after his return to duty;
- (c) If he was on leave on the 31st March of the preceding year, and continues to be on half pay leave and has opted to subscribe during such leave by the deduction which he makes or cause to be made in this behalf from his salary for the month.
- (d) if he has entered into service for the first time during the year, by the deduction which he makes or causes to be made in this behalf, from the salary bill for that month during which he joins the Fund ;
- (e) if he was on deputation on the 31st March of the preceding year by the amount credited by him in the Fund of the Corporation on account of subscription for the month of April in the current year.

(4) The amount of subscription so fixed may be,—

- (a) reduced once at any time during the course of the year;
- (b) enhanced twice during the course of the year; or
- (c) reduced and enhanced as aforesaid :

Provided that when the amount of subscription is so reduced it shall not be less than the minimum prescribed in sub-rule (1).

Provided further that if a subscriber is on leave without pay or leave on half pay or half average pay for a part of a calendar month and he has opted not to subscribe during such leave, the amount of subscription payable shall be proportionate to the number of days spent on duty including leave, if any, other than those referred to above.

11. Transfer on deputation to a post under the Government or any other organisation or deputation of India.—When subscriber is transferred or sent on deputation out of India, he shall remain subject to these rules in the same manner as if he were not so transferred or sent on deputation.

12. Realisation of subscriptions.—(1) When the emoluments are drawn from the Fund, recovery of subscriptions and the principal and interest of advances, if any, granted from the Fund shall be made direct from the emoluments.

(2) When emoluments are drawn from any other source, the subscriber shall forward his dues monthly to the Accounts Officer.

Provided that in the case of a subscriber on deputation to a body corporate owned or controlled by Government the subscription shall be recovered and forwarded to the Accounts Officer by such body.

(3) If a subscriber fails to subscribe with effect from the date on which he is required to join the Fund or is in default in any month or months during the course of a year otherwise than as provided in rule 9, the total amount due to the Fund on account of arrears or subscription shall, with interest thereon at the rate provided in rule 13, forthwith be paid by the subscriber to the Fund or in default be ordered by the Accounts Officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber by instalments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub-rule (2) of rule 14:

Provided that the subscribers whose deposits in the Fund carry no interest shall not be required to pay any interest.

13. Interest.—(1) Subject to the provisions of sub-rule (5), the Corporation shall pay to the credit of the account of a subscriber interest at such rate as may be determined for each year by the Central Government in respect of the General Provident Fund for the Central Government Employees :

Provided that if the rate of interest determined for a year is less than 4 per cent, all subscribers to the Fund in the year preceding that for which the rate has for the first time been fixed at less than 4 per cent, shall be allowed interest at the rate of 4 per cent:

Provided further that a subscriber who was previously subscribing to any other Provident Fund of the Central Government and whose subscriptions, together with interest thereon, have been transferred to his credit in his Fund under rule 26 shall also be allowed interest at the rate of 4 per cent, if he had been receiving that rate of interest under the rules of such other Fund under a provision similar to that of the first proviso to this rule.

(2) Interest shall be credited with effect from the last day in each year in the following manner:

- (i) on the amount to the credit of a subscriber on the last day of the preceding year, less sums, if any, withdrawn during the current year, interest for twelve months;
- (ii) on sums withdrawn during the current year interest from the beginning of the current year upto the last day of the month preceding the month of withdrawal;
- (iii) on all sums credited to the subscriber's account after the last day of the preceding year interest from the current year;
- (iv) the total amount of interest shall be rounded to the nearest whole rupee (fifty paise and more counting as the next higher rupee):

Provided that when the amount standing to the credit of a subscriber has become payable, interest shall thereupon be credited under this rule in respect only of the period from the beginning of the current year or from the date of deposit, as the case may be, upto the date on which the amount standing to the credit of the subscriber becomes payable.

(3) In this rule, the date of deposit, shall, in the case of recovery from emoluments, be deemed to be the first day of the month in which it is recovered, and in the case of an amount forwarded by the subscriber, shall be deemed to be the first day of the month of receipt, if it is received by the Accounts Officer before the fifty day of that month, but if it is received on or after the fifty day of that month the first day of the next succeeding month:

Provided that where there has been a delay in the drawal of pay or leave salary and allowances of a subscriber and consequently the recovery of his subscription towards the Fund, the interest on such subscriptions shall be payable from the month in which the pay or leave salary of the subscriber was due under the rules, irrespective of the month in which it was actually drawn:

Provided further that in the case of an amount forwarded in accordance with the proviso to sub-rule (2) of rule 12, the date of deposit shall be deemed to be the first day of the month if it is received by the Accounts Officer before the fifteenth day of that month:

Provided also that where the emoluments for a month are drawn and disbursed on the last working day of the same month the date of deposit shall, in the case of recovery of his subscription, be deemed to be first day of the succeeding month.

(4) In addition to any amount to be paid under rules 20, 21 or 22 interest thereon upto the end of the month preceding that in which the payment is made or upto the end of the sixth month after the month in which such amount become payable whichever of these periods be less, shall be payable to the person to whom such amount is to be paid:

Provided that where the Accounts Officer has intimated to that person (or his agent) a date on which he is prepared to make payment in cash or has posted a cheque in payment to that person, interest shall be payable only upto the end of the month preceding the date so intimated or the date of posting the cheque, as the case may be:

Provided further that where a subscriber on deputation to a body corporate, owned or controlled by the Government of an autonomous organisation registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) is subsequently absorbed in such body corporate or organisation with effect from a retrospective date, for the purpose of calculating the interest due on the Fund accumulations of the subscriber the date of issue of the orders regarding absorption shall be deemed to be the date on which the amount to the credit of the subscriber became payable subject to the condition that the amount recovered as subscription during the period commencing from the date of absorption and ending with the date of issue of orders of absorption shall be deemed to be subscription to the Fund only for the purpose of awarding interest under this sub-rule.

(5) Interest shall not be credited to the account of a subscriber if he informs the Accounts Officer that he does not wish to receive it; but if he subsequently asks for interest, it shall be credited with effect from the first day of the year in which he asks for it.

(6) The interest on amount which under sub-rule (3) of rule 12, rule 20, or rule 21 are replaced to the credit of the subscriber in the Fund, shall be calculated at such rates as may be successively prescribed under sub-rule (1) of this rule and so far as may be in the manner prescribed in this rule.

(7) In case a subscriber is found to have drawn from the Fund an amount in excess of the amount standing to his credit on the date of the drawal the overdrawn amount, irrespective of whether the overdrawal occurred in the course of an advance or a withdrawal or the final payment from the Fund, shall be repaid by him with interest thereon in one lump-sum, or in default be ordered to be recovered by deduction one lump-sum, from the emoluments of the subscriber. If the total amount to be recovered is more than half of the subscriber's emoluments, recoveries shall be made

in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount together with interest, is recovered. For this sub-rule the rate of interest, to be charged on overdrawn amount would be 2½ per cent over and above the normal rate on Provident Fund balance under sub-rule (1). The interest realised on the overdrawn amount shall be credited to Corporation account under a distinct sub-head 'Interest on withdrawals from Provided Fund' under the head "049-Interest Receipts-C—other interest receipts of Corporation—Other Receipts".

14. Advance from the Fund.—(1) The Director General or any other Officer authorised by him in this behalf, may sanction the payment to any subscriber in the prescribed Form as specified in Schedule-II of an advance consisting of a sum of whole rupees and not exceeding in amount three months pay or half the amount standing to his credit in the Fund, whichever is less, for one or more of the following purposes, namely :—

- (a) to pay expenses in connection with the illness, confinement or a disability including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him.
- (b) to meet the cost of higher education including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and member of his family or any person actually dependent on him; in the following cases, namely :—
 - (i) for the education outside India in respect of an academic, a technical, a professional or vocational course beyond the high school stage; and
 - (ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the high school stage, provided that the course of study is or not less than three years duration;
- (c) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscribers' status which, by customary usage the subscribers' has to incur in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies;
- (d) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber or any person actually dependent upon him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other Government source
- (e) to meet the cost of his defence where the subscriber engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part;
- (f) to meet the cost of plot or construction of a house or flat for his residence or to make any payment towards the allotment of a plot or flat by the Delfi Development Authority or a State Housing Board or a House Building Co-operative Society.

(2) The Director General may, in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of an advance if he is satisfied that the subscriber concerned requires the advance for reasons other than those mentioned in sub-rule (1).

(3) An advance shall not, except for special reasons to be recorded in writing, be granted to any subscriber in excess of the limit laid down in sub-rule (1) or until repayment of the last instalment of any previous advance.

(4) When an advance is sanctioned under sub-rule (3) before repayment of last instalment of any previous advance is completed the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the instalments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount.

(5) After sanctioning the advance, the amount shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer in case where the application for final payment had been forwarded to the Accounts Officer under clause (iii) of sub-rule (3) of rule 23.

Note 1.—For the purpose of this rule pay includes dearness pay, where admissible.

Note 2.—A subscriber shall be permitted to take an advance once in every six months under clause (b) of sub-rule (1) of rule 14.

15. Recovery of advance.—(1) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalments as the sanctioning authority may direct; but such number shall not be less than twelve unless the subscriber so opt and in any case not more than twenty four. In special cases where amount of advance exceeds three months' pay of the subscriber under sub-rule (2) of rule 14, the sanctioning authority may fix such number of instalments exceeding twenty four but not exceeding thirty six. A subscriber may, at his option, repay more than one instalment in a month. Each instalment shall be fixed in whole rupees, the amount of the advance being raised or reduced if necessary, to admit the fixation of such instalments.

(2) Recovery of advances shall be made in the manner specified in rule 12 for the realisation of subscription, and shall commence with the issue of pay for the month following the one in which the advance was drawn. Recovery shall not be made, except with the subscriber's consent while he is in receipt of subsistence grant or is on leave for ten days or more in a calendar month which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay, as the case may be. The recovery may on the subscriber's written request, be postponed by the sanctioning authority during the recovery of an advance of pay granted to the subscriber.

(3) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before repayment is completed, the whole or balance of amount withdrawn shall be forthwith repaid by the subscriber to the Fund. Or in default, be ordered by the Accounts Officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber in a lump sum or in monthly instalments not exceeding twelve as may be directed by the Accounts Officer :

Provided that before such advance is disallowed, the subscriber shall be given reasonable opportunity to explain the sanctioning authority to writing within 15 days of the receipt of the communication that why the repayment shall not be enforced and if an explanation is submitted by the subscriber within the said period of 15 days, it shall be referred to the Director General for decision and if no explanation within the said period is submitted by him, the repayment of the advance shall be enforced in the manner prescribed in the sub-rule.

(4) Recoveries made under this rule shall be credited to the subscriber's account in the Fund.

16. Wrongful use of advance.—Notwithstanding anything contained in these rules, if the sanctioning authority has reason to doubt that money drawn as an advance from the Fund under rule 14 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money, he shall communicate to the subscriber the reasons for his doubt and require him to explain in writing and within 15 days of the receipt of such communication whether the advance has been utilised for the purpose for which sanction was given to the drawal of the money. If the sanctioning authority is not satisfied with the explanation furnished by the subscriber within the said period of 15 days, the sanctioning authority shall direct the subscriber to repay the amount in question to the Fund forthwith or, in default, order the amount to be recovered by deduction in one sum from the emoluments of the subscriber even if he be on leave. If, however, the total amount to be repaid be more than half the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount is repaid by him.

Note:—The term "emoluments" in this rule shall not include subsistence grant.

17. Withdrawal from the Fund.—(1) Subject to the conditions specified therein, withdrawals may be sanctioned to the subscriber in the prescribed Form as specified in Schedule-II, by the authorities competent to sanction an advance for special reasons under sub-rule (2) of rule 14, at any time, after the completion of twenty years of service (including broken period of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit

in the Fund, for one or more of the following purposes, namely :—

- (a) meeting the cost of higher education, including where necessary the travelling expenses of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases, namely :—
 - (i) for the education outside India for academic, technical, professional or a vocational course beyond the high school stage; and
 - (ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the high school stage;
 - (b) meeting the expenditure in connection with the betrothal/marriage of the subscriber or his sons or daughters and of any other family relation actually dependent on him;
 - (c) meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the travelling expenses, of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;
- (2) After the completion of (Ten years) of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, a subscriber will be allowed withdrawals from the amount standing to his credit in the Fund for one or more of the following purposes, namely :
- (i) building or acquiring a suitable house or readybuilt flat for his residence including the cost of the site;
 - (ii) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or readybuilt flat for his residence;
 - (iii) purchasing a house-site for building a house thereon for his residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose;
 - (iv) reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber;
 - (v) renovating, additions or alterations or upkeep of an ancestral house at a place other than the place of duty or to a house built with the assistance of loan from Government at a place other than the place of duty;
 - (vi) constructing a house on a site purchased under clause (iii).
 - (vii) within six months before the date of the subscriber's retirement for the amount standing to his credit in the Fund for the purpose of acquiring a farm land or business premises or both.
 - (viii) once during the course of a financial year, an amount equivalent to one year's subscription paid for by the subscriber towards the Group Insurance Scheme for the Corporation employees on self financing and contributory basis.

Note 1.—A subscriber who has availed himself of an advance under the scheme of the Ministry of Urban Development for the grant of advance for house building purpose, or has been allowed any assistance in this regard from any other Government source shall be eligible for the grant of final withdrawal under clauses (i), (iii), (iv), (vi) or sub-rule (2) for the purpose specified therein and also for the purpose of repayment of any loan taken under the aforesaid scheme subject to the limit specified in the proviso to sub-rule (1) of rule 18.

If a subscriber has an ancestral house or built a house at a place other than the place of his duty with the assistance of loan taken from the Government he shall be eligible for the grant of a final withdrawal under clauses (i), (iii) and

(vi) of sub-rule (2) for purchase of a house-site or for construction of another house or for acquiring a readybuilt flat at the place of his duty.

Note 2.—Withdrawal under clauses (i), (iv), (v) or (vi) of sub-rule (2) shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the additions or alterations to be made, duly approved by the local municipal body of the area where the site or house is situated and only in cases where the plan is actually got to be approved.

Note 3.—The amount of withdrawal sanctioned under clause (ii) of sub-rule (2) shall not exceed 3/4th of the balance on date of application together with the amount of previous withdrawal under clause (i) reduced by the amount of previous withdrawal. The formula to be followed is 3/4th of (the balance as on date plus amount of previous withdrawal(s) for the house in question) minus the amount of the previous withdrawal(s).

Note 4.—Withdrawal under clause (i) or (iv) of sub rule (2) shall also be allowed where the house site or house is in the name of wife or Husband provided she or he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

Note 5.—Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this rule. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to a house or flats covered by a fresh plan duly approved by the local municipal body of the area where the house or flat is situated shall not be treated as the same purpose. Second or subsequent withdrawal under clause (i) or (vi) of sub-rule (2) for completion of the same house shall be allowed upto the limit laid down under Note 3.

Note 6.—A withdrawal under this rule shall not be sanctioned if an advance under rule 14 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

(3) After sanctioning the withdrawal the amount shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer in cases where the application for final payment had been forwarded to the Accounts Officer under clause (ii) of sub-rule (3) of rule 25.

18. Conditions for withdrawal:—(1) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes, specified in rule 17 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one-half of such amount or six months' pay, whichever is less. The sanctioning authority may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit upto 3/4th of the balance at his credit in the Fund having regard to (i) the object for which the withdrawal is being made, (ii) the status of the subscriber and (iii) the amount to this credit in the Fund.

Provided that in no case the maximum amount of withdrawal for purposes specified in sub-rule (2) of rule 17 shall exceed the maximum limit prescribed from time to time under rule 2(a) and 3(b) of the scheme of the Ministry of Urban Development for the grant of advances for house building purposes.

Provided further that in the case of a subscriber who has availed himself of an advance under the scheme of the Ministry of Urban Development for the grant of advances for house building purpose, or has been allowed any assistance in this regard from any other Government sources, the sum withdrawn under this sub-rule together with the amount of advance taken under the aforesaid scheme or the assistance taken from any other Government source shall not exceed the maximum limit prescribed from time to time under rules 2(a) and 3(b) of the aforesaid scheme.

Note 1.—A withdrawal sanctioned to a subscriber under clause (i) of sub-rule (2) of rule 17 may be drawn in instalments, the number which shall not exceed four in a period of twelve calendar months counted from the date of sanction.

Note 2.—In cases where a subscriber has to pay in instalments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed through the Delhi Development Authority or a State Housing Board or a House Building Co-operative Society he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment in any instalment. Every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for rule 16.

(2) A subscriber who has been permitted to withdraw money from Fund under rule 17 shall satisfy the sanctioning authority with in such reasonable period as may be specified by that authority that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn, or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn shall forthwith be repaid in one lump sum by the subscriber to the Fund and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined by the Director General :

Provided that, before repayment of a withdrawal is enforced under this sub-rule the subscriber shall be given a reasonable opportunity to explain in writing and within 15 days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced and if the sanctioning authority is not satisfied with the explanation or no explanation is submitted by the subscriber within the said period of 15 days the sanctioning authority shall enforce the repayment in the manner prescribed in this sub-rule.

(3) (a) A subscriber who has been permitted under clause (i), (ii) or (iii) of sub-rule (2) of rule 17 to withdraw money from the amount standing to his credit in the Fund, shall not part with the possession of the house, built or acquired or house-site purchased with the money so withdrawn, whether by way of sale, mortgage (other than mortgage to the Director General), gift, exchange or otherwise, without the previous permission of the Director General :

Provided that such permission shall not be necessary for—

- (i) the house or house-site being leased for any term not exceeding three years, or
- (ii) its being mortgaged in favour of a Housing Board, Nationalised Banks, the Life Insurance Corporation or any other Corporation owned or controlled by the Central Government which advances loans for the construction of a new house or for making additions or alteration to an existing house.

(b) The subscriber shall submit a declaration not later than the 31st day of December of every year as to whether the house or the house-site as the case may be, continues to be in his possession or has been mortgaged, otherwise transferred or let out as aforesaid and shall, if so required, produce before the sanctioning authority on or before the date specified by that authority in that behalf, the original sale, mortgage or lease deed and also the documents on which his title to the property is based.

(c) If at any time before his retirement, the subscriber parts with the possession of the house or house-site without obtaining the previous permission of the Director General, he shall forthwith repay the sum so withdrawn by him in default of such repayment, the sanctioning authority shall, after giving the subscriber a reasonable opportunity for making a representation in the matter cause the said sum to be recovered from the emoluments of the subscriber either in lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined by it.

Note A.—A subscriber who has taken loan from ESI Corporation in lieu thereof mortgaged the house or house-site to the Corporation shall be required to furnish the declaration to the following effect, namely :—

Declaration

"I do hereby certify that the house or house-site for the construction of which or for the acquisition of which I have taken a final withdrawal from the Provident

Fund continues to be in my possession but stands mortgaged to Corporation."

19. Conversion of an advance into a withdrawal.—A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under rule 14 for any of the purposes specified therein may convert, at his discretion by written request addressed to the Accounts Officer through the sanctioning authority, the balance outstanding against it into a final withdrawal on his satisfying the conditions laid down in rules 17 and 18.

Note 1.—The Head of office in case of non-gazetted subscribers and the Treasury Officer concerned in the case of gazetted subscribers may be asked by the administrative authority to stop recoveries from the pay bills when the application for such conversion is forwarded to the Accounts Officer that authority shall endorse a copy of the letter forwarding the subscriber's intimation to the Treasury Officer from where he draws his pay in order to permit stoppage of further recoveries.

Note 2.—For the purpose of sub-rule (1) of rule 18, the amount of subscription, with interest thereon standing to the credit of the subscriber in the account at the time of conversion plus the outstanding amount of advance shall be taken as the balance. Each withdrawal shall be treated as a separate one and the same principle shall apply in the event of more than one conversion.

20. Final withdrawal of accumulations in the Fund.—When a subscriber quits the service of the Corporation the amount standing to his credit in the Fund shall become payable to him :

Provided that a subscriber, who has been dismissed from the service and is subsequently reinstated in the service, shall if required to do so by the Director General, repay any amount paid to him from the fund in pursuance of this rule, with interest thereon at the rate provided in rule 13 in the manner prescribed in the proviso to rule 21. The amount so repaid shall be credited to his account in the Fund.

Explanation I.—A subscriber, other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently reemployed, with or without a break in service shall not be deemed to quit the service, when he is transferred without any break in service to a new post under a State Government or in another department of the Central Government (in which he is governed by another set of provident fund rules) and without retaining any connection with his former post, in such case, his subscriptions together with interest thereon shall be transferred—

- (a) to his account in the other Fund in accordance with the rules of that Fund, if the new post is in another department of the Central Government, or
- (b) to a new account under the State Government concerned if the new post is under a State Government and the State Government consents, by general or special order, to such transfer of his subscriptions and interest.

Note.—Transfers shall include cases of resignations from service in order to take up appointment in another department of the Central Government or under the State Government without any break and with proper permission of the Central Government. In cases where there has been a break in service it shall be limited to the joining time allowed on transfer to a different station.

The same shall hold good in cases of retrenchments followed by immediate employment whether under the same or different Government.

Explanation II.—When a subscriber, other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently reemployed or is transferred, without any break, to the service under a body corporate owned or controlled by Government, or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860, the amount of subscriptions together with interest thereon, shall not be paid to him but shall be transferred with the consent of that body to his new Provident Fund Account under that body.

Transfers shall include cases or resignation from service in order to take up appointment under a body corporate owned or controlled by Government or an autonomous organisation registered under the Societies Registration Act, 1860, without any break and with proper permission of the Central Government. The time taken to join the new post shall not be treated as a break in service if it does not exceed the joining time admissible to a Government servant on transfer from one post to another:

Provided that the amount of subscription together with interest thereon, of a subscriber opting for service under a public Enterprise may, if he so desires, be transferred to his new Provident Fund Account under the Enterprise if the concerned Enterprise also agreed to such a transfer. If, however, the subscriber does not desire the transfer or the concerned Enterprise does not operate a Provident Fund. The amount aforesaid shall be refunded to the subscriber.

21. Retirement of Subscriber.—When a subscriber—

- (a) has proceeded on leave preparatory to retirement or if he is employed in a vacation department on leave preparatory to retirement combined with vacation, or
- (b) while on leave, has been permitted to retire or been declared by a competent medical authority to be unfit for further service the amount standing to his credit in the Fund shall, upon application made by him in that behalf to the Accounts Officer, become payable to the subscriber:

Provided that the subscriber, if he returns to duty, shall if require to do so by the Director General, repay the Fund, for credit to his account, the amount paid to him from the fund in pursuance of this rule with interest thereon at the rate provided in rule 13 in cash or securities by instalments or otherwise, by recovery from his emoluments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub-rule (2) or rule 14.

22. Procedure on death of subscriber.—On the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable, or where the amount has become payable before payment has been made—

(i) When the subscriber leaves a family—

- (a) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of rule 7 or of the corresponding rule heretofore in force in favour of a member or members or his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination;
- (b) if no such nomination in favour of member or members of the family of the subscriber subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family becomes payable to the members of his family in equal shares:

Provided that no share shall be payable to—

- (1) sons who have attained majority;
- (2) sons of a deceased son who have attained majority;
- (3) married daughters whose husbands are alive;
- (4) married daughters of a deceased son whose husbands are alive;
- (c) If there is any member of the family other than those specified in clauses (1), (2), (3) and (4);

Provided further that the widow or widows and the children or of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (1) to the first proviso.

- (ii) when the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of rule 7 or of the corresponding rule heretofore in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

23. Deposit Linked Insurance Scheme.—On the death of a subscriber on or before 30th September, 1991 and to whom rule 24 does not apply, the person entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber shall be paid by the Accounts Officer an additional amount equal to the average balance in the account during the 3 years immediately preceding the death of such subscriber subject to the condition that—

- (a) the balance at the credit of such subscriber shall not at any time during the three years preceding the month of death have fallen below the limits of—
- (i) Rs. 4000 in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 1500 or more in the pre-revised scale;
- (ii) Rs. 2,500 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 900 or more but less than Rs. 1,300 in the pre-revised scale;
- (iii) Rs. 1,500 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 291 or more but less than Rs. 900 in the pre-revised scale;
- (iv) Rs. 1,000 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is less than Rs. 291 in the pre-revised scale.
- (b) the additional amount payable under this rule shall not exceed Rs. 10,000;
- (c) the subscriber has put in at least five years service at the time of his death.

Note 1.—The average balance shall be worked out on the basis of the balance at the credit of the subscriber at the end of each of the 36 months preceding the month in which the death occurs. For this purpose, as also for checking the minimum balances prescribed above:—

- (a) the balance at the end of March shall include the annual interest credited in terms of rule 13;
- (b) if the last of the aforesaid 36 months is not March, the balance at the end of the said last month shall include interest in respect of the period from the beginning of the financial year in which death occurs to the end of the said last month.

Note 2.—Payments under this scheme should be in whole rupee. If an amount due includes a fraction of a rupee it should be rounded to the nearest rupee (50 paise counting as the next higher rupee).

Note 3.—Any sum payable under this scheme is in the nature of insurance money and, therefore, the statutory protection given by section 3 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), does not apply to sums payable under this scheme.

Note 4.—This scheme also applies to those subscribers to the Fund who are transferred to an autonomous organisation consequent upon conversion of a Government Department

into such a body and who, on such transfer, opt, in terms of option given to them, to subscribe to this Fund in accordance with these rules.

Note 5. (a) In case of a Government servant who has been admitted to the benefit of the Fund under rule 26 or 27, but dies before completion of three years service, or as the case may be, five years service from the date of his admission to the fund, that period of his service under the previous employer in respect whereof the amount of his subscriptions and the employer's contribution, if any, together with interest have been received, shall count for purposes of clause (a) and clause (c) of this rule.

(b) In case of persons appointed on tenure basis and in the case of re-employed pensioners, service rendered from the date of such appointment of re-employment, as the case may be, only will count for purpose of this rule.

(c) This scheme does not apply to persons appointed on contract basis.

Note-6. The budget estimates of expenditure in respect of this scheme will be prepared by the Accounts Officer responsible for maintenance of the accounts of the Fund having regard to the trend of expenditure, in the same manner as estimates are prepared for other retirement benefits.

24. Deposit Linked Insurance Revised Scheme.—On the death of a subscriber, the person entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber shall be paid by the Accounts Officer an additional amount equal to the average balance in the account during the 3 years immediately preceding the death of such subscriber, subject to the condition that—

- a) the balance at the credit of such subscriber shall not at any time during the 3 years preceding the month of death have fallen below the limits of—
 - i) Rs. 12000 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post of maximum of the pay scale of which is Rs. 4,000 or more.
 - ii) Rs. 7,500 in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 2,900 or more but less than Rs. 4,000.
 - iii) Rs. 4,500 in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 1,151 or more but less than Rs. 2,900;
 - iv) Rs. 3,000 in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is less than Rs. 1,151;
- b) the additional amount payable under this rule shall not exceed Rs. 30,000.
- c) the subscriber has put in at least 5 years service at the time of his/her death.

Note-1. The average balance shall be worked out on the basis of the balance at the end of each of the 36 months, preceding the month in which the death occurs. For this purpose, as also for checking the maximum balance prescribed above:—

- (a) the balance at the end of March shall include the annual interest credited in terms of rule 13;
- (b) if the last of the aforesaid 36 months is not March, the balance at the end of said last month shall include interest in respect of the period from the beginning of the financial year in which death occurs to the end of the said last month.

Note-2. Payment under this scheme will be in whole rupee. If an amount due includes a fraction of a rupee it should be rounded to the nearest rupee (50 paise counting as the next higher rupee).

Note-3. Any sum payable under this scheme is in the nature of insurance money and therefore, the statutory protection given by section 3 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) does not apply to sums payable under this scheme.

Note-4. The scheme also applies to those subscribers to the funds who are transferred to an autonomous organisation consequent upon conversion of a Government Department into such a body and who, on such transfer, opt in terms of option given to them to subscribe to the Fund in accordance with these rules.

Note-5. (a) In case of a Government servant who has been admitted to the benefits of the fund under rule 26 or 27 but died before completion of three years of service or as the case may be, five years of service from the date of his admission to the Fund, the period of his service under the previous employer in respect whereof the amount of his subscription and the employer's contribution, if any, together with interest have been recovered, shall count for the purpose of clause (a) and clause (c) of this rule.

(b) In case of persons appointed on tenure basis and in the case of re-employed pensioners, service rendered from the date of such appointment on re-employment, as the case may be, only will count for the purposes of this rule.

(c) The scheme does not apply to persons appointed on contract basis.

Note-6. The Budget Estimates of expenditure in respect of this scheme will be prepared by the Accounts Officer responsible for maintenance of the account of the Fund having regard to the trend of expenditure, in the same manner as estimates are prepared for other retirement benefits.

25. Manner of payment of amount in the Fund.—(1) When the amount standing to the credit of a subscriber in the Fund become payable, it shall be the duty of the Accounts Officer to make payment on receipt of a written application in this behalf as provided in sub-rule (3).

(2) If the person whom, under these rules, any amount of policy is to be paid, assigned or reassigned or delivered; is a lunatic for whose estate a manager has been appointed in this behalf under the Lunacy Act, 1912 (4 of 1912) the payment or reassignment or delivery shall be made to such manager and not to the lunatic:

Provided that where no manager has been appointed and the person to whom the sum is payable is certified by a magistrate to be lunatic, the payment shall under the orders of the Collector be made in terms of sub-section (1) or section 93 of the Lunacy Act, 1912 (4 of 1912), to the person having charge of such lunatic and the Accounts Officer shall pay only the amount which he thinks fit to the person having charge of the lunatic and the surplus, if any, or such part thereof, as he thinks fit shall be paid for the maintenance of such member of the lunatic's family as are dependent on him for maintenance.

(3) Payment of the amount to be withdrawn shall be made in India only. The persons to whom the amounts are payable shall make their own arrangements to receive payment in India. The following procedure shall be adopted for claiming payment be a subscriber, namely:—

- (i) to enable a subscriber to submit an application for withdrawal of the amount in the Fund, the Head of office shall send to every subscriber necessary forms either one year in advance of the date on which the subscriber attains the age of superannuation, or before the date of his anticipated retirement, if earlier, with instructions that they should be returned to him duly completed within a period of one month from the date of receipt of the forms by the subscriber. The subscriber shall submit the application to the Accounts Officer through the Head of office or department for payment of the amount in the Fund. The application shall be made:—

- (a) for the amount standing to his credit in the Fund as indicated in the Account Statement for the year

ending one year prior to the date of his superannuation, or his anticipated date of retirement, or

- (b) for the amount indicated in his ledger account in case of the Accounts Statement has not been received by the subscriber.
- (ii) the Head of Office or Department shall forward the application to the Accounts Officer indicating the recoveries effected against the advances which are still current and the number of instalments yet to be recovered and also indicate the withdrawals, if any, taken by subscriber after the period covered by the last statement or the subscriber's accounts sent by the Accounts Officer.
- (iii) The Accounts Officer shall, after verification with the ledger account, issue an authority for the amount indicated in the application at least a month before the date of superannuation but payable on the date of superannuation.
- (iv) The authority mentioned in clause (iii) will constitute the first instalment of payment. A second authority for payment will be issued as soon as possible after superannuation. This will relate to the contribution made by the subscriber subsequent to the amount mentioned in the application submitted under clause (i) plus the refund of instalments against advances which were current at the time of the first application.
- (v) after forwarding the application for final payment to the Accounts Officer, advance/withdrawal may be sanctioned but the amount of advance/withdrawal shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer concerned who shall arrange this as soon as formal sanction of sanctioning authority is received by him.

Note.—When the amount standing to the credit on a subscriber has become payable under rules 20, 21 and 22 the Accounts Officer shall authorise prompt payment of the amount in the manner indicated in sub-rule (3).

26. Procedure on transfer of a Government servant from one Department to another.—(a) If a Government servant who is a subscriber to any other non-contributory Provident Fund of the Central Government or of a State Government is permanently transferred to pensionable service in a Department of the Central Government in which he is governed by these rules, the amount of subscriptions, together with interest thereon, standing to his credit to such other Fund on the date of transfer shall be transferred to his credit in the Fund:

Provided that where a subscriber was subscribing to a non-contributory Provident Fund of a State Government the consent of that Government shall be obtained.

(b) If a Government servant who is a subscriber to the State Railways Provident Fund or any other contributory Provident Fund of the Central Government or a State Contributory Provident Fund is permanently transferred to pensionable service in a Department of Central Government in which he is governed by these rules and unless such a subscriber elects to continue to be governed by the rules of such Fund, when the rules option is given :—

- (i) the amount of subscriptions with interest thereon, standing to his credit in such Contributory Provident Fund on the date of transfer shall with the consent of the other Government, if any, be transferred to his credit in the Fund;
- (ii) the amount of Government contributions, with interest thereon, standing to his credit in such contributory Provident Fund shall, with the consent of the other Government, if any, be credited to the Central Revenue (Civil);
- (iii) he shall thereupon be entitled to count towards pension, service rendered prior to the date of permanent transfer, the extent permissible under the relevant pension rules.

Note-1.—The provisions of this rule does not apply to a subscriber who has retired from service, or to a subscriber who was holding the former appointment on contract.

Note-2.—The provisions of this rule shall, however apply to persons, who are appointed without break whether temporarily or permanently to a post carrying the benefits of these rules after resignation or retirement from service under another Department of Central Government or under the State Government,

27. Procedure on transfer.—On transfer to Government service or a person from the service under a body corporate owned or controlled by Government or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860. If a Government servant admitted to the benefit of the Fund was subscriber to any Provident Fund of a body corporate owned or controlled by Government or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860, the amount of his subscriptions and the employer's contribution, if any, together with the interest thereon shall be transferred to his credit in the Fund with the consent of that body.

28. Transfer of amount to the Contributory Provident Fund (India).—If a subscriber to the Fund is subsequently admitted to the benefits of the Contributory Provident Fund (India) the amount of his subscriptions, together with interest thereon, shall be transferred to the credit of his account in the Contributory Provident Fund (India).

Note.—The provision of this rule do not apply to a subscriber who is appointed on contract or who has retired from service and is subsequently re-employed with or without a break in service in another post carrying contributory Provident Fund benefits.

29. Relaxation of the provisions of the rules in individual cases.—When the Standing Committee is satisfied that the operation of any of these rules causes or is likely to cause undue hardship to a subscriber, it may, notwithstanding anything contained in these rules after recording its reasons for so doing deal with the case of such subscriber in such manner as may appear to it to be just and equitable.

30. Number of account to be quoted at the time of the payment of subscription.—When paying a subscription in India, either by deduction from emoluments or in cash, a subscriber shall quote the number of his account in the Fund which shall be communicated to him by the Accounts Officer. Any change in the number shall similarly be communicated to the subscriber by the Accounts Officer.

31. Annual statement of account to be supplied to subscriber.—(1) As soon as possible after the close of each year, the Accounts Officer shall send to each subscriber's statement of his account in the Fund showing the opening balance as on the 1st April of the year, the total amount credited or debited during the year, the total amount of interest credited as on the 31st March of the year and closing balance on that date. The Accounts Officer shall attach to the statement of accounts an enquiry whether the subscriber—

(a) desires to make any alteration in any nomination made under rule 7; or under the corresponding rule heretofore in force.

(b) has acquired a family, in cases where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his family under the proviso to sub-rule (1) or rule 7.

(2) Subscribers should satisfy themselves as to the correctness to the annual statement, and errors should be brought to the notice of the Accounts Officer within three months from the date of receipt of the Statement.

(3) The Accounts Officer shall, if required by a subscriber, once but not more than once, in a year inform the subscriber of the total amount standing to his credit in the Fund at the end of the last month for which his account has been written up.

32. Interpretation.—If any question arises relating to interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government in the Ministry of Labour shall decide the same.

Schedule—I

[See rule 7(3)]

FORM OF NOMINATION

Account No.

I hereby nominate the persons(s) mentioned below who is/are member(s) of my family as defined in rule 2 to receive the amount that may stand to my credit in the Fund as indicated below, in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid.

FORM OF NOMINATION

Name and full address of the nominee(s)	Relationship with the subscriber	Age of the nominee(s)	Share payable to each nominee
1	2	3	4
Contingencies on the happening of which the nomination will become invalid.	Name, address & relationship of the person(s) if any to whom the right of nominee shall pass in the event of his/her Predeceasing the subscriber	If the nominee is not a member of the family as defined indicate the reasons.	
5	6	7	

Dated this day of 19... at

Signature of subscriber.....

Name in block letters.....

Signature

1. _____

2. _____

Two witnesses to signature

Name & address

1.
2.**(REVERSE OF THE FORM)****SPACE FOR USE BY THE HEAD OF OFFICE/PAY & ACCOUNTS OFFICE**

Nomination by Shri/Smt./Kumari Designation
 Date of receipt of nomination

Signature of Head of Office/Accounts officer

Designation

Date

INSTRUCTIONS FOR THE SUBSCRIBER.—

(a) Your name may be filed in:

(b) Name of the Fund may be completed suitably.

(c) Definition of term "family" as given in the General Provident Funds (CS) Rules, 1960 is reproduced below:
Family means:—

(i) in the case of a male subscriber, the wife or wives, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a paternal grandparents:

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Accounts officer that she shall continue to be so regarded.

(ii) In the case of a female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive a paternal grandparent:

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Accounts officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently cancelled such notice in writing.

Note.— Child means legitimate child and includes an adopted child where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber.

(d) Col. 4 If only one person is nominated the words "in full" should be written against the nominee. If more than one person is nominated, the share payable to each nominee over the whole amount of the Provident Fund shall be specified.

(e) Col. 5 Death of nominee(s) should not be mentioned as contingency in this column.

(f) Col. 6 Do not mention your name.

(g) Draw line across the blank space below last entry to prevent insertion of any name after you have signed.

SCHEDULE—II

[See rules 14(3) and 17(1)]

APPLICATION FOR ADVANCE/WITHDRAWAL FROM GENERAL PROVIDENT FUND

1. Name of the subscriber _____

2. Account Number _____

3. Designation _____

4. (1) Pay Rs. _____

(2) Monthly subscription Rs. _____

5. In case of withdrawal

(i) Date of Birth _____

(ii) Date of appointment _____

(iii) Date of superannuation _____

Balance at credit of the subscriber on the date of application as below:—

(i) Closing balance as per statement for the year 19_____ Rs. _____

(ii) Credit from _____ to _____ on account of monthly subscription Rs. _____

(iii) Refunds Rs. _____

(iv) Withdrawals during the period from _____ to _____ Rs. _____

(v) Net balance at credit Rs. _____

6. Amount of advance outstanding, if any, and the purpose for which advance was taken by them.
 Amount of advance taken Rs. _____
 Balance outstanding as on date Rs. _____
7. Amount of advance required Rs. _____
8. (a) Purpose for which the advance is required _____
 (b) Rules under which the request is covered _____
 (c) If advance is sought for House Building etc. following information may be given :—
 (1) Location and measurement of the plot _____
 (2) Whether plot is freehold or on lease _____
 (3) Plan for construction _____
 (4) If the flat or plot being purchased is from a H.B. Society, the name of the Society, the location and measurements, etc. _____
 (5) Cost of construction _____
 (6) If the purchase of flat is from DDA or any Housing Board etc. the location, dimension, etc. may be given _____
- (d) If advance is required for education of children, following details may be given :—
 (1) Name of the son/daughter _____
 (2) Class and Institution/College where studying _____
 (3) Whether a day-scholar or a hostler _____
- (e) If advance is required for treatment of ailing family members, following details may be given :—
 (1) Name of the patient and relationship _____
 (2) Name of the Hospital/Dispensary/Doctor where the patient is undergoing treatment _____
 (3) Whether outdoor/indoor patient _____
 (4) Whether reimbursement available or not _____

Note:—In case of advance under 8(c) to 8(e), no certificate or documentary evidence would be required.

9. Amount of the consolidated advance (items 6 and 7) and number of monthly instalments in which the consolidated advance is proposed to be repaid Rs. _____ in instalments.

10. Full particulars of the pecuniary circumstances of the subscriber, justifying the application for the advance.

I certify that particulars given above are correct and complete to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed by me.

Signature of Applicant

Name _____

Designation _____

Section/Branch _____

Dated:—

Recommendation/Remarks of
the Competent Authority

Dated:—

Signature _____

Designation _____

[File No. S-65012/1/90-SS. I]

J.P. SHUKLA Under Secy.